हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 18 मार्च, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

18.03.2025/1100/ए.जी.-एन.जी./1

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न के तहत एक महत्वपूर्ण विषय को इस माननीय सदन में उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष : नहीं, नहीं, अभी नहीं। आप बाद में अपनी बात रख लेना।...(व्यवधान) after Question Hour. ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगा।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस पर मुख्य मंत्री जी द्वारा स्टेटमैंट आनी चाहिए थी क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।...(व्यवधान)

Speaker: This is very important. You see that this is Question Hour. ...(Interruption) एक घण्टे में कुछ नहीं हो जाएगा। ...(व्यवधान) Postponed Questions for the day. ...(Interruption) I will allow you after the Question Hour. ...(Interruption) Please, please. ...(Interruption) Please, Shri Jai Ram Thakurji, आप 12.00 बजे अपनी बात रख लेना। I will allow you. Postponed Questions for the day.

श्री जय राम ठाकुर : ठीक है, अध्यक्ष महोदय।

18.03.2025/1100/ए.जी.-एन.जी./2

प्रश्न संख्या - 2205 (स्थगित)

श्री केवल सिंह पठानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला कांगड़ा को पर्यटन की राजधानी डिक्लेयर किया है। मैंने प्रश्न किया था कि पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेलवे लाइन, जोकि अंग्रेजों के समय की लाइन है, पर अभी तक क्या कार्य हुआ है? यह रेलवे लाइन आजादी से पहले की है। क्या यह रेलवे लाइन आजादी के बाद एक इंच भी आगे बढ़ी है? मैंने स्थानीय सांसद महोदय की एक स्टेटमैंट पढ़ी थी कि इस रेलवे लाइन का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार के बजट में क्या इसके लिए कोई बजट प्रावधान किया गया है? इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से मुझे पिछली बार आश्वासन दिया गया था और जिसमें डल झील, करेरी, गुणा माता आदि में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के बारे में कहा गया था। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन के संदर्भ में मैंने इसी सत्र में एक प्रश्न किया था जोकि चामुण्डा, ब्रिजेश्वरी, बैजनाथ, ज्वालाजी, मां बगलामुखी आदि के संदर्भ था। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस प्रश्न पर भी आश्वासन चाहता हूं। इसके अलावा मैं जानना चाहता हूं कि क्या पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेलवे लाइन के विस्तारीकरण पर कोई कार्य किया जा रहा है? इसके अतिरिक्त क्या वर्तमान सरकार आने वाले समय में इस रेलवे लाइन के मामले को केन्द्र सरकार के समक्ष उठाएगी? मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्र में यू0पी0ए0-1 के समय में इस रेलवे लाइन पर पांच रेल सेवाएं चलती थीं और आज उनमें से चार रेल सेवाएं बंद हैं।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केन्द्र से धनराशि मिलने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माननीय सांसद ने इसकी घोषणा की है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि इस रेलवे लाइन के विस्तारीकरण के लिए केन्द्र सरकार ने कोई पैसा दिया है।

18.03.2025/1100/ए.जी.-एन.जी./3

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री को जाना था और इन्होंने यह प्रश्न मेरे पास लगा दिया है। मेरा इनसे आग्रह है कि इस प्रश्न को अगले सत्र में माननीय मुख्य मंत्री जी के पास लगा दीजिएगा क्योंकि 'जिसका काम, उसी को साजे'। यह प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी के पास ही लगाया जाना चाहिए। मैं रेलवे के पार्ट की बात कर सकता हूं कि क्योंकि यह विभाग मेरे पास है। मैं बताना चाहता हूं कि पठानकोट-जोगिन्द्रनगर रेलवे लाइन का हमारे पास कोई पैसा नहीं है और न ही कोई सूचना है। हमारा मानना है कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में रेलवे लाइन्ज़ का काम केन्द्र सरकार को करना चाहिए।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

18.03.2025/1105/AG/PB/-1

प्रश्न संख्याः 2205 क्रमागत...

उप मुख्य मंत्री जारी...

चाहे बिलासपुर, बद्दी या कोई भी रेलवे लाइन बननी है। हमारे से अरबों रुपये ले लिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार इन रेल लाइन्स के लिए अरबों रुपये जमा करवा चुकी है। जबकि पूरे देश में रेल का नेटवर्क बना है, हमारा तो छोटा राज्य है। हमारे सांसदों की संख्या भी उतनी नहीं है, अगर हमारे सांसदों की संख्या है भी तो वे पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। रेलवे को लेकर माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि इसे अंग्रेजों ने बना दिया है तो बन गई और यह शिमला तक भी पहुंच गई और आपके जोगिंदर नगर भी पहुंच गई, जहां-जहां ये रेलवे पहुंचनी थी वहां-वहां यह पहुंचाई गई है। लेकिन इस समय इस पर न कोई पैसा है और न ही कोई सोच है। इतना जरूर है कि केंद्र के साथ जो आपकी भावनाएं हैं, उसके मुताबिक पत्र व्यवहार करेंगे और जाकर केंद्रीय मंत्री जी से भी बात करेंगे लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा4 कोई प्रपोजल नहीं है। बाकी जहां तक पर्यटन का सवाल है, मेरे पास पर्यटन मंत्रालय ने सूचना उपलब्ध करवाई है और उसमें आपके करेरी, खबरू वॉटरफॉल,

खजियार, डल झील, बीड़ बिलिंग, स्वदेश दर्शन की ज्वालाजी हैलीपैड और अन्य हैलीपोर्टस की बात लिखी है है। यह सूचना मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। आप इसको स्टडी कर लीजिए और इसमें जो कमी-पेशी होगी वह मुख्यमंत्री जी से चेंबर में जाकर बात कर लीजिए।

श्री सुधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो पठानकोट रेलवे लाइन है, क्या यह हेरिटेज घोषित हो चुकी है और क्या यह सत्य है कि इस बार का जो केंद्रीय बजट आया है, उसमें इसके लगभग चार स्टेशन अपग्रेड होने हैं? अगर इनकी सूचना हो तो उसे भी उपलब्ध कराने की कृपा करें।

18.03.2025/1105/AG/PB/-2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य केवल सिंह पठानिया जी ने कुछ अपने विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स की बात कही है। निश्चित तौर पर जो इनका विधानसभा क्षेत्र का करेरी वाला इलाका है यह बहुत अच्छा है, काफी स्नो बाउंड एरिया है। हमारी सरकार उसका विकास करने के लिए योजना बना रही है और आने वाले समय में उस योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। माननीय सदस्य श्री सुधीर शर्मा जी ने जो कहा है कि रेलवे बजट में चार स्टेशन अपग्रेड करने की बात की है और बजट में प्रोविजन किया है, जब केंद्रीय बजट था तो उसमें हमने भी सुना था लेकिन अभी उसके बारे में कोई सूचना हमें नहीं आई है। जैसे ही उनकी चिट्ठी आएगी आपको सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

18.03.2025/1105/AG/PB/-3

प्रश्न संख्याः 2520

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि पच्छाद विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़ और सराहां अस्पताल है वहां डॉक्टर के कितने पद रिक्त हैं? उप-स्वास्थ्य केंद्र डिंगर किन्नर और उप-स्वास्थ्य केंद्र बसां और ग्राम पंचायत टिक्करी कुठार में भी उप-

स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर कितने पद स्वीकृत व कितने भरे हैं? माननीय मंत्री जी आप यह बताने की कृपा करें।

Speaker: There is an information with you by when these vacancies will be filled up. That is the supplementary. माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

18.03.2025/1110/AS/AP-1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्या ने राजगढ़, सराहां, डिंगर किन्नर तथा ग्राम पंचायत टिकरी कुठार उप स्वास्थ्य केंद्र के संबंध में जो बातें पूछीं हैं, इनकी विभिन्न श्रेणियों का विस्तृत विवरण तो माननीय सदस्या को दे दिया गया है। मैं जानता हूं कि यहां पर स्वीकृत पद 131 हैं और इन 131 पदों में से 62 पद रिक्त चल रहे हैं। It is a serious shortage and no doubt about it. माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी के मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद से, मैं समझता हूं की शीघ्र स्वास्थ्य केंद्रों में अच्छे उपकरण आएंगे और जिन स्वास्थ्य केंद्र में किसी भी प्रकार की कमियां हैं, उसमें चाहे स्टाफ की कमी हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधि उपकरणों की हो, माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट अभिभाषण भी माननीय सदस्यों ने सुना है इसमें कितने विवरणात्मक व विस्तृत रूप से माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बात का वर्णन किया कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छी सुविधाएं दे रहें हैं जिससे की स्वास्थ्य क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट आए, स्टाफ की कंडिशन स्वास्थ्य संस्थानों में हैं दुरूस्त कर दी जाए। जो समस्या इनको ज्यादा लग रही है और उन दोनों ही जगह में जो सृजित पद हैं उसके अनुसार इनको स्टाफ नहीं मिला है। तो मैं अभी यही कह सकता हूं कि जितने भी स्वास्थ्य संस्थान हैं अगर उनके बारे में यह जानना चाहती हैं तो if she wants to know, with your permission, Hon'ble Speaker, Sir, I will read it out for her.

Speaker : Hon'ble Health Minister, the information is also available on the Table of the House and same is supplied to the Hon'ble Member. But she wants to ask another supplementary.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : मैं माननीय सदस्या को यह कहना चाहता हूं कि जो आपके निर्वाचन क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पद हैं वह शीघ्र भर दिए जाएंगे। सराहां और राजगढ़ है और बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, we do require proper attention.

18.03.2025/1110/AS/AP-2

श्रीमती रीना कश्यप : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से यह कहना चाहती हूं कि इन्होंने राजगढ़ व सराहां हास्पिटल्ज के बारे में आश्वासन दिया है कि इन हास्पिटल्ज में डाक्टर्ज के रिक्त पदों को जल्दि से जल्दि भरेंगे। मगर मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा और वह यह है कि जो हमारा उप-स्वास्थ्य केंद्र डिंगर-किन्नर और नया गांव हैं, इन दो उप-स्वास्थ्य केंद्रों में दो पद स्वीकृत हुए हैं लेकिन अभी तक वह दोनों पर रिक्त हैं, इसका मतलब यह है कि जो उप-स्वास्थ्य केंद्र डिंगर-किन्नर व नया गांव हैं, वहां पर ताले लटके हुए हैं, जिसके कारण वहां के स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाऐं नहीं मिल पा रही उन्हें इसके लिए या तो सराहां जाना पड़ता है या फिर चण्डीगढ़ जाना पड़ता है। इसी प्रकार जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र बसां हैं, मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि यह हमारे हिमाचल प्रदेश के निर्माता स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार जी का गांव है लेकिन वहां पर जो उप-स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी दो पद रिक्त पड़ें हैं और इस स्वास्थ्य केंद्र में भी बड़े लंबे समय से ताला लटका हुआ है। इसलिए मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम-से-कम आप उप-स्वास्थ्य केंद्र बसां, जो स्वर्गीय डॉ. यशवंत सिंह परमार जी का अपना गांव है, आप वहां पर तुरंत स्टाफ उपलब्ध करवायें ताकि वहां के लोगों को यह न लगे कि हमारे गांव से हिमाचल प्रदेश के निर्माता संबंध रखते थे और हमें अपने गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही। मेरा आपसे यह निवेदन कि आप इस संदर्भ में इस सदन में आश्वासन दें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस क्षेत्र से स्वयं भी अच्छी तरह परिचित हूं। मैंने लगभग 10 साल तक इस क्षेत्र को देखा है। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा इस तरफ ध्यान रहेगा कि आपने जिन-जिन जगहों का जिक्र किया है उन जगहों मैं खास कर spread out area हैं, वहां पर स्टाफ को शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा।। think another two months or so, you should have comfortable situation there.

18.03.2025/1110/AS/AP-3

प्रश्न संख्या : 2521

Speaker : Shri Nand Lalji is not well but authorized Shri Mohan Lal Brakta.

श्री मोहन लाल ब्राक्टा (प्राधिकृत) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा वैसे तो इन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन इन्होंने as per availability of funds की बात की है। जहां तक दत्तनगर के सी.ए. स्टोर की बात है कि मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहूंगा कि इसका कार्य जल्दी-से-जल्दी शुरू किया जाए।

श्री ऐ0टी0 द्वारा जारी---

18.03.2025/1115/AT/AS /1

प्रश्न संख्या 2521 जारी....

श्री मोहन लाल ब्रकटा: अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहुंगा की कार्य जल्दी से जल्दी हो धन्यवाद ।

राजस्व मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय , जहां तक दत्त नगर के सी0ए0 स्टोर की बात है हमने विस्तृत जानकारी दी है। उसके बाबजूद मैं इनको ये एश्योर करता हूं कि इस बार

इसका हम टेंडर पलोड कर देंगे । जहां तक रोहड़ू का सवाल है, वह अलग से मामला है, उसका जवाब मैं उस समय दूंगा।

18.03.2025/1115/AT/AS /2

प्रश्न संख्या 2522

श्री पवन कुमार काजल : माननीय अध्यक्ष जी, मैंने दो कॉलेजों के बारे में पूछा था की कितने रिक्त पद हैं? मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि वर्ष 2016-17 में जो कांगड़ा विधानसभा में दो कॉलेज खुले थे और उन दिनों जितने भी लगभग 20-22 कॉलेज खुले थे। और इस में एस्टेब्लिश्ड कॉलेज ताकीपुर और मटौर थे। हिमाचल प्रदेश में 132 कॉलेज हैं और ओवरऑल रैंकिंग ताकीपुर कॉलेज की 51 नंबर पर और लाइब्रेरी रैंकिंग पूरे हिमाचल में 9 नंबर पर है। जिला कांगड़ा में लाइब्रेरी रैंकिंग तीसरे नंबर पर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर दिनांकः 3.12.2022 से दो सालों से वेकेंट है। म्यूजिक असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दो सालों से रिक्त है ,कॉमर्स का डेढ़ साल से रिक्त है। अब कॉमर्स की अगले महीने एक और रिटायरमेंट है इसके बाद हिंदी के प्रोफेसर की रिटायरमेंट है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी ये इस्टैबलिश्ड कॉलेज हैं, ये 51वीं रैंकिंग पर हैं। लाइब्रेरी में 9 नंबर परइ और जिला कांगड़ा में तीसरे नंबर पर है। तो क्या इकोनॉमिक्स,म्यूजिक,कॉमर्स के प्रोफेसर्ज़ के पद आने वाले समय में भरेंगे ? जब ये खुले थे तो इनमें एडमिशन थी वह 500-550 के लगभग थी । आज की डेट में यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर न होने के कारण इनकी संख्या 168 रह गई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा । दूसरा सर, एक और सप्लीमेंट्री कर ही लेता हूं। जैसे की इन दोनों कॉलेजों से पहले कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था । एक जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है इसको भी एम0 यू0 एस0 एच0 ए0 से जाना जाता है। एम0 यू0 एस0 एच0 ए0 के नाम से जिला कांगड़ा को 10 करोड़ रुपये की स्वीकृति आपने

दी है। तो यह जो प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान है, तीसरे नंबर पर हमारी रैंकिंग है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसका जब भी आप बंटवारा करोगे यह प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान केवल पिछले वर्गों के लिए जहां लड़कियां ज्यादा संख्या में पढ़ती हैं, ओ0बी0सी0 के ज्यादा लोग पढ़ते हैं, एस0सी0 के ज्यादा पढ़ते बच्चे हैं,उस हिसाब से इसका बंटवारा करें । जो ये खाली पद हैं, इनको कब तक आप भरोगे? दूसरा, जब बंटवारा करोगे तो एस0सी0, ओ0बी0सी0, एस0टी0 और जो दोनों कॉलेजों में लड़कियां हैं, एक में 350 के लगभग स्ट्रैंथ है और 90% लड़कियों की संख्या है। दूसरे कॉलेज में 168 है उसमें भी 90% लड़कियां हैं तो इसका ध्यान रखें ।

18.03.2025/1115/AT/AS /3

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय,माननीय सदस्य ने अपने विधनसभा क्षेत्र के दो कॉलेजों के बारे में जानकारी दी थी और जहां कुछ पद रिक्त थे उसके बारे में तुरंत विस्तार से अपनी बात रखी । लेकिन जो मटौर कॉलेज था यहां पर आपके 17 स्वीकृत पद हैं। इसमें 18 पद हैं और 17 आपके भरे हैं मात्र एक पद आपका रिक्त पड़ा है ।जो हमारा तकीपुर महाविद्यालय है इसके बारे में आपने बताया कि यहां पर हमारे टीचिंग स्टाफ के तीन पद रिक्त हैं और कुछ आपके नॉन टीचिंग स्टाफ के भी पद पड़े हैं । लेकिन जो एनरोलमेंट की कमी की आप बात कर रहे हैं यह मात्र तकीपुर तक ही सीमित नहीं है। या तो आप कह सकते हैं कि चलो यहां पर कुछ स्टाफ की कमी है। हालांकि हमने अपने कार्यकाल के दौरान दोनों कॉलेजों में तकीपुर और मटोर में दो-दो आपके ए0पीज़ लगाए हैं ।

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी ......

18.03.2025/1120/MD/DC/1

प्रश्न संख्या 2522 क्रमागतः

शिक्षा मंत्री----जारीः

मटौर में दो-दो एoपीजo और प्रिंसीपहल लगाए हैं और आने वाले समय में युक्तिकरण के माध्यम से इन पदों को भरने का भी प्रयास किया जाएगा। लेकिन साथ-ही-साथ जहां एनरोलमेंट की बात आती है, यह एक चिंता का विषय है कि जैसे मटौर कॉलेज की बात हो जहां लगभग एक तरह से सौ प्रतिशत स्टाफ उपलब्ध है। यहां पर भी पहले लगभग 670 बच्चे उपलब्ध थे और उसके बाद 420 रहे। मैं अपने ही कार्याकाल का 3 वर्ष का विवरण दे रहा हूं। अब मात्र 313 रह चुके हैं। 50 प्रतिशत के आस-पास गिरावट आ चुकी है। मैं समझता हूं कि हमें कहीं-न-कहीं कंसोलिडेशन की तरफ भी प्रयास करना पड़ेगा। इसी तरह से टकीपुर में भी लगभग 582, आपने बताया कि ये दोनों कॉलेजिज कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल के दौरान राजा वीरभद्र सिंह जी के समय में स्वीकृत हुए थे। इन दोनों की बिल्डिंग्ज का निर्माण कार्य भी लगभग चरम पर पहुंच चुका है। अगर आप मटौर कॉलेज की बात करेंगे तो इसी वित्तीय वर्ष में आपको 4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी मिली है। इसके लिए हमने लगभग 9 करोड़ रुपये के करीब पैसा दे दिया है। इसी तरह लगभग 7 करोड़ रुपये की राशि टकीपुर कॉलेज के लिए दे दी गई है **और जो शेष राशि है, उसको भी दे दिया जाएगा।** इसके साथ ही आपने एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम की बात की है जिसमें लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि मिली है। **अगर आपके कॉलेजिज केंद्र की योजना के मापदण्डों के अंतर्गत आते होंगे तो निश्चित रूप से वह राशि उपलब्ध करवाई जाएगी।**

श्री पवन कुमार काजलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा दी गई जानकारी से सहमत हूं और ये जो मटौर कॉलेज की बात कर रहें है उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। उसमें थोड़ा रास्ते की प्रोब्लम है। वहां रास्ते के लिए जो थोड़ी-सी फंडिंग बचती है, अगर आप उसे अनाउंस कर देते तो जो 313 की वहां पर स्ट्रैंथ है वह लगभग 600 पहुंच जाएगी। वहां अब बिल्डिंग बन गई है, रास्ते की वजह से थोडी-सी

18.03.2025/1120/MD/DC/2

प्रोब्लम है। अगर आप उसके लिए भी फंडिंग कर देते तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वहां पर स्ट्रैंथ ज्यादा होगी।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य श्री पवन काजल जी फंडिंग के मामले में काफी पोजिटिव रहे हैं और आपको अधिकांश राशि दे दी है। अगर रास्ते से संबंधित कोई इस तरह की बात होगी तो **आप हमारे कार्यालय आएं, उसका भी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।**

18.03.2025/1120/MD/DC/3

प्रश्न संख्या-2523

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में जो अवैध रुप से बाहर से नर्सरी आ रही है, यह प्रश्न उसको लेकर था। मैंने पूरा जबाब पढ़ा और Speaker, Sir, I am not satisfied with this answer. हमारे बागवानी मंत्री बहुत सरल और स्पष्ट व्यक्ति हैं। मैं पेशे से वकील हूं और जो इसमें लिखा है मैं उसका अर्थ समझ सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो विदेशों से यहां नर्सरी आ रही है वह पंजाब में क्वारंटाइन होती है। इसकी जो समय अवधि है क्या वह पूरी होती है या आधी होती है? यहां पर अवैध रूप से नर्सरी आ रही है। यह भी कहा जा रहा है कि पकड़ी जा रही है, कितनी पकड़ी गई यहां उसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई। बाहर से नॉन और अननॉन वायरस आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, चिंता का विषय यह है कि बाहर से जो वायरस आ रहा है उससे हमारी पूरी आर्थिकी बर्बाद हो जाएगी । मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि वर्ष 2023 में कश्मीर में स्कैप फैला और 40 प्रतिशत से ज्यादा फसल नष्ट हो गई। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मैकेनिज्म है, यह खाली मैनिपुलेशन है। मेरा यह अनुरोध रहेगा और मेरा यह प्रश्न भी है कि आप इस संदर्भ में क्या प्रभावी कदम उठा रहे हैं?

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

18.03.2025/1125/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्या 2523जारी...

श्री कुलदीप सिंह राठौर जारी ---

दूसरा मेरा प्रश्न था कि बाहर से जो रूट स्टॉक आ रहा है, मेरा मानना है कि जो हमारा बागवानी विश्वविद्यालय है, उसकी स्थापना इसलिए हुई थी कि हम यहां पर उन्नत किस्म की नर्सरी तैयार करें। मुझे वहां के वैज्ञानिकों की काबिलीयत पर कोई संदेह नहीं है लेकिन बाहर से जो नर्सरियां आ रही हैं, जिन देशों से आ रही हैं, वहां उनकी जलवायु, भौगोलिक स्थिति, स्वॉयल कंडिशन यहां से बिल्कुल डिफरेंट है। वहां से हम नर्सरी ला रहे हैं और जो हमारा बागवानी विश्वविद्यालय है, वह सपलायर का काम कर रहा है। हम आज तक अपनी इंडीजीनस नर्सरी, जो यहां के वातावरण, जलवायु और यहां की स्वॉयल कंडिशन के मुताबिक हो, वह हम यहां पर क्यों पैदा नहीं कर पा रहे हैं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विदेशों से जो पौधे आयात किए जा रहे हैं और बिना क्वारंटीन के प्रदेश में लाए जा रहे हैं, उस विषय में वर्ष 2023-24 में हमने एक मुहिम चलाई थी कि जो भी बिना क्वारंटीन के प्रदेश में किसी भी फल के पौधे आ रहे हैं उनको पकड़ कर डिस्ट्रॉय करने का काम शुरू किया जाए। शायद पहली बार इतने लार्ज स्केल पर यानी 25 वाहन, बड़े-बड़े कंटेनर्ज़ वर्ष 2023-24 में हमने जब्त किए और विदेशों से, जम्मू-कश्मीर या अन्य प्रदेशों से जो 02,95,725 पौधे आए थे उनको नष्ट किया गया। उसके बाद जब इतनी सख्ती हो गई तो वर्ष 2024-25 में केवल 4 ही बड़े कंनेटर्ज़ और वाहन पकड़े गए और विभिन्न फलों के जो 68 हजार पौधे गैर कानूनी तरीके से लाए गए, उनको भी नष्ट किया गया। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिना क्वारंटीन के किसी भी किस्म का प्लांट मटीरियल प्रदेश में न आए। परंतु इसमें जो क्वारंटीन की जिम्मेवारी है, सर्टिफिकेशन है, वह हमारे विश्वविद्यालय को है। **इसमें हम और ज्यादा सख्ती करेंगे और ज्यादा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में बिना सर्टिफिकेशन के और बिना क्वारंटीन के प्लांट मटीरियल न आए ताकि भविष्य में यहां पर किसी भी किस्म का रोग न फैल पाए।**

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो दूसरी समस्या का ज़िक्र किया, यह ठीक है कि हमारे बागवानी विश्वविद्यालय नौणी ने लम्बे समय से हिमाचल प्रदेश में

18.03.2025/1125/केएस/डीसी/2

बागवानी के क्षेत्र में, फोरैस्ट्री के क्षेत्र में अच्छा काम भी किया है परंतु इतने लम्बे समय के बाद भी हम कोई रिसर्च या कोई नया इंडीजीनैस कोई वैरायटीज़, वे चाहे रूट स्टॉक में हो, आपके कल्टीवर्ज़ में हो, उसको हम नहीं कर पाए तो यह चिंता का विषय है और हमने उनसे समय-समय पर मीटिंग्ज़ भी की हैं। हम युनिवर्सिटी के साथ अभी एक रिव्यू मीटिंग भी करेंगे कि क्या कारण है कि हमारे साइंटिस्ट जो इतने ज्यादा अच्छे हैं परंतु अभी तक ये यहां पर कोई नई रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं? रिव्यू मीटिंग करके हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो विश्वविद्यालय हैं, इसमें भी ओरिजिनल रिसर्च का काम किया जाए।

श्री कुलदीप सिंह राठौर : अध्यक्ष महोदय, जो नॉर्मल रूट स्टॉक आयात हो रहा है,उसकी कीमत 100 रुपये है और हमारे फैदर प्लांट्स की कीमत 700 से 800 रुपये है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत महंगे हैं और 80 प्रतिशत से ज्यादा हमारे मझोले और छोटे बागवान हैं। वे उनको अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगे होते हैं। मेरा यह आग्रह रहेगा कि जो हमारा नौणी विश्वविद्यालय है, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये इस बात की जांच करेंगे कि इस तरह की वैरायटीज़ यहां पर रिसर्च क्यों नहीं हो रही है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नर्सरीज़ हैं ये उनके साथ कोलैबोरेशन करे लेकिन जो भी हो वह यहां की स्वॉयल पर हो तब वह यहां पर प्रभावी ढंग से काम करेगी लेकिन अगर...

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.03.2025/1130/av/hk/1

प्रश्न संख्या : 2523--------- क्रमागत

श्री कुलदीप सिंह राठौर------- जारी

अगर बागवानी विश्वविद्यालय को केवल मिडिल मैन का काम करना है तो इस नर्सरी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मेरा यही आग्रह रहेगा कि हमें रिसर्च पर जोर देना चाहिए। मैं यूरोप और अमेरिका की बात करना चाहूंगा कि वहां पर 50 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है जबकि हमारे यहां 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन हो रहा है यानी वहां हमारे से दस गुणा ज्यादा उत्पादन होता है। वैसे भी यहां पर सेब बड़े संकट से गुजर रहा है क्योंकि अभी आयात शुल्क भी कम होने वाला है। हमारा सेब का इतना बड़ा उद्योग है और हमारी लगभग 5000 करोड़ रुपये की आर्थिकी सेब से आती है जिस पर अब बहुत ज्यादा संकट है। इसलिए मेरा यही निवेदन रहेगा कि सरकार को इस संदर्भ में काफी प्रभावी ढंग से कदम उठाने होंगे ताकि हम इस आर्थिकी को बचा सकें।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रूट स्टॉक्स की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि एक प्रोजैक्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित एच0डी0पी0 के तहत वर्ष 2016 में शुरू हुआ था जिसको बाद में एक्सटैंड भी किया गया था और वह पिछले माह अक्तूबर, 2024 में समाप्त हो चुका है। इस प्रोजैक्ट के तहत लगभग 130 करोड़ रुपये का प्लांट मटीरियल लाया गया। परंतु यह सफल नहीं हुआ क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन में एक बीघे में कम-से-कम तीन सौ पौधे चाहिए परंतु उस हिसाब से यह डिमाण्ड पूरी नहीं हो पाई। जिसके लिए यहां होर्टिकल्चर डिपार्टमैंट के अंतर्गत एक नर्सरी मैनेजमैंट सोसाइटी बनाई गई। यहां पर हमारे 91 पी0सी0डी0ओज0 हैं। विदेशों से जो रूट स्टॉक्स आयात किया गया था उनको यहां पर लगाकर प्लांट मटीरियल तैयार करने की कोशिश की गई। परंतु यह कदम भी पर्याप्त नहीं हो पाया क्योंकि जिस स्टेज पर यह तैयार करना चाहिए था हम उतनी क्वांटिटी भी तैयार नहीं कर पाए और न ही वह क्वालिटी तैयार कर पाए। हमारे यहां पर इस बारे में बहुत सारी कमियां रही हैं जिनको मैं मानता हूं। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इस बार इटली की एक अंतर्राष्ट्रीय 'ग्रीवा' कम्पनी के साथ करार किया है। वहां से 50,000 स्लीपिंग आईज मटीरियल लाकर अब उनकी 2-3 दिन में बजौरा में प्लांटेशन शुरू

18.03.2025/1130/av/hk/2

कर दी जाएगी। उसको हम फैदर्ड करके माह दिसम्बर से पहले-पहले 7 फैदर्ड में लगाएंगे। उसका मार्किट में 700 रुपये प्रति पौधा रेट है जिसको हम 400-450 रुपये प्रति पौधा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक रूटस्टॉक्स की बात है तो हमारी अपनी नर्सरी मैनेजमैंट सोसाइटी है जोकि हमारे पी0सी0डी0ओज0 में हैं और इसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है। पिछली बार हमारे पास 900 रूटस्टॉक्स थे लेकिन अब हम रूटस्टॉक्स प्रपोगेशन यहां पर भी कर रहे हैं। अगर हम रूटस्टॉक से प्रपोगेट करते हैं तो वह 5-6 निकलने चाहिए परंतु हम यहां पर 2 या 3 से आगे नहीं निकाल पा रहे। फिर भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रूटस्टॉक्स हैं। हमने इस बार 75 रुपये प्रति रूटस्टॉक के हिसाब से 46,000 रूटस्टॉक्स बेचे हैं जबकि विश्वविद्यालय ने 100 रुपये प्रति रूटस्टॉक के हिसाब से 20,000 रूटस्टॉक्स बेचे हैं। हमने बाहर की वैरायटी के ऊपर यानी एम-9 के अंतर्गत यहां पर बिना फैदर्ड के रूटस्टॉक्स तैयार किए हैं और उसके ऊपर विभिन्न कल्टीवेट लगाए हैं, उसका रेट भी हमने केवल 180 रुपये रखा है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि हम यहां पर जो तैयार कर रहे हैं वह रेटवाइज बहुत कम है। परंतु हाई डेंसिटी प्लांट के हिसाब से अभी भी हम बहुत पीछे हैं। इस संदर्भ में बहुत काम करने की जरूरत है। हमने एक प्रयास ग्रीवा कम्पनी के अंतर्गत शुरू किया है। अगर हमारा यह पायलट प्रोजैक्ट इस बार ठीक चल पड़ेगा तो आने वाले समय में हम यहां पर लाखों प्लांट तैयार करके फैदर्ड में बागवानों को देंगे। हम **यहां पर बाहर के मुकाबले हाई डेंसिटी प्लांट प्रति हेक्टेयर प्रोडक्शन में बहुत पीछे हैं जिसको हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे।**

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने काफी डिटेल में उत्तर दिया है। मैं मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन की थी जिसके अंतर्गत यह कहा था कि एक वर्ष तक जो भी पौधा इम्पोर्ट होगा उसका क्वारंटाइन एक वर्ष तक करना है।

टी सी द्वारा जारी

18.03.2025/1135/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

प्रश्न संख्याः 2523...... क्रमागत्

श्री बलबीर सिंह वर्मा... जारी

लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो भी प्लांटेशन इंपोर्ट हो रही है, वह क्वारंटाइन नहीं हो रही है। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो पौधे बाहर से आ रहे हैं, उनमें फंगस, बैक्टीरिया और वायरस जैसी कई गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। जिस प्रकार चीन से कोरोना वायरस आया था और यह पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट बन गया था, उसी तरह यदि कोई गंभीर बीमारी हिमाचल प्रदेश में आ गई तो इसका प्रदेश की एप्पल इंडस्ट्री पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एप्पल का योगदान 5000 करोड़ रुपये से अधिक का है और प्रदेश के छह जिले मुख्य रूप से एप्पल उत्पादन में संलग्न हैं। यह युवा वर्ग के लिए रोजगार का प्रमुख साधन है। मेरी मंत्री महोदय से विनती है कि जब हिमाचल प्रदेश इटली को हाई-डेंसिटी पौधों के लिए प्रतिवर्ष 1000 करोड़ रुपये दे रहा है, तो क्या प्रदेश में हाई-डेंसिटी प्लांटेशन पर शोध के लिए अपनी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं की जा सकती? क्या मंत्री जी इस माननीय सदन को यह आश्वासन देंगे कि यह शोध कार्य नौणी यूनिवर्सिटी में ही किया जाएगा, ताकि प्रदेश के किसानों को लाभ मिल सके और यह धनराशि विदेश जाने के बजाय प्रदेश में ही बनी रहे?

इसके अतिरिक्त, जिन 3 लाख पौधों को नष्ट किया गया है, उनके विरुद्ध क्या कोई कानूनी कार्रवाई हुई है? भविष्य में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

18.03.2025/1135/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता यहां पर जाहिर की है उसके संदर्भ में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि क्वारंटाइन एक्ट केवल प्रदेश सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो भी प्लांटेशन हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं, उनका क्वारंटाइन राज्य में नहीं किया जा रहा है बल्कि पड़ोसी राज्यों पंजाब और उत्तराखंड में किया जा रहा है। वहां से सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है कि

पौधे क्वारंटाइन हो चुके हैं और उनको हिमाचल प्रदेश के लिए भेज दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश सरकार के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। हम उनके सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जहां तक 1000 करोड़ रुपये की बात है, तो ये प्लांट्स केवल इटली से ही नहीं, बल्कि हॉलैंड, चीन, सर्बिया और अमेरिका से भी आ रहे हैं। यह केवल युवा किसानों का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा मामला है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में ही उच्च गुणवत्ता वाले पौधे तैयार किए जाएं, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है। शोध कार्य के अभाव में हम इस क्षेत्र में पीछे रह रहे हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज में बड़े-बड़े शोध कार्य होने चाहिए, लेकिन वास्तविक शोध कार्य नहीं हो रहे, केवल कट-पेस्ट करके डिग्रियां हासिल की जा रही हैं। हमें ओरिजिनल रिसर्च पर ध्यान देना होगा, परंतु इसमें 10 वर्ष का समय लग जाएगा है। फिलहाल, बाहर से पौधों का आयात करना ही एकमात्र विकल्प है। हमारे पड़ोसी राज्य जम्मू-कश्मीर में लाखों के हिसाब से प्लांट्स आ रहे हैं। वे एक लाख रुटस्टॉक के प्लांट्स तो हिमाचल प्रदेश से ही ले रहे हैं। केंद्र सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन प्रदेश में संसाधनों की कमी है। हमारे पास सर्टिफिकेशन सेंटर स्थापित करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। सर्टिफिकेशन सेंटर स्थापित करने के लिए 500-600 करोड़ रुपये की आवश्यकता होती है। **फिर भी, सीमित संसाधनों के बीच हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि बाहर से आने वाले पौधे वायरस-फ्री हों।** अब तक 3 लाख पौधे नष्ट किए जा चुके हैं, जो शायद पहले कभी नहीं किए गए। इससे कुछ लोगों को असुविधा हुई और वे हमारे खिलाफ भी हो गए, लेकिन हमने कठोर कदम उठाए हैं ताकि प्रदेश की एप्पल इंडस्ट्री सुरक्षित रह सके। धन्यवाद।

अगला प्रश्न एन0एस0 द्वारा शुरू ...

18-03-2025/1140/NS-YK/1

प्रश्न संख्या : 2524

श्री दलीप ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री से जानना चाहूंगा कि जो छोटी-छोटी लघु सिंचाई योजना जिनकी डी0पी0आर0 विधायक प्राथमिकता में डाली गई है क्या उनकी डी0पी0आर0 तैयार हो गई है? जवाब में बताया गया है कि कुछ की

डी0पी0आर0 तैयार हो गई और कुछ शेष हैं। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कब तक इन डी0पी0आर्ज को तैयार कर दिया जाएगा और कब इन पर काम शुरू होगा? दूसरा, संधोल से जो पेयजल योजना सरकाघाट के लिए बनाई जा रही है उसके बारे में बताया गया है कि उसका 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। आज भी लोगों को 6-7 दिनों के बाद पानी मिल रहा है। गर्मियों में तो स्थिति और भी खराब होगी। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस योजना के कार्य को कब तक पूरा कर दिया जाएगा? तीसरा, सिंचाई योजना जो धर्मपुर और सरकाघाट विधान सभा क्षेत्रों के लिए है। उसमें ग्राम पंचायत बसन्तपुर, पपलोग, रखोह, बकारटा, बरच्छवाड़, दारपा, परसदा हवाणी, झंझैल और रोपड़ी आदि शामिल है। जवाब में कहा गया है कि इसका 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। मेरा उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा ताकि किसानों को इसका फायदा मिल सके?

18-03-2025/1140/NS-YK/2

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर विधायक प्राथमिकता की बात हो रही है और माननीय विधायक प्लानिंग की मीटिंग में तो आते ही नहीं हैं। ...(व्यवधान) आप जय राम जी को फॉलो मत कीजिए क्योंकि इनकी कॉन्स्टीच्यूएंसी में सब कुछ हो गया है। इन्होंने आपको मीटिंग में आने नहीं दिया। ...(व्यवधान) आप इस वर्ष प्लानिंग की मीटिंग में नहीं आए। अगर आप आते तो ये सारे विषय वहीं स्पष्ट हो जाते। ...(व्यवधान) रणधीर जी, ऐसा है कि नाबार्ड के लोन की एक लिमिट है। जो पैसा हमें मिलना है वह मिल गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपने over and above योजनाएं भेजी हैं। हमने किसी भी विधायक की कोई भी योजना नहीं रोकी है। जिसकी भी आई, हमने उसको प्लानिंग से नाबार्ड तक प्रेषित कर दिया है। ...(व्यवधान) वहां पर दो बाते हैं। पहली बात तो यह है कि नाबार्ड की लिमिट कितनी है? जितना उनके पास धन है और उसके बाद वे बता देते हैं कि आपकी योजनाएं नहीं ली जाएंगी। दूसरा, प्रदेश सरकार ने विधायक प्राथमिकता में 175 व 195 करोड़ रुपये की लिमिट लगाई है और अभी इसको 200 करोड़ रुपये किया गया है। वे यह

भी बता देते हैं कि आपकी कॉन्स्टीच्यूएंसकी में 200 करोड़ रुपये का काम हो गया है। इसलिए आपकी योजना नहीं ली जा रही है। उसमें ये दो ही मामले हैं। अध्यक्ष महोदय, मीटिंग में आना या नहीं आना, वे तो विधायकों की अपनी इच्छा है।

अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकाघाट विधान सभा क्षेत्र के तहत वर्ष 2014 से वर्ष 2025 तक विधायक प्राथमिकता के तहत 42 योजनाएं प्रस्तावित की जानी थीं। आप तो नये विधायक हैं और आपको इसके लिए हम कह भी नहीं सकते। लेकिन आपके क्षेत्र की 42 में से 13 प्राथमिकताएं आई ही नहीं हैं। अब आप से पहले वाले विधायक ने क्यों नहीं भेजीं, हम इसके बारे में नहीं कह सकते। आपने तो अपनी विधायक प्राथमिकताएं भेज दी हैं। आपकी 3 योजनाएं इनफीजिबल हैं जो नहीं बन सकती हैं। आपकी 10 योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत हो चुकी हैं और 4 योजनाएं जल जीवन मिशन की हैं। पिछले वर्ष जल जीवन मिशन में 916 करोड़ रुपये का एग्रीमैंट हुआ था कि आप हमें 916 करोड़ रुपये या 925 करोड़ रुपये देंगे।

आर0के0एस0 द्वारा-----जारी

18.03.2025/1145/RKS/yk-1

प्रश्न संख्याः 2524

जल शक्ति मंत्री .... जारी

जल जीवन मिशन में पिछले वर्ष हमारा लगभग 961 या 925 करोड़ रुपये का एग्रीमेंट था जो हमें केंद्र सरकार से प्राप्त होना था। वर्तमान में हमें जल जीवन मिशन के तहत 137 करोड़ रुपये जारी हुए हैं और शेष राशि अभी तक जारी नहीं की गई है। हम इस विषय पर केंद्रीय मंत्रालय से लगातार बात कर रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जो केंद्र ने राज्य से एग्री किया है उस पैसे को हमें उपलब्ध करवाएं। आप एक जल जीवन मिशन और दूसरी पी.एम.के.एस.वाई. की योजना का जिक्र कर रहे हैं। **इन दोनों योजनाओं का लगभग 80-80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। हम इन दोनों योजनाओं का शेष कार्य पूर्ण करने के लिए पैसे का प्रबंध कर लेंगे** लेकिन दिक्कत यह है कि एक योजना में वहां के

लोग आगे पाइप नहीं जाने दे रहे हैं और दूसरी योजना में नेशनल हाइवे वाले पाइप को डालने नहीं दे रहे हैं। अगर आप स्वयं उन लोगों और नेशनल हाइवे वालों से बात करते हैं तो फिर जल शक्ति विभाग के अधिकारी इन दोनों योजनाओं के शेष कार्य को पूर्ण करवा देंगे। **हम अपने स्तर पर भी इन योजनाओं का कार्य पूर्ण करवाने के लिए प्रयासरत हैं।** जो आपकी सरकाघाट डिवीजन की LWSS योजना है, इस पर 58 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। इस योजना पर कुल 64 करोड़ रुपये खर्च किए जाने प्रस्तावित हैं। **इस योजना पर अब तक 80 प्रतिशत राशि खर्च हो चुकी है और हम अप्रैल, 2025 तक इस योजना को तैयार कर देंगे।** दूसरी योजना लगभग 70 करोड़ रुपये की है और **इस योजना पर लगभग 70 करोड़ रुपये ही खर्च किए जा चुके हैं। इस योजना पर कुछ और पैसा लगना है जिसे हम जारी कर देंगे।** इस योजना का कार्य नेशनल हाइवे की वजह से रुका पड़ा है इसलिए आप उनसे बात करें। **हम कोशिश करेंगे कि इस योजना का कार्य वर्ष 2026 के शुरू में पूर्ण कर दिया जाए।**

18.03.2025/1145/RKS/yk-2

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो आपने 175 करोड़ रुपये से 195 करोड़ रुपये नाबार्ड की सीमा बढ़ाई है उसमें आपने यह कहा है कि योजनाओं के रख-रखाव और अपग्रेडेशन के लिए पैसा दिया जा सकता है। बहुत से विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बहुत सी सड़कें और सिंचाई की योजनाएं बनना बकाया हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस पैसे का प्रावधान सभी स्कीमों व रख-रखाव के लिए करें ताकि जब कोई सदस्य मेंटिनेंस या नई स्कीम की प्रपोजल दें तो वे स्कीमें नाबार्ड को प्रेषित की जाएं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने इसमें यह ऑप्शन रखा है कि यदि आपकी लिमिट पूरी नहीं हुई है तो आप अपनी स्कीम नाबार्ड को भेज सकते हैं। यदि आपकी लिमिट पूरी हो गई है तो वह स्कीम वापिस आ जाएगी। जिस सदस्य की 195 करोड़ रुपये की लिमिट पूरी हो चुकी है उसने अपनी लिमिट को एग्जॉस्ट कर लिया है और वह स्कीम वापिस आ जाएगी। हमने इस बजट में नाबार्ड सीमा को 5 करोड़ रुपये और बढ़ाया है। आप इस योजना की

लिमिट के तहत मेंटिनेंस, डे बोर्डिंग स्कूल, नई सड़कों और जल शक्ति विभाग की नई स्कीमों को नाबार्ड को प्रेषित कर सकते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है।

18.03.2025/1145/RKS/yk-3

प्रश्न संख्याः 2525

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के उत्तर में यह दर्शाया गया है कि राजस्व विभाग द्वारा बन्दोबस्त की प्रक्रिया मुहाल निहरी में फरवरी, 2022 में शुरू की गई है। इस कार्य को शुरू हुए 3 वर्ष हो गए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रश्न के उत्तर में जो मुहाल रोहाण्डा, बजीहण, चौकी, जन्द्रोह, चरखड़ी तथा रोहाड़ा दर्शाए गए हैं, इन मुहालों में गत तीन वर्षों में बन्दोबस्त का कितने प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है? दूसरा, आपने यह कहा है कि इन मुहालों में भू-व्यवस्था का कार्य ई0टी0एस0 और डी0जी0पी0एस0 मशीनों से किया जाना है। आप कृपया इस सदन को यह भी जानकारी दें कि ये मशीनें क्या हैं और इनकी उपलब्धता कब तक हो जाएगी तथा यह कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा? प्रश्न के उत्तर में यह भी दर्शाया है कि इन मुहालों में बंदोबस्त के कार्य के लिए कुल 11 पटवारी और 1 कानूनगो नियुक्त किया जाना है। मेरा प्रश्न है कि क्या ये कर्मचारी इस कार्य के लिए पर्याप्त हैं या और कर्मचारियों को इस कार्य के निष्पादन के लिए नियुक्त किया जाएगा?

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

18.03.2025/1150/बी.एस./ए.जी./-1

प्रश्न संख्याः 2524 क्रमांगत

राजस्व मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य के चुनाव क्षेत्र के बंदोबस्त का प्रश्न है, ये सही है कि इनके क्षेत्र में 399 मोहाल हैं और अभी वर्तमन में हमनें केवल 7 मोहालों में ही बंदोबस्त के कार्य की नॉटिफिकेशन की है और मौके पर अभी भी काम शुरू नहीं हुआ है। अब उसका कारण यह है कि बंदोबस्त का जो हमारा सिस्टम है कि यह टी0डी0एस0 और टाइम टेकिंग प्रोसिजर है। अब इस पर मैंने विभाग में कई बार बैठकें भी की हैं कि किस तरह से इस बंदोबस्त के सेटलमैंट को फास्ट ट्रेक पर डाला जाए। यह अभी हमारा ऑन गोइंग प्रोसेस है और अब इसमें बहुत सारी आधुनिक टेक्निक्स भी आई हैं। पहले जहां नाप नपाई के लिए जरेब को ले करके काम होता था, उसमें ई0टी0एस0 और जी0पी0एस0 भी एक नापने का तरीका है, जो आधुनिक उपकरण हैं जिन्हें फास्ट ट्रेक में डाला जा रहा है परंतु नाम नपाई के बाद जब उसका मिलान करना होता है, जो हमारे पुराने कागजात हैं उनके ऊपर सारा कार्य निर्भर है। इसे तेजी से करने की जरूरत है और इसके ऊपर हम गहन विचार-विमर्श कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसे कैसे फास्ट ट्रेक में डाला जाएगा। जहां बदोबस्त का 10-15 साल का समय एक ही जगह पर हो रहा है इसे बढ़ाने की जरूरत है और जो हमारे कर्मचारियों की संख्याः है वह भी सिमित है और इसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है अन्यथा बंदोबस्त के कोई मायने नहीं रहते। अगर एक बंदोबस्त को करने में 15 साल लग जाएंगे उतने में तो दूसरा बंदोबस्त आ जाता है। इस तरह से कोई फायदा नहीं है। मैं माननीय सदस्य की चिंता से बिल्कुल सहमत हूं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम तेजी से इस कार्य को करने जा रहे हैं और जिन मशीनों को हम खरीद नहीं पाए हमें उन्हें खरीदने की भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है परंतु टेंडर प्रकिया में समय लग रहा है। हमारे पास पैसा भी है और टेंडर भी हो गए हैं परंतु मशीनें फिर भी नहीं आई है, मैं इस प्रक्रिया को तेज कवाऊंगा।

18.03.2025/1150/बी.एस./ए.जी./-2

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत विस्तृत जवाब दिया है, मैं संतुष्ट भी हूं और जानता हूं कि समस्या है। परंतु जिस तरह से आज जमीनों को ले करके समस्या है और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। बंदोबस्त एक अच्छी प्रक्रिया है लेकिन मेरी एक और चिंता थी

कि बहुत जगह रिकार्ड खराब हो चुका है, जैसे लट्ठा,करुकाल, मीटर काल, खसरा नंबर मिट गए हैं। क्या मुसाब्बी और नकल मोमी की सहायता से यह बंदोबस्त ठीक हो जाएगा?

अध्यक्ष : यह तो विभाग करेगा ही, क्योंकि यह राजस्व का हिस्सा है।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है कि मुसाबी नहीं है, उसे शायद चूहे खा गए हैं या दूसरे खा गए हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि मोमी भी ठीक नहीं है और तीसरा लट्ठा भी ठीक नहीं है। जब तीनों चीजें मेरे पास नहीं है फिर भी हमें सेटलमैंट रुल्ज के मुताबिक पूरी करनी है। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हमारे पास मुसाबी है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस कार्य को पूरा किया जाएगा।

18.03.2025/1150/बी.एस./ए.जी./3

प्रश्न संख्याः 2526

श्री मोहन लाल ब्राक्टा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर विस्तार से आया है। फिर भी मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जहां तक मेरा डोडरा क्वार का सिविल अस्पताल है, यह दूर दराज का क्षेत्र है और मैं रोहड़ू सिविल अस्पताल की बात करूं तो यह 200 बिस्तरों का सिविल अस्पताल है। इसमें प्रतिदिन 700 से 800 की ओ0पी0डी0 होती है। मैं तो कहूंगा कि जो शिमला में हमारा डी0डी0यू0 अस्पताल है, इससे भी ज्यादा ओ0पी0डी0 सिविल अस्पताल राहड़ू की है। लोग यहां डोडरा क्वार,रोहड़ू और जुब्बल-कोटखाई के लगते क्षेत्र से भी आते हैं। जहां तक इस अस्पताल में खाली पदों की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि सभी पदों को तो एक साथ नहीं भरा जा सकता। परंतु जो मेरा सिविल अस्पताल रोहड़ू है, यहां पर जनरल सर्जन का पद एक साल से खाली पड़ा है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

18.03.2025/1155/DT/AG-1

प्रश्न संख्या 2526 जारी...

श्री मोहन लाल ब्राक्टा जारी..

इसमें जो बहुत सारी वेकैंसीज हैं, मैं यह तो नहीं कह सकता कि सभी को एक साथ भरा जा सकता है, लेकिन जो रोहडू का सिविल हास्पिटल है यहां पर जनरल सर्जन का पद एक साल से रिक्त पड़ा है, मैं माननीय स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस पद को आप जल्द-से-जल्द भरने की कृपा करें और शेष रिक्त पद को फेज-मैन्नर में भरा जाए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले ही विभाग द्वारा यह कहा गया है कि अगले दो महिनों में पूरे प्रदेश में सभी रिक्तियां भर दी जाएंगी। This is adminission from the department itself.

स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को भी बता देना चाहता हूं कि अभी डाकटर्ज के 200 पदों के लिए लिखित परीक्षा हुई हैं और इसके बाद शीघ्र डाक्टर्ज के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। जहां पर सेंसटिव एरियाज है where we need to send the staff immediately with some priority तो वह कार्य आरंभ हो जाएगा। **इसलिए इन्होंने जो सिविल हास्पिटल रोहडू की बात की है, उस पर हमारा भी ध्यान रहेगा और इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो दो भागों में प्रश्न पूछा गया है, पहला रिक्तियों के बारे में दूसरा किस-किस स्थान पर स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं उसके बारे में, तो मैंने विस्तार से इनको बता दिया है। लेकिन जहां तक स्टाफिंग पेटर्न शीघ्रअतिशीघ्र पटरी में आ जाएगा, मैं इस माननीय सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा।**

Speaker : Hon'ble Chief Minsiter wants to supplement the Hon'ble Minister.

13.03.2025/1125/DT/AG-2

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने डोडरा-क्वार की बात कही। मैं स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से डोडरा-क्वार गया था और एक रात वहां पर रूका भी था। मैंने अपने उस प्रवास के दौरान वहां पर भी कहा था, क्योंकि माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री उस प्रवास के दौरान मेरे साथ नहीं जा पाए थे, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि डोडरा-क्वार में स्वास्थ्य संस्थानों में जिन पदों की आवश्यकता है, हम उन्हें स्वीकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त जो ओ.पी.डी. सिविल होस्पिटल रोहड़ू में है, इसमें कोई दोराय नहीं कि वहां पर ओ.पी.डी. की संख्या बहुत अधिक है। उस क्षेत्र के लोगों को वहां के मुख्य चिकित्सालय की बजाए उन के आस-पास के स्वास्थ्य केंद्रों में ही डाक्टर उपलब्ध हो, उस बारे में हमारी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। **मैंने अपने बजट अभिभाषण में भी कहा है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले एक वर्ष के भीतर और सुदृढ़ करेंगे, इसमें रोहडू होस्पिटल को भी शामिल किया जाएगा।**

13.03.2025/1125/DT/AG-3

प्रश्न संख्या : 2527

डॉ जनक राज : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने सवाल किया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने अधिकारियों के पद हैं जो कार्यकारी अधिकारियों के द्वारा चलाए जा रहे हैं? इसके उत्तर में लिखा गया है कि 45 पदों पर कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि यह चरणबद्ध तरीके से और नीड-बेस्ड तरीके से काम करने वाली सरकार के चरण मेरे विधान सभा क्षेत्र में कब पड़ेंगे? क्योंकि मेरे विधान स्भा क्षेत्र की परिस्थितियां पहले ही बहुत खराब है; और इतीन खराब परिस्थितियों में जख्मों में नमक तब लग जाता है जब पदों पर कोई अधिकारी नहीं मिलता, उसमें चाहे मैं कृषि विभाग की बात करूं, चाहे मैं जिला प्रशासन की बात करूं, चाहे ब्लॉक स्तर के कार्यालयों की बात करूं, चाहे बिजली बोर्ड की बात करूं, चाहे होस्पिटल्ज की बात करूं, इन विभागों में सभी के सभी पद कार्यकारी अधिकारी द्वारा

चलाए जा रहे हैं। मैं सरकार से आवश्वासन चाहूंगा कि इन पदों को कब तक भरा जाएगा?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने चरण पड़ने की बात कही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में पक्ष-विपक्ष दोनों साथ ही चलते हैं और इनके चुनाव क्षेत्र में दौरा करते हैं। यह चिंता का विषय है कि न केवल इन्हीं के क्षेत्र में अपितु प्रदेश के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में में इस तरह कि व्यवस्था की गई है कि एक अधिकारी के पास तीन-तीन, चार-चार चार्ज हैं। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी जो जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष भी हैं से इस विषय पर यह चर्चा हुई कि जो ट्राइबल सब-कैडर किसी समय शुरू किया गया था इसको दोबारा से शुरू करने की जरूरत है। क्योंकि जो भी नए अधिकारी बनते हैं वह ट्राइबल एरिया में जाना ही नहीं चाहते। अगर किसी के आर्डर कर भी दिए जाते हैं तो वह दूसरे दिन वापिस आ जाता है। इसलिए जनजातीय क्षेत्रों में केवल 40 प्रतिशत, 35 प्रतिशत या 30 प्रतिशत तक ही पद ही भरे हुए हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जनजातीय क्षेत्रों कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए वहां पर पोस्टिंग्ज प्राथमिकता के आधार पर हों और ट्राइबल सब-कैडर को फिर से बहाल किया जाए।

13.03.2025/1125/DT/AG-4

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य डॉ. जनक राज जी को कहना चाहता हूं कि इनके निर्वाचन क्षेत्र में मेरे चरण जल्द पड़ने वाले हैं, क्योंकि मैं वहां जाने वाला हूं और जब मैं वहां जाऊंगा तो इनसे भी मिलूंगा।

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

18.03.2025/1200/ए.एस.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 2527 ......जारी

मुख्य मंत्री........जारी

माननीय राजस्व मंत्री ने भी कहा है कि हम एक नीति पर काम कर रहे हैं। ट्राइबल बैल्ट्स और पूरे हिमाचल प्रदेश की Population, Demography or Geography के आधार पर सभी पदों का रेशनलाइजेशन (युक्तिकरण) किया जाएगा जिससे कोई भी व्यक्ति खाली न रहे। इस दृष्टि से ट्राइबल की बैठक में भी चर्चा हुई है और इस पर हम गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। हम आने वाले समय में ट्राइबल क्षेत्र व पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक नीतिगत फैसला करने जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जहां तक चरण की बात की है तो बहुत ही शुभ दिन में मैं इनके क्षेत्र में अपने चरण डालने जा रहा हूं। धन्यवाद।

प्रश्न काल समाप्त

18.03.2025/1200/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय रत्न की ओर से एक अनुरोध किया गया है कि उन्होंने अपने जन्मदिवस, जोकि कुछ दिन पूर्व था, के मौके पर आज दिनांक 18-03-2025 को विधान सभा के लाइब्रेरी हॉल में दोपहर के भोजन की व्यवस्था सभी माननीय सदस्यों के लिए की है और सभी माननीय सदस्यों को मेरे द्वारा यह निमंत्रण एक्सटेंड किया जा रहा है। This is the information which I wanted to give you.

अब एक शून्य काल का भी एक विषय आया है।...(व्यवधान) माननीय मुख्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। ...(Interruption) Leader of the House has a priority.

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिलासपुर की घटना पर अपनी एक स्टेटमैंट देने जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, दिनांक 14.03.2025 को बिलासपुर स्थित पूर्व विधायक श्री बम्बर

ठाकुर के सरकारी आवास पर हुई गोलीबारी की घटना पर संक्षिप्त टिप्पणी इस प्रकार से है :-

श्री विशाल चंदेल पुत्र शेर सिंह, निवासी वार्ड नंबर 11, डा० लखनपुर, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के ब्यान पर अभियोग संख्या 58/25, दिनांक 14.03.2025, अधीन धारा 109, 3(5) भारतीय न्याय सहिंता और धारा 25 आयुध अधिनियम, 1959 (आर्मस एक्ट) के तहत पुलिस थाना सदर जिला बिलासपुर में दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दिनांक 14.03.2025 को वह चंगर सेक्टर बिलासपुर में पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर के घर पर मौजूद था। लगभग 3:00 बजे 04 लोग आंगन के अंदर आए और उनमें से 02 ने पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर पर गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी के दौरान शिकायतकर्ता के बाएं पैर में गोली लग गई। पूर्व विधायक श्री बंबर ठाकुर और उनके पी०एस०ओ०/आरक्षी संजीव कुमार को भी गोली लगी।

वर्तमान में पूर्व विधायक श्री बम्बर ठाकुर का आई०जी०एम०सी० शिमला में और पी०एस०ओ०/आरक्षी संजीव कुमार का AIIMS बिलासपुर में इलाज चल रहा है।

18.03.2025/1200/ए.एस.-एन.जी./3

अन्वेषण की प्रगति रिपोर्ट :-

- फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम द्वारा घटनास्थल का दौरा किया गया और घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए।
- निरीक्षण के दौरान मौके पर 24 खाली कारतूस/लेड (11 खाली कारतूस, 2 बुलेट लेड 7.62 mm, 10 खाली कारतूस 7.65 mm और 1 खाली कारतूस 9 mm) बरामद किए गए।
- सी०सी०टी०वी० फुटेज, आई०टी०एम०एस० और आई०पी०डी०आर०/ सी०डी०आर०/डंप डेटा सहित डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
- बरादात में प्रयोग किए गए संदिग्ध वाहन एच०पी० 69 - 7257 (बोलेरो) को चालक रितेश शर्मा उर्फ रिशु पुत्र राज कुमार, निवासी गांव व डाकघर रोहिन, तहसील घुमारवीं, बिलासपुर, उम्र 24 वर्ष को वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया गया है।

फोरेंसिक विशेषज्ञों के माध्यम से वाहन की जांच की गई और 10 जिंदा कारतूस 7.65 मिमी, 1 खाली कारतूस 8 मिमी और 1 खाली मैगजीन बरामद की गई।

- दो अन्य आरोपी रोहित कुमार राणा पुत्र गुरपाल सिंह, निवासी गांव व डाकघर लखाणु, तहसील श्री नैना देवीजी, जिला बिलासपुर, उम्र 29 वर्ष और मंजीत सिंह नड्डा पुत्र नंद लाल ठाकुर, निवासी गांव व डाकघर बिनौला, तहसील सदर, जिला बिलासपुर, उम्र 33 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

18.03.2025/1205/AS/PB/-1

मुख्य मंत्री जारी...

- उपरोक्त तीनों आरोपियों रोहित कुमार, मंजीत सिंह व चालक रितेश शर्मा उर्फ रिशु को दिनांक 16.03.2025 को न्यायालय में पेश करके चार दिन का पुलिस रिमांड (19.03.2025 तक) प्राप्त किया गया।
- जांच के दौरान यह पाया गया कि उपरोक्त दोनों आरोपी मुख्य साजिशकर्ताओं में से है और लगातार गोलीबारी की घटना की निगरानी और समन्वय कर रहे थे। गोलीबारी की घटना में कुल 04 शूटर शामिल थे। अब तक दो शूटरों अमन पुत्र श्री अशोक निवासी रितौली, रोहतक, हरियाणा और सागर पुत्र कुलदीप निवासी रितौली, रोहतक हरियाणा की पहचान हो चुकी है। बिलासपुर में इन शूटरों के ठहरने के स्थान की पहचान हो चुकी है।
- अपराधियों की तलाश/पकड़ के लिए अलग-अलग टीमें गठित कर पड़ोसी जिलों/राज्यों को भेजी गई हैं।
- हरियाणा के उपरोक्त दोनों आरोपियों की सी0सी0टी0वी0 फुटेज की तस्वीरें पड़ोसी जिलों/राज्यों को भेजी गई हैं। हरियाणा पुलिस की सहायता भी ली जा रही है।
- मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय द्वारा श्री ज्ञानेश्वर सिंह, भा0पु0से0, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पु0मु0 के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमती सौम्या

सम्वासिवन, डी0आई0जी0 मण्डी की अध्यक्षता में एक विशेष अन्वेषण दल (SIT) का गठन दिनांक 15.03.2025 को किया गया है।

- अभियोग का आगामी अन्वेषण नियमासनुसार प्राथमिकता के आधार पर जारी है।

आरक्षी संजीव कुमार पी0एस0ओ0 की बहादुरी की यह सदन सराहना करता है। उसने गोली लगने के बावजूद जान पर खेल कर वापसी फायर कर वहां खड़े और आसपास के लोगों की जान बचाई, यह सदन उसकी सराहना करता है।

अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार किसी भी आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। इस विधान सभा में इस मामले में हम अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए एक्ट लाने जा रहे रहे हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की वारदातें न हों। इस वर्तमान विधानसभा के सत्र में आने वाले समय में हम यहां एक्ट लेकर आएंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई वारदात न हो सके, धन्यवाद।

18.03.2025/1205/AS/PB/-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, यह घटना देव भूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से घटित हुई है यह कई तरह के संकेत दे रही है। पहली बात तो यह है कि इस घटना की हम निंदा करते हैं। मुख्य मंत्री जी ने अपनी स्टेटमेंट के माध्यम से सम्मानित सदन को जो जानकारी दी है और उस जानकारी के अनुसार जांच-पड़ताल की प्रक्रिया अभी तक चली है और पुलिस कार्यवाही के लिए आगे बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं की बहुत जल्दी उसमें कार्रवाही होगी। मुझे लगता है कि इस विषय की जांच-पड़ताल की प्रक्रिया पूरी होने पर मालूम पड़ेगा कि इसका क्या कारण है? जिस तरह से यह घटना घटी है इससे पूरे हिमाचल प्रदेश में एक दहशत और डर का माहौल बना हुआ है। जैसा कि आपने कहा कि डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व विधायक की जान खतरे से बाहर है और उनके पी0एस0ओ0 की जान भी खतरे से बाहर है। यह अच्छी बात है। परन्तु जब तक जांच-पड़ताल की सारी प्रक्रिया खत्म नहीं होती है, तब तक के लिए राजनैतिक ब्यानबाज़ी जो पूर्व-विधायक महोदय कर रहे हैं वह दुभाग्यपूर्ण है। अपने इलाज के लिए AIIMS (All India Institute of Medical Sciences) में न जा कर किसी अन्य अस्पताल में इलाज

करवाने की इच्छा भी हो सकती है। लेकिन इस आरोप के साथ कि उन्हें वहां मार देंगे तथा इस प्रकार से राजनैतिक लोगों का नाम लेना मैं समझता हूं कि बहुत दुभाग्यपूर्ण है। यह हमारे प्रदेश की न संस्कृति है, न संस्कार है और न ही इस तरह की उम्मीद की की जा सकती है। इस तरह से कहना हमारे डॉक्टरों का भी अपमान है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

18.03.2025/1210/A.P/D.C/1

श्री जय राम ठाकुर द्वारा जारी .....

एम्स प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है और देश का भी नामी अस्पताल है, जो हमारे प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। इन संस्थानों के बारे में ऐसी टिप्पणी करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय जिस प्रकार से पूर्व विधायक लगातार मीडिया के सामने, व अन्य प्लैटफोर्मस में ब्यान दे रहे है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी investigation process चली हुई है। हम इस बात को कह रहे है कि दोषियों के खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन वह आरोपियों को स्वयं तय कर रहे हैं। कुछ लोगों के नाम ले रहे है कि इसके पीछे वो है। मैं समझता हूं कि यह दूर्भाग्यपूर्ण है इन सब चीज़ो को रोकना आवश्यक है। आपकी ही सरकार है, आपकी पार्टी से उनका तालुक है, आपकी पार्टी से ही वह पूर्व में विधायक रहे और ऐसी सूरत में यह सलाह उन तक पहुंचाई जाए तो मुझे लगता है कि उचित रहेगा।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश का वातावरण खराब करने की एक अन्य कोशिश की जा रही है। कुछ अरसे से मीडिया में भी देखा गया है कि हमारे पडोसी राज्य के नौज़वान हमारे प्रदेश में आते है, उनका स्वागत है।

लेकिन वह यहां हुड़दंग मचा रहे है। जिस तरह से अपने वाहनों में भिंडरांवाले का फोटों, झण्डें लगाकर उनके सम्मान में बाते कह रहे है और जब उनको रोका जा रहा है तो वह कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे है। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की मनाली डिपू की बस को दिल्ली या पंजाब में कही रोका, तलवारें ले कर के ड्राइवर को बस रोकाने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद जहां पर मुख्य मंत्री जी का फोटो लगा है उसके साथ भिंडरांवाले का फोटो लगा दिया गया। पूरे सोशल मीडिय में यह सब चल रहा है। क्या मुख्य मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेगें की पंजाब की सरकार के साथ इस विषय को उठाएंगे और इस विषय पर एक सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाने की अपील करेगें? अन्यथा इससे स्थिति और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इन सब चीज़ों को सरकार को गंभीरता से से लेना चाहिए। इसी तरह से एक और घटना है, HPPCLएक Chief Engineer है जोकि कई दिनों से गायब है। माननीय राजस्व मंत्री जी ने भी इस संदर्भ में अपनी चिन्ता जाहिर की है। लेकिन उनका कुछ पता नहीं लग पाया है।

18.03.2025/1210/A.P/D.C/2

यह चिन्ता का विषय है, हमारा हिमाचल प्रदेश किस दिशा में जा रहा है? मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी इन सारी बातों का संज्ञान ले और आवश्यक कार्यवाही इस पर की जाएं, धन्यवाद।

Speaker : ...(Interruption)... There will be no debate on this issue, your(Hon'ble Member Shri Trilok Jamwal) concerns are already ventilated by Hon'ble Leader of Opposition.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूर्व मुख्य मंत्री और विपक्ष में नेता द्वारा कुछ बातें कही गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि investigation process चल रहा है, मैं उनसे बात करूंगा कि इस प्रकार की बायानवाजी न करें, मैं व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करूंगा।

दूसरी बात जो पोस्टर की बात चली है उस पर हमने एफ.आई.आर. दर्ज की है। कई बार कुछ शरारती लोग होते है, जो इस प्रकार की वारदात करते हैं। जैसा अपने कहा है, वह मनाली बस की बात है, मैं पंजाब के मुख्य मंत्री से इस बारे में बात करूंगा।

तीसरी बात जो Chief Engineer नेगी साहब की बात है, मैं उनके परिवार के लोगों से मिला था। इस बारे में मैंने डी0जी0पी0 साहब से बात की थीं और उन्हें special instructions दिये है कि उनका पूरा पता करें। उनकी location का पता नहीं लग रहा है, यह सारी बातें अलग-अलग वाक्यों से संबंधित है। Chief Engineer की बात पर हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि उनका पता लगाया जा सके। लेकिन उन्होंने अपना मोबाइल बंद रखा है। जिससे उनकी location का कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। अगर ऑन होता तो location का पता लगता। लेकिन हमारी सरकार, Chief Engineer के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगा है और गंभीरता से उनकी तालाश कर रही है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

18.03.2025/1215/AT/ DC/1

शून्यकाल

डॉ0 जनक राजः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मेरा विधानसभा क्षेत्र जल विद्युत परियोजनाओं से भरा पड़ा है। अनेकों जल विद्युत परियोजनाएं वहां पर चल रही हैं। वर्तमान समय में मै सरकार का ध्यान एक जल विद्युत परियोजना बी0वी0 हाइड्रो की ओर खींचना चाहूंगा। वहां पर स्थानीय पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि और स्थानीय लोगों के हितों को दरकिनार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि जो सरकार ने नीति बनाई है उसके तहत रोजगार स्थानीय लोगों को मिले। टेक्निकल व्यक्ति अगर वहां उस पंचायत में नहीं मिलता है तो उसके लिए जो-जो भी प्रावधान सरकार के द्वारा तय किए गए हैं, उनका पालन हो। साथ ही नॉन टेक्निकल आदमी जैसे ड्राइवर है, चाय बनाने वाला है, चपरासी की नौकरी के लिए कोई आदमी चाहिए तो कम से कम उस स्थानीय पंचायत के लोग, जो लैंड लूजर हैं, जो वहां पर प्रदूषण झेल रहे हैं और जिनकी अपनी जमीनों का नुकसान हुआ है, उनको प्राथमिकता देना यह सरकार

सुनिश्चित करें। मैं सरकार से इस विशेष मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की उम्मीद करता हूं ताकि जो लोग हफ्ते भर से वहां पर धरने पर बैठे हैं, उनको वहां समाधान मिल सके, धन्यवाद।

Speaker: This is Zero Hour question, if Hon'ble Minister wants to reply, he can. Otherwise the House has taken cognizance of this issue.

मुख्य मंत्री : मानीनय अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति वहां लोकल लोगों को काम देने की भी है लेकिन जब एम0ओ0यू0 होता है तो कई बार नीति में थोड़ा संशोधन कर दिया जाता है। यह जो ए0डी0बी0 हाईड्रो जो प्रोजेक्ट है, उसका 60-70% काम हो चुका है। जब 60-70% काम हो जाए तो बीच में काम की कोई ऐसी नीति नहीं है लेकिन फिर भी वहां लोकल लोगों को किस प्रकार का काम मिल सकता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में प्राइवेट पार्टी पैसा लगती है और जो प्राइवेट पार्टी पैसा लगाएगी उसको किस व्यक्ति के लोकल काम की कौन सी जरूरत है, वह देखा जाएगा **लेकिन जो जरूरत होगी, हम कंपनी वालों से बात करेंगे।**

18.03.2025/1215/AT/ DC/2

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाएंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जो कि इस प्रकार है:-

मंगलवार, 18 मार्च, 2025 1. शासकीय/विधायी कार्य।

2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 सामान्य चर्चा।

बुधवार, 19 मार्च, 2025

1. शासकीय/विधायी कार्य ।

2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 सामान्य चर्चा।

वीरवार, 20 मार्च, 2025

1. शासकीय/विधायी कार्य ।

2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 सामान्य चर्चा।

शुक्रवार, 21 मार्च, 2025

1. शासकीय/विधायी कार्य ।

2. बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 सामान्य चर्चा एवं समापन।

शनिवार, 22 मार्च, 2025

1. शासकीय/विधायी कार्य।

2. गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस।

18.03.2025/1215/AT/ DC/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम अधिनियम, 1979 की धारा 23 (6) के अन्तर्गत

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम का वार्षिक प्रशासनिक विवरणिका, वर्ष 2023-24 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

18.03.2025/1215/AT/ DC/4

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री किशोरी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2024-25) के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूं:-

1) समिति का 17वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2018-19) 31 मार्च, 2019 के ऑडिट पैरा संख्याः 4.27 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का 18वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (आर्थिक क्षेत्र) (वर्ष 2018-19) 31 मार्च, 2019 के ऑडिट पैरा संख्याः 4.28 की समीक्षा पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है।

18.03.2025/1215/AT/ DC/5

वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान

अध्यक्षः अब बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 पर सामान्य चर्चा होगी । आज से वित्तीय वर्ष 2025 -26 के बजट अनुमानों/वार्षिक वित्तीय विवरण पर सामान्य चर्चा प्रारंभ हो रही है तथा इसका समापन 21 मार्च 2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उत्तर के साथ हो जाएगा। समय की उपलब्धता को देखते हुए

श्रीमती एम0डी0द्वारा जारीः

18.03.2025/1220/MD/HK/1

अध्यक्ष : क्रमागत

विपक्ष के माननीय नेता को 45 मिनट का समय तथा अन्य सदस्य को अधिकतम 15-20 मिनट का समय सुनिश्चित किया गया है। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन रहेगा कि वह अपना-अपना भाषण बजट तक ही सीमित रखकर निर्धारित अवधि के भीतर समाप्त करें। सर्वप्रथम मैं माननीय विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी को चर्चा आरंभ करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए जो बजट अनुमान माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किए हैं, मैं उस पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार का, व्यवस्था परिवर्तन की और श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की सरकार का यह चरणबद्ध तरीके से तीसरा बजट है। जब तीसरा बजट प्रस्तुत होता है तो समझ लेना चाहिए कि आपकी सरकार की उम्र काफी बढ़ गई है और अब वह उम्र ढलान की तरफ है। इसके बाद मात्र दो बजट होंगे। मैं इस बात को भी साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो एक स्थापित व्यवस्था कई वर्षों से चल रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप आपका कार्यकाल भी घटता जा रहा है। आपका चरणबद्ध तरीके से तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ और अगली बार चरणबद्ध तरीके से जब आपका चौथा बजट प्रस्तुत होता है तो उसको लोग सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं है। चरणबद्ध तरीके से जब पांचवा बजट प्रस्तुत होता है तो उसको लोग

न सुनते हैं और न ही मानते हैं। आपका जो बजट प्रस्तुत हुआ यह सचमुच में हक़ीकत से बहुत दूर है। आपने शेर सुनाकर शुरू किया इसलिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं :-

नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं,
जमीन पर चांद सितारों की बात करतें हैं।
वह हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले,
भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं।
मिली कंमाड तो अटकी नज़र खज़ाने पर,
नदी सूखा के किनारों के बात करते हैं।

यानी कि नदी को सूखाकर आप किनारों की बात करते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान बजट की यह स्थिति है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

18.03.2025/1225/केएस/एचके/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---

अध्यक्ष महोदय, 58,514 करोड़ रुपये का बजट इस बार प्रस्तुत किया गया है और हिमाचल प्रदेश के आज तक के इतिहास में यह सबसे कम ग्रोथ वाला बजट है जिसमें मामूली सी ग्रोथ है। अगर हम थोड़ी नज़र डालें तो वर्ष 2018-19 में 41,440 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया था और वह पिछले बजट की तुलना में 5,702 करोड़ रुपये की इन्क्रीज़ के साथ था जो लगभग 16 प्रतिशत थी। वर्ष 2019-20 में 44,388 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत हुआ था और पिछले बजट की तुलना में 2,948 करोड़ रुपये की इन्क्रीज़ के साथ थाजिसमें 7.11 परसेंट की इन्क्रीज़ थी। वर्ष 2020-21 में 49,131 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया था, 4743 करोड़ रुपये की उसमें इन्क्रीज़ थी जो लगभग 10.70 थी। वर्ष 2021-22 में जब भयंकर कोविड का दौर पूरी दुनिया में, पूरे देश व इस प्रदेश में था तो उस समय 50,192 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया और उसमें भी इन्क्रीज़ 1061 करोड़ रुपये की थी जो कि 2.16 प्रतिशत थी। वर्ष 2022-23 में 51,365 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया था जिसमें 1173 करोड़ रुपये की इन्क्रीज़ थी जो कि 2.34 प्रतिशत थी।

वर्ष 2023-24 में जो आपने बजट प्रस्तुत किया था वह 53,412 करोड़ रुपये का था जिसमें 2047 करोड़ रुपये की इन्क्रीज़ थी जो 4 प्रतिशत के लगभग थी। वर्ष 2024-25 में 58, 453 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया गया था जिसमें 5031 करोड़ रुपये की इन्क्रीज़ थी जो कि 9.42 प्रतिशत थी। वर्ष 2025-26 में आपने 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है इसमें इन्क्रीज़ मात्र 71 करोड़ रुपये की है जो कि 0.12 परसेंट है। उसके बाद जो आपने घोषणाएं की, वायदे किए, उनमें तो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि अब हकीकत दुनिया भी समझ चुकी है, आप उसको कब तक छिपाएंगे? आपने हिमाचल प्रदेश में झूठ बोलकर सरकार बनाई। अगर झूठ शब्द अच्छा नहीं लगता तो असत्य बोल कर आप सत्ता में आए हैं। लोगों को गुमराह कर सत्ता में आए हैं क्योंकि आपने गारंटियां दी थीं और उनका स्वभाविक रूप से असर पड़ा लेकिन आपका तीन साल का कार्यकाल बीत गया। गारंटियों से तो आप बिल्कुल विमुख हो गए हैं, उनके बिल्कुल विपरीत आप काम कर रहे हैं। आप उस वक्त इस माननीय सदन में थे। क्या उस वक्त आपको मालूम नहीं था कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति किस दौर से गुजर रही

18.03.2025/1225/केएस/एचके/2

है? आने वाले समय में हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति और खराब होगी, यह आपको मानकर चलना चाहिए। सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, सिर्फ कुर्सी हासिल करने के लिए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, इस बात के लिए आपने झूठ बोला और उसके बाद आपने जो गारंटियां दीं, अगर आपने उन पर अमल किया होता तो भी हम समझ सकते थे लेकिन ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, अभी थोड़ा रुकिए। आपने बाद में जवाब देना है। उन गारंटियों को आपने कूड़ेदान में डालकर ब्यास नदी में प्रवाहित कर दिया। आगे कि बातें तो आप करेंगे ही लेकिन पहले तो यह बात है कि आपकी जो फ्लैगशिप स्कीम्ज़ हैं, मुख्य मंत्री जी ऐसा नहीं है कि आप पिछली बातों को छोड़कर अबकी बार नई बातें कह कर और अगली बार इन बातों को छोड़कर, उससे अगली बार फिर अगली बार, चरणबद्ध तरीके से झूठ बोलते हुए आगे बढ़ेंगे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.03.2025/1230/av/yk/1

श्री जय राम ठाकुर ------- जारी

आपको कहीं पर तो सत्यता के साथ चलना चाहिए। आपकी सरकार के कार्यकाल के तीसरे वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। परंतु आपके पहले बजट की योजनाएं भी अभी धरी-की-धरी पड़ी हुई हैं। उन पर काम नहीं हो पाया, काम तो क्या होना उनको तवज्जो ही नहीं दी जा रही। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यह है कि जो भरोसा एक नेतृत्व पर होना चाहिए वह भरोसा अब टूट चुका है। कोई भी सरकार भरोसे पर चलती है और आपका एक भरोसा तो तब टूटा जब आपने गारंटीज दीं और फिर उनको बाद में पूरा करने से मुकर गए। चुनाव से पहले दी गई गारंटीज के बारे में थोड़ा-सा समझा जा सकता है कि वे राजनैतिक परिस्थितियों के तहत दी होंगी परंतु बजट तो हक़ीकत होना चाहिए। आप जो बजट प्रस्तुत करते हैं उसके हिसाब से काम नहीं करते। मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि आपके अधिकारी जो आपको बजट बनाकर देते हैं आपकी उस बारे में काम करने की इच्छा नहीं है या आप जो बजट के अंतर्गत योजनाएं बनाकर देते हैं उस पर आपके अधिकारियों की काम करने की इच्छा नहीं है; ये सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिएं। आपकी फ्लैगशिप योजनाएं जैसे सुख शिक्षा योजना, सुख सम्मान निधि योजना, सुख आश्रय योजना, राजीव गांधी स्टार्टअप योजना; अगर हम पिछले बजट की बात करें तो उसमें आपका 37.7 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। लेकिन जितना बजट प्रावधान है आपने होर्डिंग्ज के माध्यम से प्रचार करके उससे ज्यादा पैसा खर्च किया। यह आज की तारीख में हिमाचल प्रदेश में सच्चाई है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि तीन वर्ष के उपरांत भी आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि यह आपकी सरकार है। आपकी सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष बीत चुके हैं और तीसरा वर्ष शुरू हो चुका है। मैं समझता हूं कि तीसरे वर्ष के बाद तो समय फटाफट निकलेगा। लेकिन आपको अभी भी यह अहसास नहीं हो रहा है कि आप लोग सत्ता में हैं। आपको जितना जिक्र अपनी सरकार का करना

चाहिए उससे ज्यादा जिक्र तो आप लोग हमारी सरकार का करते रहते हैं। अभी तक आप एक ही गीत गा रहे हैं कि जय राम ठाकुर ने लोन लिया और माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने पैसा नहीं दिया। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें सच्चाई को समझने की आवश्यकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2017 में जब यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और

18.03.2025/1230/av/yk/2

मुझे यहां प्रदेश सरकार में मुख्य मंत्री का दायित्व मिला तो क्या आपकी सरकार उस वक्त हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट देकर गई थी? उस वक्त आपने हमें लगभग 50,000 करोड़ रुपये का ऋण विरासत में दिया था। लेकिन हमने उस हकीकत को स्वीकार किया क्योंकि सरकारें आती रहती हैं और ऋण लेना आज की परिस्थिति है। परंतु बार-बार गाने से अच्छा इसको कम करने के संदर्भ में विचार-विमर्श करना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने आपकी तरह कोसते-कोसते वक्त नहीं गुजारा बल्कि काम करते-करते वक्त गुजारा है। लेकिन आप एक ही काम कर रहे हैं और आपके इस बार के बजट के पहले पैरा में भी यही है कि पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी की सुरक्षा नहीं की गई और गलत तरीके से यह काम या वह काम किया गया।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

अब तो आपको सब कुछ ठीक करने के लिए बहुत ज्यादा समय मिल गया है और मेरे हिसाब से दो वर्षों का कार्यकाल कम नहीं होता क्योंकि अभी आप तीसरे वर्ष का बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कब तक पूर्व की सरकार को कोसते रहेंगे? आप जो यह बोलते हैं कि जय राम ठाकुर ने ऋण लिया तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि ऋण लेना आज की तारीख में सभी सरकारों की विवशता हो गई है और यह हकीकत है। मैं बताना चाहता हूं कि वर्ष 1993 तक हिमाचल प्रदेश के ऊपर न के बराबर ऋण था। लेकिन वर्ष 1993 से 1998 में ऋण लेने की शुरुआत हुई और वह गलत शुरुआत हुई थी, उससे बचा जा सकता था।

टी सी द्वारा जारी

18.03.2025/1235/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री जय राम ठाकुर... जारी

लेकिन उस समय कारपोरेशन के नाम पर अनावश्यक रूप से ऋण लिया गया। वे ऋण भी लिए गए जिनकी जरूरत नहीं थी, और एक बार जब कोई व्यक्ति या सरकार ऐसी स्थिति में फिसल जाती है, तो उसका संभलना मुश्किल हो जाता है। यह फिसला हुआ पांव उस समय का है, जिसका असर अब दिख रहा है और अभी भी हालात पटरी पर नहीं आ सके हैं। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ी, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस बात को आप कब स्वीकार करेंगे? हम उन बातों का जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन यह जरूर कहना चाहते हैं कि आज की स्थिति में हिमाचल प्रदेश पहले से कहीं अधिक ऋणग्रस्त हो चुका है। मात्र दो वर्षों में ही सरकार ने इतने ऋण लिए हैं कि पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारी पिछली सरकार ने अपने कार्यकाल में 28,744 करोड़ रुपये का ऋण लिया था और हमने ब्याज व किस्तों सहित लगभग 38,500 करोड़ रुपये अदा किए थे। हमने कभी भी ऋण की लिमिट को एक्सीड नहीं किया।

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इसके विपरीत, मौजूदा सरकार ने मात्र दो वर्षों में ही लगभग 27,000 करोड़ रुपये का ऋण ले लिया है। अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश का कुल ऋण एक लाख करोड़ रुपये को पार कर जाएगा। इसका श्रेय व्यवस्था परिवर्तन, सुख की सरकार और श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नाम पर जाएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा, तब यह दर्ज होगा कि हिमाचल प्रदेश के ऋण ने एक लाख करोड़ का आंकड़ा कब पार किया था और उसके साथ उस समय की सरकार का नाम भी जोड़ा जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें भी कई चिंताजनक बातें हैं। आपने जो बजट यहां पर प्रस्तुत किया है उसके बाद हिमाचल प्रदेश में विकास की संभावनाएं लगभग बंद होती नजर आ रही हैं। वर्ष 2024-25 में रोड, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म और सिविल एविएशन के लिए 2,700 करोड़ रुपये का बजट था, लेकिन वर्ष 2025-26 के लिए इसमें 1,522.45 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है।

एन0एस0 द्वारा जारी ...

18-03-2025/1240/NS-AG/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

अबकी बार आपने 2700 करोड़ रुपये की बजाय लगभग 1522 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया है और उसमें 1178.27 करोड़ रुपये की कमी की है यानी कि माइनस 43.63 प्रतिशत की कमी आई है। आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। आप सपने दिखा रहे हैं कि हम इलैक्ट्रिक व्हीकल्ज चलाएंगे और आप ग्रीन हिमाचल की कल्पना दे रहे हैं। परन्तु आप बजट में कटौती कर रहे हैं और आप सड़क एवं परिवहन विभाग के बजट में 1522 करोड़ रुपये की कटौती कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब अगर फ्लड कंट्रोल एंड इरीगेशन की बात की जाए तो पिछले वर्ष 2024-25 का बजट 300.66 करोड़ रुपये था और इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 201 करोड़ रुपये का बजट है तथा इसका डिफरेंस 99.66 करोड़ रुपये है। आपने सीधा 32.9 प्रतिशत का कट मारा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि माननीय मुकेश जी के विभाग को इतनी मार क्यों पड़ रही है? आगे अगर वाटर सप्लाई की बात की जाए, पिछले वर्ष का बजट 883 करोड़ रुपये का था और अबकी बार वर्ष 2025-26 के लिए 499 करोड़ रुपये का बजट है यानी 383 करोड़ रुपये की कमी की गई है। इसका मतलब यह है कि 43.45 प्रतिशत सीधा कट मारा गया है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर शिक्षा मंत्री जी नहीं बैठे हैं। एलीमैंटरी एजुकेशन में पिछले वर्ष 214 करोड़ रुपये का बजट था और अबकी बार 182 करोड़ रुपये का बजट है और माइनस14.76 प्रतिशत की कमी की गई है। हायर एजुकेशन में भी 3.18 प्रतिशत की कमी

है। हैल्थ एंड आयुर्वेद विभाग की बात करें तो पिछले वर्ष 520 करोड़ रुपये का बजट था और अबकी बार 490 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है तथा इसमें भी 5.78 प्रतिशत की कमी की गई है।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा गया कि हम अर्थव्यवस्था को ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ ले जाना चाहते हैं। आपने बहुत लम्बा बोला और कहानियां सुना करके किसानों के दर्द को दिल का दर्द बताया। बजट पर कहानियां सुनाने से कुछ नहीं बनेगा। आपने क्या बजटरी प्रोवीजन्ज किए हैं और आप उन योजनाओं को कैसे लागू करेंगे? हमारी अपनी स्थानीय भाषा में कहते हैं कि जेबा नी देल्ला चढ़ना रेला और आपकी भी यही स्थिति है। पिछले वर्ष कृषि के लिए 1009 करोड़ रुपये का बजट था और अबकी बार

18-03-2025/1240/NS-AG/2

616 करोड़ रुपये का बजट है तथा उसमें 393 करोड़ रुपये का कट है। इसमें भी 39 प्रतिशत की कमी की गई है।

अध्यक्ष महोदय, Women and Child Development including Nutrition and Others जो हैड है उसमें पिछली बार 465 करोड़ रुपये का बजट था और अबकी बार 311 करोड़ रुपये का बजट है। आपने 154 करोड़ रुपये कम किए और 33.14 प्रतिशत की कमी की है। अगर हम टोटल कहें तो पिछले वर्ष 9,990 करोड़ रुपये का बजट था और इसमें मैंने मुख्य विभागों का ही यहां पर बताया है जबकि और भी कई विभाग हैं।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.03.2025/1245/RKS/ag-1

श्री जय राम ठाकुर जारी.....

पिछले बजट की तुलना में इस बार 9,989 करोड़ रुपये की बजाय 7,634 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया है। इसका मतलब है कि आपने प्रमुख विभागों में 2,354 करोड़ रुपये से अधिक की कटौती की है। ये वही विभाग हैं जो जमीनी स्तर पर विकासात्मक कार्य

करते हैं और आपने इन विभागों में इतनी बड़ी कटौती की है। यह लगभग 23.57 प्रतिशत की कटौती है और इसके बावजूद आप यह कह रहे हैं कि हम बहुत विकास करेंगे। इसमें सबसे बड़ी चिंता का विषय कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम करना है। कोविड के दौर में भी हिमाचल प्रदेश में कैपिटल एक्सपेंडिचर में इतनी कमी नहीं आई थी। वह संकट का समय था लेकिन इसके बावजूद भी हमने विकास के साथ कोई समझौता नहीं किया। हमने समय पर कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन जारी की और बेरोजगारों को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए। लेकिन आपने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में कमी की है उस कमी के कारण आप भविष्य में किस प्रकार विकास कार्य करवाएंगे? हमने वर्ष 2017-18 में कैपिटल एक्सपेंडिचर में 61 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इस राशि को 3,756 करोड़ रुपये और वर्ष 2022 में 6,029 करोड़ रुपये तक पहुंचाया। यह हमारी आगे बढ़ने और बढ़ाने की सोच है। बेहतर तरीके से आगे बढ़ने के साथ यह भी आवश्यक है कि लोगों को हर क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं मिलें और इसे सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

अध्यक्ष : श्री जय राम ठाकुर जी माननीय मुख्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कृपया एक मिनट बैठ जाइए। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं तो मैं स्वयं कहता हूं कि इन्हें बोलने का पर्याप्त समय दीजिए और आप इन्हें उचित समय भी देते हैं। मैंने नेता प्रतिपक्ष की पूरी बात सुनी है। ये कह रहे हैं कि हमारे बजट का आकार 71 करोड़ रुपये बढ़ा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं... (व्यवधान) बजट के पैरों में मैंने यह लिखा है कि किस प्रकार RDG में टेपरिंग की गई है। इनके समय में पहले 11,000 करोड़ रुपये फिर 9,000 करोड़ रुपये और फिर 8,000 करोड़ रुपये आए। हमें RDG के रूप में 3, 257 करोड़ रुपये मिले हैं। अगर यह टेपरिंग नहीं की गई होती और 15वें वित्तायोग द्वारा दिए गए 37,000 करोड़ रुपये की राशि को हर साल समान रूप से रखा गया होता तो बजट में 3,000 करोड़ रुपये और बढ़ सकते थे। इसलिए हमने सच्चाई को

18.03.2025/1245/RKS/ag-2

सामने रखा है। जब RDG में 3,000 करोड़ रुपये की कमी हो रही है तब भी हमने अपने संसाधनों से 71 करोड़ रुपये की वृद्धि की है। ऐसा पहले 15वें वित्तायोग में कभी नहीं हुआ था। 15वें वित्तायोग में जो टैक्स का डिवैल्यूएशन था उसके अनुसार वर्ष 2012-17 के बीच 40,000 करोड़ रुपये मिलने थे। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे साल में 8-8 हजार करोड़ मिलेंगे लेकिन फिर वर्ष 2017 में क्या हुआ? 15वें वित्तायोग ने कहा कि अब आपको 37,000 करोड़ रुपये मिलेंगे। वित्तायोग ने पहले साल में 11,000 करोड़ रुपये, दूसरे साल 9,000 करोड़ रुपये, तीसरे साल 8,000 करोड़ रुपये जारी किए और हमारे समय में यह राशि घटाकर 6,000 करोड़ रुपये कर दी।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

18.03.2025/1250/बी.एस./ए एस/-1

मुख्य मंत्री जारी...

जो हमारा पांचवा वित्त आयोग समाप्त हो रहा है, बजट में यह स्पष्ट लिखा गया है कि यह हमारा छः हजार करोड़ रुपये से घट कर आर0डी0जी0 3,257 करोड़ रुपये रह गई। उस 3,257 करोड़ रुपये की भी तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए पूर्ति करनी है। उस पैसे की पूर्ति हमने कैसे करनी है, उसे डाला गया और उसके अलावा 31 करोड़ रुपया हमने अधिक इसलिए लाया ताकि हिमाचल प्रदेश की जनता और सभी सदन के माननीय सदस्यों को यह बताया जाए कि अगले वर्ष हमारी जो आर0डी0जी0 है उसमें 3,257 करोड़ रुपये का कट लग रहा है। दूसरा आपको बताना चाहा रहा हूं कि जो नम्बर आपने आई0पी0एच0, लोक निर्माण विभाग और कैपिटल एक्सपेंडिचर के दिए हैं, मैं उसका उत्तर आपको बाद में दूंगा। मैं आपके ध्यान में लाना चाहा रहा हूं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके समय जी0एस0टी0 कंपनसेशन था। उसे मैंने मेंशन किया है, उस बात को आप खा गए। जी0एस0टी0 कंपनसेशन सैस वर्ष 2017-18 में मिलना शुरू हुआ था। आप उस वक्त मुख्य

मंत्री थे। उस समय आपको 3200 करोड़ रुपये जी0एस0टी0 कंपनसेशन आया था और जून, 2022 तक आपको 3200 करोड़ रुपया आता रहा और आपने रेवड़ियां बांट दी। आपने चुनाव जीतने के लिए 5,000 करोड़ रुपया बांट दिया। जी0एस0टी0 का 16,000 करोड़ रुपया आया। मुख्य मंत्री हो करके आपने पैसे को दान में दे दिया। परंतु आपने अपने आपको एक अच्छा वित्त मंत्री बन करके नहीं दिखाया। अगर आप अच्छे वित्त मंत्री होते तो 16,000 करोड़ रुपये के कर्ज को कम कर देते। इसलिए मैं आप से कहना चाहा रहा हूं कि पहले जो पेज आप खा रहे हैं उन पेजिज की सच्चाई पर भी जाइए। मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट बुक में जो लिखा गया है वह तथ्य है और जो बात लिखी गई है वह भी तथ्यों से परे नहीं है। अब झूठ कौन बोल रहा है? मैं आपके सामने कह रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो पूर्व मुख्य मंत्री उठ करके अभी बता सकते हैं। क्या जी0एस0टी0 कंपनसेशन 16,000 करोड़ रुपये नहीं आया? आया था और जो लोन लिमिट की बात कर रहे हैं, आपको 4.5 प्रतिशत लोन की लिमिट थी फिर आपके पास 3.5 प्रतिशत लोन की लिमिट थी। हमने सरकारी कर्मचारियों/अधिकायों को ओ0पी0एस0 दी और यह हमारी पहली गारंटी थी। हमने कहा कि हम सरकारी कर्मचारियों को ओ0पी0एस0 देंगे। हमारे लोन की लिमिट को भी कैपिंग गर दिया गया और जो मल्टी लेट्रल

18.03.2025/1250/बी.एस./ए एस/-2

एसिस्टेंस के तहत जाइका और अन्य प्रोजैक्ट्स आते थे उनमें भी 29,000 करोड़ रुपये की कैपिंग कर दी। अगर में गलत हूं तो आप अभी उठ कर इस विषय पर बोल सकते है और अगर मैं सत्य पर आधारित बात कर रहा हूं तो इसे स्वीकार कीजिए। बाकी जो इनके प्वाइंट्स बजट से संबंधित हैं उन्हें में अपने विस्तृत उत्तर में बताऊंगा। पूर्व मुख्य मंत्री जी सब बातों को जानते हैं, कृपया ये भी सत्य पर बोलें।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, अपनी बात रखेंगे।

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, पिछले कल मैं देख रहा था, मुख्य मंत्री कहीं स्टेटमेंट दे रहे थे और यह कह रहे थे कि जितना बजट को मैंने पढ़ा, जितना बजट को मैंने समझा,

मैं कह सकता हूं कि आज तक के किसी मुख्य मंत्री ने बजट को न पढ़ा होगा और न समझा होगा। ज्ञान की अनुभूति होना अच्छी बात है।

मुख्य मंत्री : यह स्टेटमेंट मैंने कहां दी?

श्री जय राम ठाकुर : आपकी स्टेटमैंट सोशल मीडिया में चल रही है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। मेरे मोबाइल पर यह स्टेटमैंट है और मैं इसे आपको अभी भेज दूंगा। यह रिकार्डिड है, इसे हम आपको भी भेज देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे स्टेटमैंट नहीं भेजनी है, जो आप कह रहे हैं कि जितना बजट को मैंने पढ़ा, जितना बजट को मैंने समझा।...(व्यवधान)... यह जो सोशल मीडिया और आपके सलाहकार हैं उसमें आप फंस जाते हैं। इसे कोई सोशल मीडिया में चला रहा है या मेरी स्टेटमैंट है? आप जो कह रहे हैं, आप इस बात को यहां पर लाइए। कृपया, अभी इस वीडियो को यहां पर भेजिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अगर आप अनुमति देंगे तो मैं इसे यहां पर सुना दूंगा।

मुख्य मंत्री : आप सुना दीजिए। आप यह सुनाइए कि मैंने बोला है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

18.03.2025/1255/DT/AS-1

श्री जय राम ठाकुर : मैं व्यवस्था के अनुरूप चलूंगा। ...(व्यवधान) व्यवस्था के अनुरूप यहां पर सुनना ठीक नहीं होगा परंतु इसे मैं आपको दे दूंगा

Speaker : Let it be placed on the Table of the House and we will look into it.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कोई भी चीज Table of the House बाद में होती है, उसका कोई औचित्य नहीं रहता। ...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बार-बार मेरे भाषण को आब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ...(व्यवधान) अगर आप हमें नहीं बोलने देना चाहते तो हम नहीं बोलेंगे और हम चले जाएंगे। ...(व्यवधान)

मुख्य मंत्री : आपने यह बात गलत कही है इसलिए आप अपने शब्द वापिस लीजिए। ...(व्यवधान)

Speaker : Please ...(Interruption) Please take your seat. ...(Interruption) माननीय नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वह स्टेटमेंट हमारे पास है और मैं कह रहा हूं कि उस स्टेटमेंट को मैं आपको दे दूंगा। हम व्यवस्था के अनुरूप सदन का सम्मान करते हैं इसलिए उस स्टेटमें को यहां देना उचित नहीं होगा। मुख्य मंत्री जी की यह आदत ठीक नहीं है इसलिए इन्हें थोड़ा समझाइये। मुख्य मंत्री मुझे डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं लेकिन मैं होने वाला नहीं हूं। हमने 15वें वित्तायोग के समक्ष अपना पक्ष बड़े प्रभावी ढंग से रखा है और उन्होंने हमारे पक्ष को सुना है। वित्तायोग के लिए हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों के लिए अलग-अलग पैरामीटर्ज रखना संभव नहीं है। वित्तायोग हर राज्य का समान रूप से पक्ष रखता है। उसके अनुरूप पूरे देश के लिए फैसला लिया जाता है और पूरे देश के राज्यों के लिए जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टेपरड ऑन होनी है उसके मुताबिक फैसला हुआ है। हिमाचल प्रदेश को बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर श्रेणी में रखा गया है और इसके लिए हम धन्यवादी हैं। जो पार्लियामेंट ने वित्तायोग की सिफारिशें अडॉप्ट की और फिर हिमाचल

18.03.2025/1255/DT/AS-2

प्रदेश में लागू हुई तो उसमें हमारे प्रदेश को अच्छा पैसा मिला। आप जो फिगर कह रहे हैं उसमें मैं डिस्प्यूट नहीं करता हूं लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश

का पैसा रोक दिया गया? हमसे ज्यादा RDG का नुकसान हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को हुआ है। वह अपनी बात कहते रहे लेकिन फाइनेंस कमीशन की बात कोई बदल नहीं सकता। जब आपको पता था कि तीसरे साल RDG मात्र 3200 करोड़ रुपये रह जाएगी तो क्या ये गारंटियां देना जरूरी थी? क्या ये झूठी बातें करना जरूरी थी? अगर आप RDG के मुताबिक बात करते तो अच्छा होता। फिर आप बार-बार कह रहे हैं कि हमारी RDG रोक दी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वित्तायोग के सिस्टम से जो फैसला हुआ है उससे कई राज्यों की RDG रूकी है। वित्तायोग के सिस्टम से जो फैसला हुआ वह हिमाचल प्रदेश में भी लागू हुआ। आप इसका आरोप हमारे ऊपर और केंद्र सरकार पर नहीं लगा सकते। इसका फॉर्मूला सैट होता है। जब जी.एस.टी. कंपनसेशन का फैसला हुआ तो जी.एस.टी. काउंसिल की मीटिंग में उस वक्त हम वहां नहीं थे। उस वक्त आपकी सरकार थी जिसमें यह नीतिगत फैसला लिया गया कि जी.एस.टी. कंपनसेशन का पैसा 5 साल तक मिलेगा। वह पैसा जून, 2022 तक मिलना था। वह फैसला सभी राज्यों के लिए सबकी सहमति से लिया गया था। वहां पर सभी राज्यों के मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री मौजदू थे। जी.एस.टी. काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला हुआ कि हम जो प्रस्ताव पारित कर रहे हैं उसमें 5 साल तक जी.एस.टी. कंपनसेशन का पैसा मिलेगा उसके बाद यह पैसा नहीं मिलेगा। उसकी वजह यह थी कि जी.एस.टी. एक नया कंसैप्ट था।

श्री एन.जी. द्वारा जारी

18.03.2025/1300/डी.सी.-एन.जी./1

श्री जय राम ठाकुर ......जारी

और नए कंसेप्ट के अनुसार आपको वैट से जी0एस0टी0 पर जाना था। जिसके लिए आपको थोड़ी-सी अवधि के लिए कुछ कंपनसेशन दिया जाना था क्योंकि सारे सिस्टम को इन-ऑर्डर (लागू) करने के लिए और जी0एस0टी0 को एकत्रित करने के लिए आपको थोड़ा वक्त लगना था। इस व्यवस्था में छोटे-से-छोटे व बड़े-से-बड़े कारोबारी ने शामिल होना था जिसके लिए टाइम लगना ही था और इस व्यवस्था को बनाने के लिए केन्द्र

सरकार को ओर से प्रदेश को पांच वर्ष का समय दिया गया। ...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, इसमें हमारा भाग्य था कि हमारी सरकार का मेजर पार्ट जी0एस0टी0 कंपनसेशन प्राप्त करने में निकला और वह कंपनसेशन जून-2022 में मिलना बंद हो गया। इसके बाद आप (माननीय मुख्य मंत्री की ओर इशारा करते हुए) कैसे कह सकते हैं कि आप (स्वयं के लिए कहा) दोषी हैं या आपने गलत किया? जी0एस0टी0 काउंसिल का फैसला पूरे देश के लिए था और जब यह फैसला हुआ तब हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही थी। इस फैसले में कांग्रेस पार्टी के मुख्य मंत्री और कांग्रेस पार्टी के ही वित्त मंत्री हिस्सेदार थे।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, आपकी सरकार में तो धन्यवाद करने का कोई रिवाज ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व घाटा अनुदान के संदर्भ में बात करना चाहता हूं और इसके लिए थोड़ा-सा समय और चाहता हूं क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने भी मेरा बहुत सारा वक्त ज़ाया किया है।

अध्यक्ष : माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, आपको बोलते हुए 33 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरे समय में से 15-20 मिनट तो मुख्य मंत्री जी ने ले लिए हैं।

18.03.2025/1300/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, इनका (सत्तापक्ष की ओर इशारा करते हुए) टाइम अलग है और आपका (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) टाइम अलग है। दोनों पक्षों का टाइम अलग-अलग काउंट हो रहा है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व घाटा अनुदान के बारे में बात करना चाहता हूं। 13वें वित्तायोग के अंतर्गत राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2010-11 में 232 करोड़ रुपये, वर्ष 2011-12 में 2055 करोड़ रुपये, वर्ष 2012-13 में 3883 करोड़ रुपये, वर्ष 2013-14 में 1313 करोड़ रुपये और वर्ष 2014-15 में 405 करोड़ रुपये मिला था। इस प्रकार से 13वें वित्तायोग के तहत कुल 7889 करोड़ रुपये मिले थे। इसी प्रकार 14वें वित्तायोग के अंतर्गत राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2015-16 में 8009 करोड़ रुपये, वर्ष 2016-17 में 8232 करोड़ रुपये, वर्ष 2017-18 में 8311 करोड़ रुपये, वर्ष 2018-19 में 8206 करोड़ रुपये और वर्ष 2019-20 में 7866 करोड़ रुपये मिला था। इस प्रकार से 14वें वित्तायोग के तहत कुल 40624 करोड़ रुपये मिले थे। इसी प्रकार 15वें वित्तायोग के अंतर्गत राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2021-22 में 11249 करोड़ रुपये, वर्ष 2022-23 में 9377 करोड़ रुपये, वर्ष 2023-24 में 8058 करोड़ रुपये, वर्ष 2024-25 में 6058 करोड़ रुपये मिले हैं और वर्ष 2025-26 में 3057 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से 15वें वित्तायोग के तहत कुल 37799 करोड़ रुपये मिलेंगे। ...(व्यवधान) हम ठीक बोलते हैं। ठीक आदमी, ठीक ही बोलता है और जो गलत होता है, वह गलत ही बोलता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं share in central taxes के बारे में बताना चाहता हूं और यह लगातार इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि जी0एस0टी0 की कलैक्शन हर बार बेहतर हो रही है। जब से यह स्वभाविक रूप से लागू हुआ है और इसका इफैक्टिव पार्ट अब आना शुरू हुआ है। मैं share in central taxes के संदर्भ में बताना चाहता हूं कि वर्ष 2018-19 में 5430 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 4678 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 4754 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 में 7349 करोड़ रुपये मिले थे।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

18.03.2025/1305/DC/PB/-1

श्री जय राम ठाकुर जारी...

इसके बाद, वर्ष 2022-23 में 7,784 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में सेंट्रल टैक्स का 9,390 करोड़ रुपये मिला था। वर्ष 2024-25 में राज्य को 10,680 करोड़ रुपये मिले और आगामी वर्ष 2025-26 में यह 11,806 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। यह हमारी

है...(व्यवधान) आप (मुख्य मंत्री जी की ओर देखते हुए।) इसमें क्या करैक्ट करेंगे मैं करैक्ट ही बोल रहा हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि टैक्स कलेक्शन प्रभावी रहा है और केंद्र सरकार से मिलने वाला हिस्सा भी लगातार बढ़ रहा है। चिंता का विषय यह है कि पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) में लगातार कटौती की जा रही है। वर्ष 2017-18 में पूंजीगत व्यय 3,756 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2018-19 में बढ़कर 4,583 करोड़ रुपये हुआ। वर्ष 2020-21 में यह 5,399 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 में 6,029 करोड़ रुपये तक पहुंचा। वर्ष 2022-23 में भी यह 6,029 करोड़ रुपये रहा, लेकिन वर्ष 2023-24 में यह घटकर 5,630 करोड़ रुपये रह गया। अध्यक्ष महोदय, सबसे चिंताजनक स्थिति वर्ष 2024-25 में आई, जब संशोधित बजट और पूरक बजट को मिलाकर केवल 8,666 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किया गया। वर्ष 2025-26 में इसे और घटाकर 3,941 करोड़ रुपये कर दिया गया है। हालांकि, वास्तविकता यह है कि यह आंकड़ा अगले वर्ष 5,000 करोड़ रुपये से पार हो सकता है, क्योंकि आगामी वर्षों में पूंजीगत व्यय के अन्य स्त्रोतों को भी ध्यान में रखना होगा। मैं गणित का विद्यार्थी नहीं था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा-थोड़ा हिसाब लगाना शुरू किया है और हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर काम किया है। अपको जो असली बात है वह सदन में बतानी चाहिए उसे आप छुपाते हैं। राज्य सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि उसे केंद्र सरकार से भारी वित्तीय सहायता मिली है। विशेष केंद्रीय सहायता (स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस) के तहत पिछले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश को लगभग 1,900 करोड़ रुपये मिले। वर्ष 2023-24 में यह सहायता 1,515 करोड़ रुपये थी, जबकि वर्ष 2024-25 में इसे घटाकर 1,357 करोड़ रुपये कर दिया गया। वर्ष 2025-26 में भी इसका एक हिस्सा, 457 करोड़ रुपये राज्य को मिल चुका है। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण जैसी योजनाओं की घोषणा तो करती है, लेकिन यहां पर केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता का जिक्र तक नहीं करती। वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने विशेष केंद्रीयसहायता के रूप में 457 करोड़ रुपये दिए, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

18.03.2025/1310/AS/AP-1

श्री जय राम ठाकुर जारी....

हम इतना पैसा खर्चेंगे, उसके अगेंस्ट आपको केंद्र की और से 457 करोड़ रुपए की स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस मिली है। मुख्य मंत्री जी आपने एक बार भी केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद नहीं किया। आपके तीन साल के कार्यकाल में 3329 करोड़ रुपये का स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस भेजा गया है। जिसके अनुसार आपको 50 सालों में बिना ब्याज के वह ऋण वापिस करना है। मुझे इस बात को लेकर जरूर कहना है कि इस पैसे का दुरूपयोग हो रहा है। इन पैसों में तय हो रहा है कि स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स सिर्फ आपके विधायकों के बनाए जा रहे हैं और आपने विपक्ष के विधायकों को इस लिस्ट से निकाल दिया है। आपको केन्द्र से 3.50 हज़ार करोड़ रुपये मिल भी गये हैं, इसके बावजूद आपने विपक्ष के विधान सभा क्षेत्र में, एक पुल के निर्माण, पानी की स्कीम आदि के लिए इन पैसों का उपयोग नहीं किया। यह सारे का सारा पैसा कांग्रेस पार्टी के विधायकों के प्रोजैक्ट्स को सैंक्शन करने में इस्तेमाल किया गया है। आप यहां पर वाहवाही लूट रहे है कि आप एयरपोर्ट का एक्सपेंशन कर रहे हैं, आपने उसके लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। ठीक है वह आपने शुरू किया होगा। लेकिन पैसा कहां से आ रहा है? पैसा केंद्र सरकार दे रही है। इस बात को भी आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात ... (व्यवधान) बार-बार यह संभव नहीं है। अगर ऐसा ही होगा तो मैं अपनी बात छोड़कर सदन से बाहर निकल जाउंगा। यह संभव नहीं है। यह हकीकत है कि जो सच्चाई है वह आप स्वीकार नहीं करना चाहते है। अध्यक्ष महोदय, चिन्ता हमारे लिए इस बात की है ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष जी आप कृपा बोलें।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो अधिकारी यहां पर बैठे हैं, ये घुमाते रहते हैं। नेताओं को भी, सरकारों को भी और बजट के सारे आंकड़ों को भी, यही अधिकारी घूमाते रहते हैं। इस दौर में से हम कई लोग निपट आये हैं, आप भी बहुत जल्द निपट जायेंगे। यह

हकीकत है कि कई बड़े-बड़े नेता निपट गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा एस.सी.ए. का पैसा जो केंद्र से आया इसका बहुत बड़ा

18.03.2025/1315/AS/AP-2

कम्पोनेंट, जो प्रोजेक्ट्स स्पैसीफिक होने चाहिए, जहां काम होना चाहिए वहां काम न करके आप इस पैसे को पैंशन व सेलरी देने में लगा रहे हैं। आज आप कर्मचारियों को जो सैलरी व पेंशन दे रहे हैं उसकी वजह यह पैसा है। आपने उस पैसे को इस तरह से घुमाया है। क्या यह सत्य नहीं है? लगभग 300 करोड़ रुपये से ज्यादा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया गया, फिर उसके बाद उस पैसे को आगे बढ़ाकर Infrastructure Development Board को दिया गया, फिर उसके बाद किश्तों में निकालकर कर्मचारियों की सैलरी दी गई है। लेकिन यह सच्चाई है कि यह पैसा सैलरी व पेंशन में खर्च नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो पैसा दिया गया है, उस पैसे को सैलरी व पेंशन में खर्च कर रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद में आगे बढ़कर बात कहूं कि क्या यह सचाई नहीं है? आपके बटज अभिभाषण में कहा गया कि हम इतने किलोमीटर सड़क बनाएंगे और उसके ऊपर इतना पैसा खर्च करेंगे। मैं उस सारी डिटेल में जाना चाहूंगा तो वक्त थोड़ा और लगेगा। अध्यक्ष महोदय, हकीकत यह है कि अगर हम सच्चाई को देंखे तो वह सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश में आज अगर विकास के कार्य हो रहे हैं तो उसकी एक मात्र वजह केंद्र सरकार की सेंटर स्पोंसर्ड स्कीमस का है। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग मदों में जो मदद मिल रही है, जो प्रोजेक्ट्स केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत किये गये हैं, उन पैसों से हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य हो रहे हैं। उसके सिवाय प्रदेश सरकार के पास प्रदेश के विकास के लिए पैसा ही नहीं है। आपकी सरकार ने कहा कि हम सड़कों पर इतना पैसा खर्च करेंगे और इतने किलोमीटर सड़क बनायेंगे। लेकिन लोक निर्माण विभाग के पास कितना बजट है? आप प्रदेश की ओर से कौन-सा पैसा लगा रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, पैसा वह है, अगर सड़कों का निर्माण होगा तो सी.आर.एफ. के माध्यम से होगा जो कि केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया पैसा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अतंर्गत केंद्र

सरकार की ओर से पैसा दिया गया है, उस पैसों से सड़कें बनेगी। नाबार्ड का पैसा जो केंद्र सरकार ने लोन के रूप में दिया है उस पैसों से सड़कें बनेगी। वर्ल्ड बैंक का पैसा है, उस पैसों से सड़कें बनेगीं।

श्री ए.टी. द्वारा जारी...

18.03.2025/1315/HK/AT/1

श्री जय राम ठाकुर जारी :

और जितना भी टूरिज्म का ए0डी0बी0 का प्रोजेक्ट है, यहां कहा कि 2400 करोड़ रुपये हिमाचल प्रदेश पर पर्यटन के क्षेत्र में नई टूरिज्म डेस्टिनेशन डवलप करने के लिए खर्च करेंगे। हम यहां कन्वेंशन सैंटर बनाएंगे, वहां कन्वेंशन सैंटर बनाएंगे लेकिन हकीकत क्या है? प्रदेश सरकार का कितना बजट टूरिज्म के लिए है? एक तरह का शून्य ही है। 2400 करोड़ रूपये जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री जी से मिलकर और फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर लाए थे ए0डी0बी0 प्रोजेक्ट लाए क्योंकि केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान पूरे देश के ए0डी0बी0 के प्रोजेक्ट सैल्फ कर दिए थे। केंद्र ने कहा कि किसी भी राज्य को नहीं मिलेगा लेकिन हमने कहा कि हमें चाहिए । हमने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी आवश्यकता है। मैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिला तब जाकर एकमात्र ए0डी0बी0 का प्रोजेक्ट कोविड के बाद सेंक्शन हुआ तो हिमाचल प्रदेश को हुआ और 2400 करोड़ रुपये लाए, यह हकीकत है और इस बात को आपको कहने के लिए क्या एतराज होता है कि हम टूरिज्म के क्षेत्र में 2400 करोड़ रूपये खर्च करेंगे? लेकिन साथ में यह भी कहते कि केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ए0डी0बी0 का यह प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, उसके अंतर्गत ये पैसा खर्च करेंगे। आज हिमाचल प्रदेश में कोई भी सेक्टर वह चाहे हैल्थ या ऐजुकेशन का सेक्टर है, जो आपकी स्टेट की व्यवस्था है, उसके अनुसार आप कहां विकास कर पाएंगे क्योंकि पैसा आपके पास नहीं है। इस बात को सोचने की आवश्यकता है ....(व्यवधान) नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अध्यक्ष जी, जब बजट का यह डॉक्यूमेंट बनाया गया, मैं उम्मीद करता था कि ये नेता लोग तो ऐसे ही करेंगे लेकिन अधिकारियों से मैं उम्मीद करता था कि वे उसमें जिक्र करेंगे कि ए0डी0बी0 का पैसा है,

सी0आर0एफ0 का पैसा है, पी0एम0जी0एस0वाई0 का इतना पैसा है, वर्ल्ड बैंक का इतना पैसा है, सेंट्रल असिस्टेंस का इतना पैसा है और सेंट्रल के प्रोजेक्ट के तहत इतना पैसा है, उनका जिक्र करते तो हकीकत सामने आती लेकिन सारी चीजों को दफन कर दिया गया और हकीकत को छिपाना और हकीकत को नहीं बताना अपराध है। सरेआम उसको दफन कर देना, बदल देना और केंद्र की सारी योजनाओं का श्रेय प्रदेश सरकार ले रही है। सड़कें बनेगी तो यह, पुल बनेंगे तो यह, पानी की सकीमें बनेंगी तो यह पैसा सेंटर गवर्नमेंट का। मैं यह कह रहा हूं .....(व्यवधान) हकीकत है, पाकिस्तान नहीं है लेकिन हम यह कह रहे हैं कि इतना तो कम से कम आपको धर्म रखना चाहिए कि आप थोड़ा तो बोलते कि

18.03.2025/1315/HK/AT/2

18.03.2025/1315/HK/AT/2

केंद्र सरकार की ओर से यह पैसा दिया गया है और उस पैसे के अनरूप जो है......(व्यवधान)

Speaker : Let him complete please.

श्री जयराम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर पढ़ लेता हूं किः-

टूटा हुआ लश्कर का भ्रम देख रहे हैं और मुख्यमंत्री जी हम आपके कर्म देख रहे हैं।
ताकत का नशा अकल पर भारी है तुम्हारी, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं ।

सत्ता एक तरह की ताकत ही होती है इसलिए रहम करो, इस प्रदेश पर रहम करो।.....(व्यवधान)

अध्यक्षः 50 मिनट हो गए ।

श्री जयराम ठाकुर : आपने वर्ष 2023-24 में जो कमिटमेंट्स की थीं, जो पिछले बजट की आपकी घोषणा है, मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, प्रोग्रेस शून्य। मेधावी छात्राओं के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी सब्सिडीद्व प्रोग्रेस शून्य, जमीन पर ही नहीं उतरी, शुरू ही नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान, प्रोग्रेस शून्य यानी उसमें कोई काम नहीं हुआ, उसमें तो अभी चरण भी शुरू नहीं हुआ। बागवानी उत्कृष्ट केंद्र, प्रोग्रेस शून्य कोई काम उस पर नहीं हुआ और उसके बाद कुफरी के पास हसन घाटी में स्काई ब्रिज बनाएंगे। अरे, यह भी आपने पूरा नहीं किया।

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारीः

18.03.2025/1320/MD/YK/1

श्री जय राम ठाकुर----जारीः

उस अभियान में तो अभी चरण भी शुरू नहीं हुआ है। बागवानी उत्कृष्ट केंद्र की प्रगति शून्य है, वहां कोई काम नहीं हुआ। इसके बाद कुफरी के पास हसन घाटी में स्काई ब्रिज बनाने की योजना है, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश में परिवर्तन प्रकोष्ठ, परिवर्तन प्रकाश, एच0पी0 टच के सतत विकास के लक्ष्य का समन्वय केंद्र भी पूरी तरह शून्य विकास पर है।

अध्यक्ष महोदय, अगर मैं कहूं कि पिछले बजट की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, तो अब इस बजट में जो बातें कही गई हैं, वे कब पूरी होंगी? समय बहुत तेजी से निकलता जा रहा है और यह दौर भी बहुत जल्दी समाप्त होने की दिशा में बढ़ रहा है। चरणबद्ध तरीके से कार्य आगे नहीं बढ़ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम के तहत हमारे जो सेंटर्स पहुंचे हैं, वह इस वर्ष 2025-26 के लिए 5.62 करोड़ रुपये की राशि प्रोवाइड करेगी। इस पर भी अगर सरकार धन्यवाद देती तो यह उचित होता। साथ ही, सरकार बार-बार यह कहती है कि हमारे रेवेन्यू में बहुत बड़ा इंक्रीज हुआ है। मैं इस पर जरूर कहना चाहता हूं कि अगर एक्सेस कलेक्शन की बात करें, तो वर्ष 2023-24 में यह

2,692 करोड़ रुपये था और वर्ष 2024-25 में यह बढ़कर 2,884 करोड़ रुपये हुआ, जो केवल लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2025-26 में इसका अनुमानित आंकड़ा 3,250 करोड़ रुपये है, जो लगभग 70 प्रतिशत इंक्रीज दर्शाता है। जबकि हमारे समय में, कोविड के दो वर्षों को छोड़कर, सतत वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022-23 की वृद्धि भी 20 प्रतिशत से ऊपर रही थी। इसलिए अगर सरकार आंकड़ों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है, तो यह उचित नहीं है। इस बजट में स्पष्ट दिशा की कमी दिख रही है। भ्रष्टाचार की घटनाएं प्रदेश की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। पानी की सप्लाई स्कूटर से होने जैसी घटनाएं घोटाले की ओर इशारा कर रही हैं। डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक की सामग्री बिना ट्रेस के गायब हो गई। 118 को लेकर वायरल ऑडियो में कई नेताओं और अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। इसी तरह, बिजली, पानी और पी0डब्ल्यू0डी0 के टेंडरों में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। यदि इन मामलों की विस्तार से चर्चा की जाए, तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा।

18.03.2025/1320/MD/YK/2

अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा होगा और वर्ष 2032 में पूरे देश में सबसे समृद्धशाली होगा। लेकिन ये चरण आपके आगे बढ़ नहीं रहे हैं। मुझे बड़ा दिलचस्प लगता है और बड़ी हैरानी भी होती है कि पता नहीं कौन-सी आपके पास जादू की छड़ी है जिससे ऐसा होगा। वैसे तो आपने बड़ा जोरदार तरीका निकाल दिया है और कुछ अधिकारियों ने चिट्ठियां निकाल दी हैं कि जादूगर का शो दिखाया जाएगा और उससे रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

18.03.2025/1325/केएस/वाईके/1

श्री जय राम ठाकुर जारी---

जिसका कलैक्शन का 50 परसेंट प्रदेश सरकार को दिया जाएगा। आप भी यही गिली,गिली,गिली कर रहे हैं और वर्ष 2027 तक, आपके पास कौन सा जादू है? आपका बजट तबाह हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में आपके कार्यकाल में विकास को ताला लग गया है उसके बावजूद आप गिली-गिली करके कह रहे हैं कि वर्ष 2027 में हिमाचल प्रदेश समृद्ध राज्य बन जाएगा। उसका कोई आधार तो हो। अध्यक्ष महोदय, उसका कोई आधार नहीं मिल रहा है। इसलिए यह बहुत ही चिंता का विषय है। हिमाचल कहां जाएगा, कहां पहुंचेगा, यह हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रदेश के बारे में सोचा जाए। यह सबका प्रदेश है, सिर्फ एक दल, एक विचार या एक पार्टी का ही प्रदेश नहीं है। इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हमें कुछ बातों से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। आपको उचित लगा तो आपने संस्थान बंद कर दिए और हमें यह लगा कि आर्थिक रूप से आप इससे कुछ खर्चा बचाएंगे लेकिन उससे ज्यादा खर्चा तो आप फालतू की चीज़ों पर कर रहे हैं। आपकी गाड़ी 365 दिन चलती है लेकिन जिस दिन बजट आता है तो मुख्य मंत्री साहब ऑल्टो में आते हैं और साथ में भाभी जी को भी नहीं लाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह सच्चाई बता रहा हूं कि इस तरह से ड्रामा करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। सुक्खू जी से आप सुखविन्दर सिंह सुक्खू तब बनेंगे जब हिमाचल प्रदेश को आप हकीकत में पहचान पाएंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आप ठोस कदम उठाएंगे। अनावश्यक रूप से टैक्सिज़ लगाकर आपने मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी लेकिन उसके बावजूद हिमाचल की आर्थिकी सुधर नहीं पा रही है। आपने सी0पी0एस0 पर खर्चे लगाए। पायलट आगे, एस्कोर्ट पीछे लगाकर जो करोड़ों रुपये आपने खर्च किए क्या उस वक्त आपको चिंता नहीं हुई और आज बजट के दिन आप खुद ऑल्टो गाड़ी में आ रहे हैं? हमें तो कहते थे कि हैलीकॉप्टर में जाते हैं लेकिन क्या आप हैलीकॉप्टर के बिना जाते हैं? हैलीकॉप्टर प्रदेश का है, उसका उपयोग होना चाहिए,हम यह कहते हैं लेकिन मेरे बारे में बार-बार यही प्रचार किया जाता था जैसे कि मैंने हैलीकॉप्टर खरीद ही लिया था।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

18.03.2025/1325/केएस/वाईके/2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता का भी उस समय यही राग होता था कि हैलीकॉप्टर में जाते हैं। क्या हैलीकॉप्टर चलना नहीं चाहिए? अगर ले कर रखा है तो प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के काम के लिए उसका इस्तेमाल होना चाहिए। अगर ले ही रखा है तो कभी-कभी आप लोग भी उसमें झूटा मार दिया करो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता की दो लाइनें जरूर कहना चाहता हूं किः

आप पड़ाव को न समझें मंजिल,
लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल,
वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं।

यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और अध्यक्ष महोदय, इस बजट में जो सारी बातें की हैं, वे सत्य पर आधारित नहीं हैं। बजट में उसके लिए प्रावधान नहीं है। आपके पहले बजट की घोषणाएं अभी तक जमीन पर नहीं उतरीं हैं, रोबोटिक सर्जरी का हम इंतज़ार कर रहे हैं, PET स्कैन आपने लगाना था, हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ढूंढ रहे हैं कि हमारे यहां पर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कहां पर खुला है, वह अभी तक हमको मिल नहीं पाया है। आपके हिसाब से आपने वहां पर रेडियोलॉजिस्ट भी लगा दिया, एम0आर0आई0 की मशीन भी लगा दी है, सब कुछ लगा दिया लेकिन कम से कम सत्य बोलना चाहिए। चुनाव से पहले आपने गारंटियां दीं, प्रदेश भी जान गया है कि वे झूठी थीं। उसके बाद जब बजट प्रस्तुत किया जाता है तो सच्चाई बोली चाहिए, जो हकीकत है, उसको बोलना चाहिए। आपने 23 लाख महिलाओं को वायदा किया था लेकिन आप 23 हजार महिलाओं को सुविधा दे कर छुटकारा पा रहे हैं और अब 21 साल के ऊपर कह रहे हैं , उसमें भी चरणबद्ध तरीके से। ये चरण आने वाले समय में आपके बहुत महंगे पड़ेंगे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.03.2025/1330/av/AG/1

श्री जय राम ठाकुर------- जारी

मैं आपकी पार्टी और सरकार को यही कहूंगा कि इस बजट में समर्थन करने लायक कोई चीज नहीं है। यह बजट किसी भी वर्ग के हित में नहीं है इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी, आप बोलिए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कुछ बातें माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी खा गए। मैं मानता हूं कि विपक्ष के नेता का इस प्रकार का स्वभाव होता है क्योंकि विपक्ष के नेता चर्चा करते हुए कुछ बातों को छिपाना चाहते हैं। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। यहां पर नेता प्रतिपक्ष जी ने जो एस0सी0ए0 की बात की है कि सरकारी कर्मचारी वेतन या पेंशन में चले गए, तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे दो भाग हैं। मेरा एक भाग मुख्य मंत्री के तौर पर है तथा दूसरा वित्त मंत्री के तौर पर है। मेरे छात्र जीवन से लेकर कुछ साथी उस तरफ बैठे हैं और कुछ इस तरफ भी बैठे हैं जोकि मेरी कार्य प्रणाली को भलीभान्ति जानते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैं अपने छात्र जीवन में, पी0सी0सी0 अध्यक्ष और मुख्य मंत्री बनने से पहले हिमाचल प्रदेश के हर कोने में गया हूं। हम जब कहीं जाते हैं तो वहां से भाव एकत्रित करके उनको अपने बजट में सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि जी0एस0टी0 बढ़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी स्टेट तो बहुत छोटी-सी है। हमारे यहां तो केवल 75 लाख के करीब जनसंख्या है। हम अगर हिमाचल प्रदेश में जी0एस0टी0 के लिए रिवेट भी दे दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जी0एस0टी0 तो कंज्यूमर स्टेट में लगता है। अगर कोई बद्दी की पैरासिटामोल यू0पी0 में खरीदेगा तो जी0एस0टी0 उसको मिलेगा। यहां जी0एस0टी0 तो आपके समय से लागू है। परंतु जी0एस0टी0 की चोरी जो आपके समय में होती थी हमने उसको रोका है और इंक्रीज किया है। ...(व्यवधान) आपको जी0एस0टी0 कंपनसेशन सैस मिलता रहा। ...(व्यवधान) माननीय श्री जय राम ठाकुर जी सोशल मीडिया पर ज्यादा विश्वास करते हैं। वैसे तो अधिकारी सरकार के होते हैं। परंतु इनको जिन अधिकारियों ने भी तथ्य उपलब्ध करवाए हैं तो मैं मानता हूं कि उन्होंने इनके

साथ इनकी सरकार के कार्यकाल में भी काम किया है और यह उनका दायित्व भी बनता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर

18.03.2025/1330/av/AG/2

बन जाएगा और वर्ष 2032 में हिमाचल प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे समृद्धशाली प्रदेश होगा। इन्होंने एक व्यक्तिगत टिप्पणी की कि ऑल्टो में एक दिन ही आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ...(व्यवधान) बिल्कुल सही है, मैं एक ही दिन आता हूं और बल्कि उसमें वापिस भी नहीं जाता। ...(व्यवधान) मैं उसके बारे में बता रहा हूं। मैं बजट वाले दिन आता हूं और वह इसलिए आता हूं क्योंकि मैं आम आदमी का दर्द जानता हूं। हम आम आदमी का दर्द सीने में छिपाकर याद रखते हैं। आज जो बजट आया है वह आम आदमी से संबंधित है। ...(व्यवधान) कई बार समय की पाबंदी का भी ध्यान रखना पड़ता है। आम आदमी का दर्द सीने में होता है तथा सीने व दिमाग में योजनाएं होती हैं। उन योजनाओं को लेकर हम आगे का बजट प्रस्तुत करते हैं और इसी को व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। हमने जो बजट लाया है वह सम्पदा का वह भाग है जो वंचित वर्गों को मिलना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश हेतु 02.35 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है। We will reassemble at 02.35 PM.

18.03.2025/1440/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.40 बज़े अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी भाग लेंगे।

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने सरकार का तीसरा बजट प्रस्तुत किया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आपने बजट में कम-से-कम 10 बार पालमपुर का नाम लिया है। ...(व्यवधान) मुझे जनता ने काम करने के लिए भेजा है, मंत्री बनने के लिए नहीं। मेरा जितना ज्यादा काम हो जाए, उतना ही अच्छा है। अध्यक्ष जी, हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और जब यह अस्तित्व में आया था, तभी यह स्पष्ट हो गया था कि हमारे आय के साधन बहुत कमजोर होंगे। उस समय हमारे पास मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं थीं। जैसे-जैसे सरकारें आईं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया।

अध्यक्ष महोदय, चाहे डॉ0 वाई0एस0 परमार जी, ठाकुर रामलाल जी, शांता कुमार जी, श्री वीरभद्र सिंह जी या प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी मुख्य मंत्री रहे, इन सभी ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि जहां-जहां भी सुविधाएं गांवों तक नहीं पहुंच पाई थीं, वहां उन्हें उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। इस दिशा में केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिलता रहा। लेकिन बाद में पता नहीं क्या हुआ कि केंद्र सरकार सहयोग देने से घबराने लगी। अगर आप में से किसी ने कुछ कहा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार वर्ष 2022 में बनी। हमने प्रयास किया कि जो आर्थिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, उसे किस तरह से ठीक किया जाए और विकास को गति दी जाए। हमारी सरकार मुख्य मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में *व्यवस्था परिवर्तन* के नारे के साथ आई और यह इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि वर्ष 2017 से 2022 तक रही बी0जे0पी0 सरकार, जिसका नेतृत्व उस समय वर्तमान नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे, उन्होंने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया था। मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे और जंगल में पिकनिक मनाने जाते थे, तो वहां चिप्स-बिस्किट खाकर कचरा फैला देते थे। ठीक

18.03.2025/1440/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

उसी तरह पिछली सरकार ने भी राज्य की अर्थव्यवस्था में कचरा फैला दिया और आज हमारी सरकार उसे साफ करने का प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, इस बार मुख्य मंत्री जी का बजट अभिभाषण तीन घंटे का था, जिसमें शेरो-शायरी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास कहने को बहुत कुछ था। जबकि आज नेता प्रतिपक्ष का भाषण मात्र आधे घंटे का रहा, जिसमें काफी शेरो-शायरी थी, क्योंकि उनके पास कहने को कुछ खास नहीं था। ...(व्यवधान) वे जब आएंगे, मैं उनके सामने भी यह बात जरूर रखूंगा। अध्यक्ष महोदय,

एन0एस0 द्वारा जारी ...

18-03-2025/1445/NS-AS/1

श्री आशीष बुटेल -----जारी

मैं आप सबको एक विषय से अवगत करवाना चाहता हूं कि वर्ष 2017-22 में इनकी सरकार थी, प्लानिंग डिपार्टमैंट इनके पास था और उस समय वर्ष 2021-22 का आर्थिक सर्वे आया। जिसके अंदर यह कहा गया कि 87 प्रतिशत रेवेन्यू रिसिप्ट्स का जो हिस्सा होगा वह हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर पर खर्च किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह जानना चाहता हूं कि ये उस समय कोई ऐसे कदम क्यों नहीं उठा पाए? उस समय यह भी बात हुई कि वर्ष 2025-26 में हमारी जो इनकम 87 प्रतिशत होगी यानी जो रेवेन्यू इनकम होगी वह एक्सपेंडिचर के रूप में दर्शाइ गई और उसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए। आप लोगों को तो जी0एस0टी0 कंपनसेशन भरपूर मिला। उस समय 16,000 करोड़ रुपए का जी0एस0टी0 कंपनसेशन आया। कोई कदम नहीं उठाए गए। आज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट टेपर करके बिल्कुल कम हो गई है। आपको तो 11,000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली।

अध्यक्ष महोदय, आज बहुत हंसी आई जब माननीय नेता प्रतिपक्ष यह कह रहे थे कि आप लोगों ने लोन लिया। लोन कौन सी सरकार नहीं लेती? आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि जो लोन हम यहां पर आज ले रहे हैं उससे 70 प्रतिशत इनके टाइम का लोन हम वापस कर रहे हैं। यह यहां पर बजट डॉक्यूमैंट में लिखा हुआ है। हमारे पास जब वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार की ग्रांट लगभग14,000 करोड़ रुपए आई और आज वर्ष 2025-26 में कम हो गई है। उसमें भी 30 प्रतिशत का कट लगा दिया गया है। आपके

समय पर आई आपदा तो आपदा होती थी। कोविड के समय आपदा आई तो आप कहते थे कि आपदा आई और हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाई है और जो भी कर सकी वह हमने किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे समय पर आपदाएं नहीं आईं? हमारे समय पर तो ऐसी आपदा आई जो पूरे देश में नहीं थी और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर थी। आप इसे राष्ट्रीय आपदा कहो या न कहो लेकिन हम तो उसको राष्ट्रीय आपदा ही मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि केंद्र सरकार से बिल्कुल भी मदद नहीं हुई। अगर आज विपक्ष अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल के यह कहे कि कोविड की वजह से काम नहीं हो पाया और उस समय हमें बहुत बुरी हालत से गुजरना पड़ा तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने कोविड के दौरान आपकी

18-03-2025/1445/NS-AS/2

मदद भी नहीं की? अगर आप कहते हैं कि कोविड में यह मदद उनकी हुई है तो आज केंद्र सरकार को क्या तकलीफ है कि हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई तो उसकी भरपाई नहीं की जा रही है?

अध्यक्ष महोदय, आज हमारी राष्ट्रीय जी0डी0पी0 तकरीबन 10 प्रतिशत पर ग्रो कर रही है और हिमाचल प्रदेश की भी 10 प्रतिशत पर ग्रो कर रही है। मैं विपक्ष से यह पूछना चाहूंगा कि यहां पर दो सेट ऑफ रूल्स तो नहीं हो सकते। आप अगर निंदा करना चाहते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार की निंदा करना चाहते हैं कि 10 प्रतिशत जी0डी0पी0 की बढ़ोतरी हुई है तो क्या आप यहां पर केंद्र सरकार की भी निंदा करेंगे जिनकी भी बढ़ोतरी सिर्फ 10 प्रतिशत की हुई है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आज हम रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमें 6,486 करोड़ रुपए यानी 2.8 प्रतिशत रेवेन्यू डेफिसिट हुआ। आज हमने उसको कम करके 6,390 करोड़ रुपए यानी 100 करोड़ रुपए का घाटा और कम किया है। क्या उससे आप लोग खुश नहीं हैं? अभी आदरणीय जय राम जी कह रहे थे कि बहुत बदनामी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि बदनामी कोई नहीं कर रहा है। बदनामी आप लोग कर रहे हैं जिनको पूरी तरह से यह

जानकारी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में क्या विकास हो रहा है और हम किस तरह से व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, यहां पर कहा जा रहा है कि कर्मचारियों के बारे में नहीं सोचा। उनके एरियर नहीं दिए गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हमारा तो वह समय है जब जी0एस0टी0 की कंपनसेशन कुछ नहीं मिलती, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 11,000 करोड़ रुपए से कम होकर 3,000 करोड़ रुपए के लगभग आ गई है। उसके बावजूद आज हमने कमिट किया है कि हम इम्पलॉयज को चरणबद्ध तरीके से एरियर देंगे। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनकी सरकार के समय में क्या हुआ? आपने लोन क्यों लिया, आज आप यह जनता को जरूर बताएं क्योंकि सबसे जरूरी यह होता है कि जो

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.03.2025/1450/RKS/डीसी-1

श्री आशीष बुटेल जारी....

एक घर के मुखिया का फर्ज होता है कि वह अपनी आमदनी में से कुछ सेविंग भी करे। वह अपनी आमदन से अपने परिवार व बच्चों पर पैसा खर्च करें लेकिन उसे इसके साथ-साथ सेविंग भी जरूर करनी चाहिए। वर्ष 2017 से वर्ष 2022 के बीच आपको इतना खुला पैसा मिलने के बावजूद भी आपने बहुत ज्यादा ऋण लिये जोकि हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ एक विश्वासघात है इसलिए आप आज उस तरफ बैठे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नदी सूखाकर गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जी यह बात आपके ऊपर सही बैठती है क्योंकि आप हमें बिल्कुल सूखी हुई नदी छोड़कर गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस नदी में कहां से पानी लेकर आएं और इस पर हमारी सरकार पूरे जोर से कार्य कर रही है। आप कह रहे हैं कि बजट का साइज इंक्रीज नहीं हुआ। जब जी0एस0टी0 और आर0डी0जी0 की ग्रांट कम होती जा रही है तो बजट का साइज कैसे इंक्रीज होगा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि बजट का साइज बढ़ा नहीं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप लोन मत लीजिए। ये

दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मुख्य मंत्री जी ने बजट के पैराग्राफ-9 में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2025-26 का वित्तीय वर्ष will be the most challenging year in the history of Himachal Pradesh. But he has taken it up as a challenge and we will make sure that we sail through this problem very soon. आपने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर केंद्र सरकार का धन्यवाद नहीं किया। मैं कहता हूं कि इन्होंने भारत सरकार का धन्यवाद किया है। केंद्र सरकार ने जो असैसमेंट के लिए PDNA की टीम भेजी थी उसके लिए मुख्य मंत्री जी ने धन्यवाद किया है लेकिन असली धन्यवाद तब होगा जब वह पैसा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। अभी तक हमें वह पैसा नहीं मिला है। वर्ष 2024-25 में हमारी fiscal deficit की दर 6.6 प्रतिशत थी। आज हमें इसे पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत पर लाने जा रहे हैं यानी 2.6 प्रतिशत कम करने जा रहे हैं तो उसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने वर्ष 2023-24 में 7896 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 में रिवाइज्ड एस्टीमेट के अनुसार 15,616 करोड़ रुपये की debt repayment की है। यह श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू की सरकार है जो इसे लोन और बोरोइंग से कम कर रही है। हमने यह भी कहा है कि वर्ष 2023-24 में 14,900 करोड़ रुपये का लोन लिया था लेकिन वर्ष 2025-26 में हम 13,375

18.03.2025/1450/RKS/डीसी-2

करोड़ रुपये का अनुमानित लोन लेंगे जोकि 1600 करोड़ रुपये कम होगा जोकि एक अच्छी पहल है। आपने कमिटिड एक्सपेंडिचर की बात की। वर्ष 2021-22 का जो इक्नोमिक सर्वे था उसमें बहुत क्लीयरली डिफाइन था कि वर्ष 2025-26 में जो रेवेन्यू रिसिट्स होगी उसका 87 प्रतिशत कमिटिड लाइबलिटीज में जाएगा। मुझे आज इस सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि आपने जो उस समय लाइबलिटिज के लिए 87 प्रतिशत राशि शो की थी उसमें आज हम 81 और 83 प्रतिशत पर हैं। हिमाचल प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है लेकिन आपने इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की है। हमारा शेयर इन सेंट्रल टैक्सिज अगले वर्ष और बढ़ेगा लेकिन यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से नहीं बढ़ेगा अपितु उस शेयर में हिमालच प्रदेश के शेयर की 11 प्रतिशत वृद्धि होगाी। हिमाचल प्रदेश का own

tax revenue 19 प्रतिशत बढ़ने वाला है। अगर हम जी0एस0डी0पी0 की परसेंटेज देखें तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल 6.3 प्रतिशत पर पहुंचने वाले हैं। एक्साइज और वैट 12-12 प्रतिशत बढ़ने वाला है। आप कह रहे हैं कि जी.एस.टी. बढ़ती ही है। हां पहले जी.एस.टी. 6-7 प्रतिशत बढ़ती थी लेकिन मुख्य मत्री जी के निर्देशानुसार जब एक्साइज और जी.एस.टी. के दो अलग-अलग विंग बने तो हमारे जी.एस.टी. कंपोनेंट में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

18.03.2025/1455/बी.एस./डी सी/-1

श्री आशीष बुटेल जारी...

उसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं। मुझे यह एक बहुत हैरत अंगेज बाद लगी, आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात की और आपने एलिमेंट्री और हायर की बात की। लेकिन आप यह भी तो देखिए वर्ष 2023-24 में जहां पर 84 करोड़ रुपए का बजट केवल हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एजुकेशन में रखा था आज वही बजट 1500 करोड़ रुपये बढ़कर वर्ष 2023-24 से आज वह बजट 9,965 करोड़ रुपये का यानी की 1500 करोड़ रुपये की वृद्धि उस बजट में हुई है। इस तरह से आपने सोशल वेलफेयर की बात की, उसमें हमने पिछली बजट एस्टीमेट से 100 करोड़ रुपये से बढ़कर 3158 करोड़ रुपये का बजट आपके सामने प्रस्तुत किया है।

एनर्जी में हमने 2.50 करोड़ रुपये का बजट बढ़ाया है और आपको सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर हम नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर है। एजुकेशन में 15 प्रतिशत जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है। हमारे यहां पर 18.9 प्रतिशत है। यह कांग्रेस पार्टी की सरकार ने करके दिखाया है। हेल्थ में आपकी नेशनल एवरेज से हम कहीं आगे हैं।

रोड्स एंड ब्रिजिज में नेशनल एवरेज 4.3 प्रतिशत की है, हम वहां पर 6.1 प्रतिशत हैं। वाटर सप्लाई और सेनिटेशन में जहां ढाई परसेंट की नेशनल एवरेज है वहां पर हम 6.1 प्रतिशत की एवरेज पर हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यहां पर यह फिगर्ज रखने बहुत जरूरी थे। क्योंकि हमारे मित्र गुमराह और भ्रमित करने में कोई चांस नहीं छोड़ते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यदि विपक्ष के माननीय सदस्यों को लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो अगला जो भी इनका स्पीकर होगा वह बोल लें। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की आपने बात की, वर्ष 2021-22 में 10,250 करोड़ रुपये की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट और आज रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो इस प्रदेश को आ रही है वह 3200 करोड़ रुपये की आ रही। इसका मतलब नालायकी की बात नहीं है। यह जो केंद्र सरकार भेदभाव करना जानती है उन स्टेट्स में जहां पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट से वहां पर यह शायद हो रहा होगा। आप यह समझिए 70 प्रतिशत आफ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आपकी कम हो चुकी है उसके बाद आप कहते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट पर आपने क्यों नहीं किया?

18.03.2025/1455/बी.एस./डी सी/-2

अनइंप्लॉयमेंट का पिरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जोकि आपकी नेशनल स्टैटिसटिक्स डिपार्मेंट करवाता है। उसमें यह था कि आपके समय में 14.1 प्रतिशत आपकी अनइंप्लॉयमेंट रजिस्टर्ड थी। आज वही हमारी सरकार के दौरान वह 9 प्रतिशत पर आ गई है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। महोदय, बस 5 मिनट का समय और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय, टूरिज्म कृषि और इन सभी क्षेत्रों में जो काम मुख्य मंत्री जी आपने किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। एम0एस0पी0 आपने बधाई और खास करके जो हल्दी की एम0एस0पी0 की बात की है, मैं समझता हूं एक किसान जो एक छोटे से अपने एरिया में कम-से-कम एक लाख रुपए की धनराशि साल भर कमा सकता है। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। ऊना का पोटेटो प्रोसेसिंग प्लांट आपने दिया, वह किसानों के लिए, खास करके परमार साहब आपके और मेरे क्षेत्र में जहां

पर आलू बहुत होता है और उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मैं चाहूंगा आप अपने भाषण में मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद जरूर करेंगे और अपने 50 लाख रुपये का एक रिवाल्विंग फंड भेड़ पालकों के लिए दिया। बहुत सारे एम0एल0ए0 हैं, जो ऐसे क्षेत्र से आते हैं जहां पर भेड़ पालक काफी मात्रा में हैं और उनके लिए यह जरूरी था कि हम एक रिवाल्विंग फंड उनको दें ताकि उनकी ऊन की खरीद हम कर सकें और उस ऊन को फिर बाद में जब बेचा जाता है तो लोगों को पैसा बहुत देर के बाद मिलता था। इस रिवाल्विंग फंड से उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और महोदय जो युवक मंडल और महिला मंडलों के लिए, खास करके यह कहा गया है कि प्लांटेशन और ट्रीज जो दो हेक्टर से ऊपर है, अभी आप इसका मजाक उड़ा ले कुछ भी कर ले, क्योंकि आप तो हर बात का मजाक उड़ाना चाहते हैं लेकिन एक महिला मंडल एक युवक मंडल के खाते में 6.40 लाख रुपये पांच साल के अंदर उनके खातों में जाएंगे। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। सोशल वेलफेयर की स्कीम जो आपने चलाई जिसके अंदर सामाजिक दृष्टि से सबसे अंतिम इंसान है उसके लिए भी आपने किया है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

18.03.2025/1500/DT/HK-1

श्री आशीष बुटेल जारी...

आज माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अतिरिक्त 37000 लाभार्थी सामाजिक पेंशन में इन्कलूड करने की बात कही है ,उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। विधवाहों की बच्चियों की शिक्षा के लिए, जब तक वह शिक्षा ग्रहण करेंगी उसका खर्चा उठाने की बात कही है , उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों कील स्थिति के बारे में बाते तो सब करते हैं लेकिन इनके उत्थान के लिए कोई काम नहीं करता लेकिन माननीय मुख्य मंत्री ने इस ओर कदम उठाया है। आर्थिक तौर पर पिछड़े आदमी को मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार 1.50 लाख रुपया देती है। लेकिन 1.50 लाख रुपये से तो आजकल

टॉयलेट नहीं बनता, घर बनाना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन मुख्य मंत्री महोदय ने इसको अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्ज करने की बात इस बजट में कही है, यह बहुत अच्छी पहल उनके द्वारा की गई है, इसके लिए भी मैं उनका का धन्यवाद करता हूं। मुख्य मंत्री विधवाह एवं एकल नारी आवास योजना में आपने उन विधवाहों के लिए मकान का प्रावधान रखा है उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा।

पर्यटन में विशेषतौर पर पालमपुर में जो टी-टूरिज्म का प्रस्ताव आप लेकर आए हैं, माननीय अध्यक्ष जी मैं यह बताना चाहूंगा कि it is only in Himachal जहां पर टी-टूरिज्म अलाउड है। मैं लाभार्थी हो सकता हूं I may start or I may not start but everybody in Himachal can start it. I am not going to be a sole beneficiary, it is said that 1.00 crore Rupees spent on Tourism Project can employee 5 people और अगर लाभार्थी मैं नहीं हूंगा तो लाभार्थी वह होगा जो वहां पर स्टुअर्ट का काम करेगा, जो वहां पर हाउस कीपिंग का काम करेगा इससे वह अपने परिवार को पालेगा। It will not be me who will be the beneficiary, it will be them also. मैं यहां पर पुलिस के संबंध में भी बात करना चाहूंगा। पिछली सरकार में हमने बहुत बार यह बात उठाई तब उनको एक दिन की 7 रुपये डाइट मनी मिलती थी यानी प्रतिमाह 210 रुपये। आज उनकी डाइट मनी को अगर किसी ने बढ़ाया है तो श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू जी की सरकार ने बढ़ाया है। पुलिस विभाग के सभी कांस्टेबल्ज को मैं यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने आज बी-1 का एग्जाम कंडक्ट करने की

18.03.2025/1500/DT/HK-2

जो बात की है यह उन कांस्टेबल्ज की प्रमोशन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहुंगा कि जो हमारे प्रदेश के युवा हैं उनको 25000 रोजगार देने की बात बजट में कही गई है। अगर रोजगार देने में पिछली भाजपा सरकार और वर्तमान कांग्रेस सरकार की तुलना करते हैं तो 1500 रोजगार पांच साल के कार्यकाल

में भाजपा के द्वारा दिए गए और अभी दो वर्ष् ही वर्तमान सरकार के पूरे हुए हैं और इन दो साल के कार्यकाल में ही वर्तमान सरकार ने 6000 रोजगार दे दिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेते हुए आपका धन्यवाद करता हूं पर मैं जनता से यह आग्रह करूंगा कि भाजपा की बातों में न आएं, इनकी बातों से भ्रमित न हों, क्योंकि यह व्यवस्था का दौर है। यह एक ऐसा दौर है जब हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश को समृद्ध और सुदृढ़ करना है, उस के लिए हम सब मिलकर काम करें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पिछले कल बजट पेश किया है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जय हिंद।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : माननीय अध्यक्ष जी, टूरिज्म की पॉलिसी यूनिफॉर्मटी में होती है, यह किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है। अभी तो हमने घोषणा की है कि टी-टूरिज्म की पॉलिसी हम लेकर आएंगे और 15 प्रतिशत असम या जहां भी टी-टूरिज्म होता है, एसी सभी स्ट्ेटस के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह किसी व्यक्तिगत लाभार्थी के लिए नहीं किया हुआ है यह टी-टूरिज्म से संबंधित सभी लाभार्थियों के लिए हुआ है।

18.03.2025/1500/DT/HK-3

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में भाग लेंगे मााननीय सदस्य डॉ. हंस राज जी।

डॉ. हंस राज : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो पिछले कल बजट इस माननीय सदन में बजट प्रस्तुत किया था, उसपर बोलने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल की बातें सुन रहा था। इनकी जो मजबूरियाँ हैं उनको भी मैं समझता हूं। इन्हें बजट के पक्ष में अच्छा-अच्छा बोलना है। मैं भी सिर्फ क्रिटिसिज़्म के लिए क्रिटिसिज़्म नहीं करूंगा या हर बात की मुखालफ्त हो , इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय,

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

18.03.2025/1505/एच.के.-एन.जी./1

डॉ0 हंस राज......जारी

जब चाचा चौधरी जी (माननीय कृषि मंत्री जी को देख कर हंसते हुए कहा) जब टोकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि हमें लगता है कि हम अभी भी बच्चे हैं। मैं चाचा चौधरी जी को बताना चाहता हूं कि इनके विभाग को भी कुछ नहीं मिला है। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा क्योंकि पठानिया जी (माननीय सदस्य, श्री भवानी सिंह पठानिया जी की ओर देखते हुए कहा) जब अपना भाषण देंगे तब ये सारे आंकड़े रखेंगे। हमने पूरे हाऊस के अकाऊंट्स का जिम्मा इन्हीं को दिया हुआ है और ये सभी चीज़ों को जस्टिफाई करेंगे। माननीय पूर्व मुख्य मंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जी ने यहां पर सारा विषय रख दिया है। बजट में कहा गया है कि जी0डी0पी0 की ग्रोथ 6.7 प्रतिशत हुई है, यह हुई है या नहीं और आगे फलीभूत होगी या नहीं, लेकिन यह रोजगार में कैसे तब्दील होगी या हम विकास कैसे कर

पाएंगे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है? जब हम आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रहे थे तो उसमें यह सब बातें दर्शाई जानी चाहिए थीं। यदि ये बातें उसमें नहीं होंगी तो हमारी चिंता बढ़ जाती है क्योंकि मैं व मेरे साथ के माननीय सदस्य इस माननीय सदन में पिछले लगभग 12-13 सालों से भाषण दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप भी जिला चम्बा से आते हैं और मैं जब जिला चम्बा के हालात देखता हूं तो वहां का केवल एकमात्र विधान सभा क्षेत्र इस बजट में नहीं है। इस बजट में हरोली विधान सभा क्षेत्र का भी जिक्र काफी बार किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बार बजट में काफी मैनेज किया है और हरोली विधान सभा क्षेत्र को हर मद के साथ जोड़ कर रखा है। मुझे तो लग रहा था कि जो स्नो एक्टिविटी शुरू की जा रही हैं वे भी कहीं हरोली विधान सभा क्षेत्र में न शुरू कर दी जाएं। लेकिन इसके लिए सिर्फ धर्मशाला का ही चयन हुआ है। मैं धर्मशाला विधान सभा क्षेत्र के लिए भी संशय में हूं क्योंकि माननीय सदस्य, श्री सुधीर शर्मा जी तो हमारे पक्ष में आ गए हैं तो इसे धर्मशाला में किस के लिए शुरू करने की योजना है?

18.03.2025/1505/एच.के.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा हो और रोजगार के साधन उपलब्ध हों तथा हम लोग कृषि-बागवानी में और आगे बढ़ें, मैं यही कामना करता हूं। आज सुबह माननीय राजस्व मंत्री, श्री जगत सिंह नेगी जी एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। मैं माननीय सदस्य, श्री कुलदीप सिंह राठौर जी का धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सेब के प्लांट्स, जिन्हें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, के संदर्भ में अपनी चिंता जाहिर की है, वह सराहनीय है। इनकी चिंता सच में बहुत भयावह चिंता है। जिला चम्बा में मनरेगा के तहत भी प्लांटेशन हो रही है। उसकी सप्लाई ऐसी नर्सरियों से हो रही है जहां के पौधों से पता ही नहीं चल पाता कि इसमें से लाल सेब निकलेगा, रॉयल सेब निकलेगा या गोल्डन

निकलेगा। इसके अलावा निकलेगा भी या नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उनके रेट अच्छे मिल रहे हैं जिससे बी0डी0ओ0 ऑफिस में काफी हलचल रहती है। मेरा मानना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी को इसमें जरूर हस्तक्षेप करना चाहिए। इनका हाल भी इंटरलॉक टाइल्स की तरह न हो जाए कि 12 रुपये की टाइल का टेण्डर 26 रुपये में हो जाए। मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस मामले में जरूर हस्तक्षेप करें और इसमें जांच बिठाएं। मैं कोई जोर से नहीं बोल रहा हूं लेकिन मुझे दर्द महसूस होता है क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंचायत ही ठीक कर सकती है और इसमें कोई दोराय नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि दूध के रेट इंक्रीज़ किए।...(व्यवधान) हमारे वहां पर तो 1.5-1.5 करोड़ रुपये की खच्चरें भी चली हैं। अध्यक्ष महोदय, आप चम्बा जिला से आते हैं और एक सम्मानीय पद पर विराजमान हैं। आप थोड़ा ध्यान रखें कि जो तथाकथित व्यक्ति आपसे मिलते हैं, वे किसी के भी नहीं हैं। वे 26-26 करोड़ रुपये का घोटाला करके बैठे हुए हैं और माननीय उच्च न्यायालय से जमानत लेकर आए हैं। यह एक चिंता का विषय बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले 08 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष पर मैंने चुराह में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उसमें मैंने कहा कि हम चिट्टे के विरूद्ध लड़ाई लड़ेंगे।

18.03.2025/1505/एच.के.-एन.जी./3

आपने (माननीय मुख्य मंत्री जी को देखते हुए कहा) वहां पर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है और जिस दिन माननीय लोक निर्माण मंत्री, श्री विक्रमादित्य सिंह जी वहां पर गए थे उस समय इन्हें रिझाने के चक्कर में कि मैं भी भाषण दे सकता हूं और माननीय लोक निर्माण मंत्री जी की पी0सी0 करवाई गई थी उस दिन वहां पर लाइट भी नहीं थी जोकि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैंने 08 मार्च वाले कार्यक्रम में कहा कि जो व्यक्ति चिट्टे को बेचने

वालों की जानकारी देगा उसे हम 51 हज़ार रुपये ईनाम देंगे। तो क्या हमने कुछ गलत बोल दिया है? वह व्यक्ति सीधे तौर पर तथा विभिन्न एजंसियों के साथ मिलकर, मैं इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से मिलकर अलग से चर्चा करूंगा कि आप एक बार उस व्यक्ति पर भी जांच बिठाइए। यहां पर हमारे वन विभाग के लोग (अधिकारी) बैठे हुए हैं। वहां पर कसमल के पेड़ के लिए तबाही मची हुई हैं और उसकी एवज में हमें कोई राजस्व प्राप्त ही नहीं हुआ है। लोग देहरदून व अन्य जगहों से वहां पर आए और कसमल के ट्रक भर-भर कर ले गए। उन लोगों ने वहां पर मैनेज किया हुआ था और कहा कि हम यहां पर ये दे रहे हैं, वह दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, असली चिंता यही है। हम कह रहे हैं कि हम हरित हिमाचल प्रदेश बनाने की दिशा में जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी, हमारी चिंता केवल इतनी है कि कसमल का पेड़ जब उख़ाड़ा जाता है तो बहुत नुकसान होता है। क्योंकि यदि कोई मिट्टी को जकड़ कर रखता है तो वह कसमल का पेड़ ही करता है। हमारे वहां पर तो इस पेड़ को केमल भी बोलते हैं। वहां पर केवल निजी भूमि से उख़ड़ने की इजाज़त दी गई थी। वन विभाग की खासियत देखो, मैं एक दिन पी0सी0सी0एफ0 साहब को मिला था और हमने कहा था कि

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

18.03.2025/1510/YK/PB/-1

डॉ0 हंस राज जारी...

आप इस तरफ भी ध्यान दें। लेकिन जो काम होने चाहिए वह धरातल पर नहीं हो रहे हैं। मैं आपके सामने सच्चाई जाहिर कर रहा हूं। हमें दर्द होता है कि हमारे देखते-देखते ऐसे जंगलों से कशमल उखाड़ी गई जहां 70-70 वर्षों, सदियों से कशमल लगी हुई थी। अब वह सारे फ्रेजाइल क्षेत्र हैं वह जमीन खिसक जाएगी। जैसा माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज जी के वहां हो रहा है कि अगर टनल का टेक्निकल तरीके से काम न किया जाए तो

जमीन कमज़ोर हो जाती है। यह हाइड्रो पावर में भी हुआ है, जिसकी वजह से किन्नौर दिक्कतों में फंसा हुआ है। चम्बा में भरमौर, चुराह और पांगी हाइड्रो पावर में भी दिक्कत है। यह इस वजह से है कि अगर टेक्निकली साउंड लोग इस काम को नहीं करेंगे या सही तरीके से जो काम को जानते हैं वह नहीं करेंगे तो वह अनाड़ी का खेलना खेल का सत्यानाश जैसा होगा, ऐसा प्रदेश के साथ हो रहा है। मेरा मुख्य मंत्री जी से यह निवेदन है कि आप इसमें हस्तक्षेप करें और बेहतर तरीके से करें। इसमें समय तो जा ही रहा है, हमें भी इस सरकार में भाषण देते हुए 3 वर्ष हो गए हैं। मैं माफी चाहूंगा लेकिन यह जरूर कहूंगा कि तीसा में स्पोर्टस के लिहाज से बहुत पोटेंशियल है। यह अच्छी बात है कि आपने खेल मैदान देने की बात कही है। आप खेल मैदान ऊना, हरोली, देहरा तथा इधर-उधार, सब जगह दे दें उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है परंतु चम्बा एक ऐसा स्थान है जहां पर बच्चों में जेनुइन पोटेंशियल है। बच्चे आज भी वहां 10-10 किलोमीटर सीनियर सेकंडरी स्कूल के लिए जाते हैं इसलिए अगर उनको ऐसे खामखा भी दौड़ाया जाएगा तो वह पहले नंबर पर ही आएगें। जैसे हम खुद सीनियर सेकंडरी स्कूल में पड़े हुए है। उन बच्चों में बहुत जज्बा है। चुराह क्षेत्र की बेटी चम्पा ने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा खेला है और ऐसी ही एक बेटी सीमा जिसने दौड़ में अच्छा प्रदर्शन किया है। कल मैंने डॉ0 राजीव भारद्वाज जी का संसद में दिया हुआ भाषण सुना, मैं उनको इस सदन के माध्यम से बधाई देता हूं कि कम-से-कम उन्होंने यह कहा कि पठानकोट से डलहौजी मात्र 50-55 किलोमीटर दूर है और वहां पर आसानी से रेल लाइन बन सकती है। आप रेल को भानुपल्ली, बिलासपुर, लेह-लद्दाख ले जाएं हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन नजदीक के सामरिक दृष्टि से देखें तो भारत के किसी मुल्क से युद्ध होने की स्थिति में जो सबसे नज़दीक के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, वह पठानकोट और अंबाला है। आज जिस तरह से बसों

18.03.2025/1510/YK/PB/-2

को रोका गया है यह भी चिंता का विषय है। जो लोग पंजाब की तरफ से वाहनों पर झंडे लगाए हुए आ रहे थे वे ह्रास हुए हैं। यह सारे संवेदनशील मामले हैं इसमें आपको मुखर होकर के कार्य करना चाहिए। मेरी चिंता सिर्फ इतनी है कि मुझे बेरोज़गार लोग बहुत फोन

कर रहे हैं ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने जे0बी0टी0, बी0एड0, पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट की हुई है। हमें संवेदनशील तरीके से बजट में कोई प्रावधान करना पड़ेगा। यह बात ठीक है कि हमारी माली हालत ठीक नहीं है लेकिन उस संदर्भ में हमें जाना पड़ेगा। अगर हमने आउटसोर्स पर भी भर्तियां की हुई हैं या जैसे अभी आंगनबाड़ी में 200, 300, 400, 500 रुपये ऐसे करके पैसे बढ़ाए गए है यह स्वागत योग्य है लेकिन एस0पी0ओ0 को भी उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए है। उनकी 26 वर्ष पहले अपॉइंटमेंट हुई है, यह तो शुक्र है कि मैं 1998 में 10वीं नहीं हुई थी नहीं तो मैं भी एस0पी0ओ0 लगा होता और चाचा चौधरी जी खुश हुए होते कि देखो वह एस0पी0ओ0 लग गया। हमारे भी हालत ठीक नहीं थे पिताजी पाइप फिटर थे तो 1200,1500, 700 रुपये इतनी तनख्वाह होती थी, तो उस समय लोग लग जाते थे और हम भी लगे होते। लेकिन 12वीं, ग्रेजुएट और एम0ए0 पढ़ा हुआ बच्चा जो पिछले 26 सालों से इस प्रदेश की सीमा पर पुलिस वालों के साथ-साथ अपनी पूरी-पूरी ड्यूटी देता है उनका 300 रुपये बढ़ाया है। मुख्य मंत्री से मेरा आग्रह और निवेदन है कि इस पर आप अनुकंपा जरूर करें कि उन एस0पी0ओज0 के लिए विशेष राहत दी जाए। यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष भी हैं इन्होंने भी प्रयास किए थे और इनके प्रयास से एस0पी0ओ0 पहली बार बजट में शामिल हुए और उनका जिक्र हुआ था। मैं आपके सामने यह प्रस्ताव रखता हूं कि इन एस0पी0ओ0 के लिए हम पक्ष-विपक्ष दोनों ही तरफ से दो-दो या तीन-तीन माननीय सदस्य दिल्ली चलते हैं। उन्हें जिस तरह से जम्मू-कश्मीर में 18-20, 26-28 पैकेज़िज मिलते हैं और उनकी जो शैक्षणिक योग्यता है उस हिसाब से मिलते हैं। हम उन्हें मर्ज़ नहीं कर सकते लेकिन कुछ मरहम तो लगा सकते हैं। उनके लिए कुछ न कुछ तो कर सकते हैं। उनकी यह गुज़ारिश मैं आपके सामने रख रहा हूं।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

18.03.2025/1515/YK/AP-1

डॉ0 हंस राज जारी....

अध्यक्ष महोदय आप इस विषय पर ध्यान दें क्योंकि आप भी चम्बा से आते हैं, दुर्भाग्य यह है कि इनमें से कुछ जिला चम्बा में लगे हैं और थोड़े से लाहुल-स्पिति में लगे हैं, माननीय सदस्य सुश्री अनुराधा जी इस बात को जानती हैं। इसके अलावा कुछ एस0पी0ओ0 पांगी, उदयपुर में हैं। वह लोग मुझे फोर्स करते हुए कहते हैं कि आपने हमारा यह विषय रखा है, पर देखें उम्मीद तो सरकार से ही होती है। सरकार माई-बाप है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन हमारा माई-बाप कौन-सी सरकार बनेगी यह थोड़ा चिन्ता का विषय है।

पर्यटन की दृष्टि से जो हमारा चम्बा, चुराह है। इसमें आप जोत का इलाका ले लीजिए। अगर यह द्रमण से जोत, चम्बा, तिस्सा, साच पास (जो 12 महीने स्नो बाउंडेड ही रहता है) 12 महीने आपको रास्ते में बर्फ देखने को मिलेगी। उसको हम एक्सपलोर नहीं कर पा रहे हैं और नई-नई वर्जन डेस्टिनेशनज़ की तरफ जा रहे हैं। उसको अगर हम नेशनल हाईवे में तबदील कर पाते हैं, इससे चम्बा की काया तो ऐसे ही पलट जाएंगी। ऐसा अगर हो गया तो आगे जाकर के पांगी को सुराल और इससे आगे लेह-लद्दाख की तरफ भी ले जा सकते हैं। बाया मण्ड़ी, मनाली और इधर से होती हुई, हमारी नेशनल हाईवे फोरलेन जा रही, यह 925 किलोमीटर बनती है। अगर दूसरी तरफ से लेह-लद्दाख तक ले जाएं तो वह 412 किलोमीटर बनती है। मैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी से 2018 में मिला था, उस समय भी जिक्र किया था और आज मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि इस नेशनल हाइवे की और भी सोचा जाए। पिछले कल जो माननीय डॉ राजीव भारद्वाज जी ने दिल्ली में कहा है कि ट्रेंन हमारे डलहौजी, खज्जियार, चम्बा-सदर, भटियात और चुवाड़ी आदि जगह तक भी पहुंच सकती है, इसमें क्या ही दिक्कत है। मुझे इस बजट के माध्यम से यह भी निवेदन करना है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र चुराह बहुत ही दूरस्त और हिल ट्रैक टॉप माउण्टेन्ड एरिया है, जिसके लिए हम यह कह सकते हैं कि एक स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। अभी आदर्श अस्पताल की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बजट अभिभाषण में करी। यह आदर्श अस्पताल वाला सिस्टम एक बार तीसा में शुरू कर दो, इस अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 400 से ऊपर की

18.03.2025/1515/YK/AP-2

ओ.पी.डी होती है। इस अस्पताल में सिर्फ दो ही डॉक्टर हैं। पेरासिटामोल और एज़िथ्रोमाइसिन जैसी दवाईयां इस अस्पताल में मिल जाए तो वह भी बहुत बड़ी बात है। यह दवाईयां भी उस अस्पताल में नहीं मिलती है। हमने उस अस्पताल में आर.के.एस. के माध्यम से चपरासी भी रखे थे, उनको भी वहां से निकाल दिया गया है। उस अस्पताल की स्वच्छता ऐसी बिखर गई है कि वहां पर माल-मवेशी बहुत बढ़िया तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन हमारे लोगों के हालात सच में बहुत ही बत्तर हो गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पी.एच.सी. की तो मांग ही नहीं कर रहा हूं। आप पी.एच.सी. बैरागढ़ और कोहाल वाली खोल दो, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वह अस्पताल लगभग 42 पंचायतों को फीड करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उसको ठीक कर दें और उस अस्पताल को आदर्श अस्पताल ही बना दें तो बहुत अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुछेक जगह काफी रिमोट एरिया है, बहुत सारी पंचायतें अभी भी सड़कों से छूटी हुई हैं। परसों माननीय मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी मुझे बीच में इंटरविन करके बोल रहे थे, मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि हमने जनवाल से सूईला की गिफ्ट डीड करवा दी है। इसमें पैसे दो, नाबार्ड वाले भी हमें पैसे नहीं देते। जिसकी चिट जाती है उसको ही पैसे दिये जाते है। हमारे पैसे तो कभी खर्च हुये ही नहीं होंगे। किसी दिन वहां पर भी झगड़ा होना है कि जब तक आपको किसी की चिट नहीं आती तब तक आप लोग पैसा ही नहीं देते है। यह हमारे साथ नाइसांफी ही है । गुईला से भंडोड़ी, तरवाई से लेकर बंजल तक, बेहाली वाया गोट, खजूआ करातोट, इनकी गिफ्ट डीड करवा दी हैं। शिंड रोड को तो फोरेस्ट क्लीयरेंस करवा दिया है और हमारी मुख्य सड़कें हिमगीरी से थनेला, आयल, साऊ, मक्कण, चचूण, सनवाल, इनका भी हमने फोरेस्ट क्लीयरेंस करवा दिया है। दूसरा जो शलेला बाड़ी और मझौगा दौणा का इलाका है वहां पर तो कहीं भी फोरेस्ट लैंड नहीं आती। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपने वहां पर जिसको टिकट दी थी, वह बोल रहा था

कि मैं कह रहा हूं कि 246 सड़कें बानाई। मैं विधान सभा के पटल पर कह रहा हूं कि मुझे विरासत में 16 सड़कें मिली थीं। लेकिन जब हमें मौका मिला, पूर्व मुख्य मंत्री जी के आर्शीवाद

18.03.2025/1515/YK/AP-3

से हमने 246 सड़कें कंस्ट्रक की और वहां पर गाड़ियां भी चलीं। जब लोगों ने टिकटें ली तब जाकर लोगों ने वहां जाकर वोट भी मांगे हैं। वहां पर ऐसे लोग जाकर (***) करते हैं। मुझे इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए परंतु अब तो बोल दिया है, अब क्या कर सकता हूं।

अध्यक्ष : आपने बोल दिया है तो अब इसको निकाल भी देते है।

डॉ0 हंस राज : अध्यक्ष महोदय, आप निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि कुहाल से लेकर सपरोट तक सड़क हमने बना दी थी। जब माननीय लोक निर्माण मंत्री चंबा गये थे, अगर वह चाहते तो उसका उद्घाटन भी कर सकते थे। हमने बकायदा उसकी टायरिंग भी करवा दी है।

श्री AT द्वारा जारी--

(***) **अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।**

18.03.2025/1520/AT/ए0जी0/1

श्री हंस राज जारी

और कोहाल से सपरोट और सपरोट से मसरूंड को बड़े मजे से जोड़ा जा सकता है। वहां भी हमने क्लीयरेंस दिलवाई है और गिफ्ट डीडें भी करवा दी हैं। सर, हमारे जितने प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं, तीन प्राइमरी स्कूल जो बंद हुए हैं, वहां पर बच्चे चार-चार, पांच -पांच किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। आप सर्वे करवा लो, वहां बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारे लिए यह बहुत जरूरी है। हर विधान सभा क्षेत्र को एक तराजू में न

तोलें। मैं मुख्यमंत्री जी से तब व्यवस्था परिवर्तन मानूंगा जब ये अपने उत्तर के दौरान कहेंगे कि मेरा जो बिजली बोर्ड का डिवीजन खत्म हुआ है, उसको मैं बहाल करता हूं और यह मेरी रिक्वेस्ट है। और जो हमने सब डिविजन खोया है,उसको बहाल कर दें। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। लाइट की वजह से बड़ा मुश्किल हो गया है मुख्यमंत्री जी। आपने कहा भी है। आप जब इसका उत्तर देंगे तो आप घोषणा ही कर देना कि भाई चलो हो गई यह कहानी पूरी। आदर्श स्वास्थ्य जो हमारा हॉस्पिटल है पूर्व मुख्यमंत्री जी ने 100 बैड्ड का किया है। वहां पर पूरे चार साल 17 डॉक्टर थे, जब तक हमारी सरकार रही। अब दो ही डॉक्टर रह गये हैं। ये दो काम तो बड़े ही जरूरी हैं। बाकी बस अड्डे पर तारकोल बिछा नहीं बिछा,चलो धूल चली है, दो-ढाई साल और सहन कर लेंगे, क्या दिक्कत है लेकिन मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारे लिए ये दो-तीन काम बहुत जरूरी हैं। मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा। लेकिन मेरा यह निवेदन , एक जो वन मित्रों और स्वास्थ्य मित्र कोई बताए गए हैं। वन मित्रों में ...व्यवधान मेरा यह निवेदन है कि वन मित्रों में जो सरकारी नर्सरियां लगी हैं जिनमें पौधे तैयार किए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी, यह बड़ा गंभीर विषय है। उन लोगों को इन्होंने पिछले दो-ढाई सालों से तनखाह नहीं दी है। पहले मस्ट्रोल टाइप बनाते थे और उसमें उनको एडजस्ट कर देते थे। अगर वन मित्र लगाए जाते हैं तो जो नर्सरियां चला रहे हैं, उनको उनमें तवज्जो दी जाए, यह मेरी आपसे गुजारिश है। इतना ही मुझे कहना था। इसके अलावा हमारे दो नेशनल हाईवे, एक भद्रवाह भलेशा से , पीछे मैंने मंत्री साहब से भी बात की थी क्योंकि यह पी0डब्ल्यू0डी0 का मैटर था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी जम्मू-कश्मीर ने एक पत्र शायद आपको भी लिखा होगा। मैंने आपसे चर्चा भी की थी

18.03.2025/1520/AT/ए0जी0/2

मक्कन,चचूल टनल का प्रस्ताव है, प्रस्ताव क्या उन्होंने वहां से स्वीकृति दे दी है। हमारी तरफ से ही कागजात जाने बाकी थे। एक तो वह, दूसरा जो पदरी जोत में जो मूवमेंट बढ़ाई है, सर, एक दिन आप पूरे काफिले के साथ जाइए क्योंकि आप सब कुछ हैं। आप जाएं वहां पर उन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा किया है। मैं फिर बोल रहा हूं और इस मंच

में बोल रहा हूं। मैं तो उनके जोत में जाकर भी बोल आया था। हालांकि जब मैं वोट मांगने गया उन्होंने कहा यही बंदा है जो उस वक्त वहां पर आया था। वहां पर उन्होंने अब सड़के निकालनी शुरू कर दी और सड़के निकाल भी दी। वहां जम्मू कश्मीर में रोपवे को गंडोला बोलते है। उन्होंने वहां पर दो गंडोले भी लगा दिए हैं। यह मैं हाउस में बोल रहा हूं क्योंकि वहां से मैं निकला हूं दिसंबर के महीने में। इसमें तो आप जरूर एक्शन लें सर। वह बहुत अच्छी जमीन है हमारी। दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारी एक भनोटी से एक डी0पी0आर0 किलाड़ तक पूरी अप्रूव हो गई थी और जनक राज जी भी यह विषय रखेंगे। यह बहुत महत्वकांक्षी योजना है। सर, इसको हम पी0 पी0 मोड पर या कुछ और कर सकते हैं। इसमें हमें दो-तीन प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे। हाईड्रो पावर में हमारे यहां आपने एक्सिअन ऑफिस बहाल किया है। उसके लिए धन्यवाद करता हूं। लेकिन हमारा सई कोठी वन, सई कोठी टू है टेपा-चंडू, यह प्रोजेक्ट बड़ी आसानी से चल सकते हैं। उसमें स्टाफ दे दीजिए, एक्सिअन ने तो ज्वाइन किया है। एक विषय जो है एन0एच0पी0सी0 वालों ने रखा है कि जो एन0एच0पी0सी0 का हमारा प्रोजेक्ट पांगी में बन रहा है, वे कह रहे हैं कि पॉलिसी में हमारी 5000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट है। 200 करोड़ तक तो सी0एस0आर0 में ही पैसा वे दे देंगे। तो वह विषय पांगी और चंबा का हमारे से जुड़ा हुआ विषय है। बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उनमें हाईड्रो में भी अगर हम करेंगे तो उसमें हम बेरोजगारी कम कर सकते है। मैं लास्ट में आपकी परमिशन से दो शब्द बोलूंगा इसमें मेरा यह निवेदन है, आपने जिस तरह से बजट पेश किया है,

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी....

18.03.2025/1525/MD/एजी/1

डॉ0 हंस राज---- क्रमागतः

इसमें कोशिश तो आपने अपने तरीके से की होगी कि आंकड़ों को ऐसे-वैसे घुमा दिया जाए। इन आंकड़ों में हम नहीं फंसते क्योंकि हम आर्ट्स के स्टूडेंट रहे हैं। हमारा बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड काम रहा है। अगर मुझे राहत नहीं है तो बजट में भी मुझे राहत नहीं दिखती है और मैं प्रदेश को भी उसी दृष्टि से देखता हूं। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आप उत्तर देंगे, आप तब एक शब्द जरूर इस्तेमाल करें कि चुराह को मैं विशेष निर्वाचन क्षेत्र मानूंगा और उसके स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़कों इत्यादि की पैरवी मैं स्वयं करूंगा। मैं माननीय सदस्या, श्रीमती कमलेश ठाकुर जी से भी यह प्रार्थना करता हूं। बजट मैं ऐसा बोलने या समर्थन करने के लिए कुछ नहीं है फिर भी आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.03.2025/1525/MD/एजी/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में भाग लेंगे मााननीय सदस्य श्री राम कुमार जी।

श्री राम कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। पिछले कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश का तीसरा बजट 18514.31 करोड़ रुपये पेश किया जोकि बहुत ही सराहनीय बजट है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जैसे शपथ ली थी कि प्रदेश का हर एक आदमी जोकि पिछली लाइन में खडा है और जिसकी बात किसी ने नहीं पूछी उसको तवज्जो देनी है, यह इनका मानना था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वह इस बजट में करके दिखाया है। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि रिसोर्सिज मोबलाइजेशन पिछली सरकारों के समय नहीं हुआ और वह कार्य मुख्य मंत्री बनते ही इन्होंने शुरू किया। जिसके चलते सबसे बडा उदाहरण मैं कहूंगा कि जब शराब के ठेकों की नीलामी होनी थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी से ठेकेदारों का एक दल मिला। उन्होंने कहा कि आप भी पिछली सरकार की तरह हमें 10 प्रतिशत इन्क्रीज लेकर रीन्यूअल दे दो आप जो कहेंगे हम पार्टी फंड में डाल देंगे। लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी का जिन्होंने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति पिछली सरकार ने जो खराब की है उसको अब मैं खराब नहीं होने दूंगा। इस वर्ष ठेकों की खुलेआम ऑक्शन करेंगे।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

जिसके चलते पिछली सरकार ने पांच वर्ष में जितना कमाया उतना इस सरकार ने एक वर्ष में कमाकर प्रदेश की आय में बढ़ोतरी की है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्याहवाद करता हूं। इन्होंने कहा कि प्रदेश की संपदा को मैं लूटने नहीं दूंगा। मैंने कई बार यह मामला उठाया कि जमीनें भले ही वो कस्टमाइज पैकेज में दी हो। सरकार ने एक रुपये या ढ़ाई सौ रुपये मैं अलॉट किया है। उन जमीनों से लगभग सौ से ड़ेढ सौ करोड़ की आमदन प्रदेश सरकार को होगी। जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी कार्य कर रहे हैं। उन जमीनों पर उनको समय दिया गया था कि वह दो वर्षों के भीतर उसमें काम शुरु करें। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करुंगा कि जिन्होंने काम शुरु नहीं किया उनको फौरी तौर पर कैंसल करें और उनकी ओपन-ऑक्शन करें। जो जमीन 250 रुपये मैं इन्होंने दी है

18.03.2025/1525/MD/एजी/3

उस जमीन की बजार कीमत जो है वह 15 हजार रूपये प्रति मीटर आज की डेट मैं है। जिससे प्रदेश की आय में बढ़ोतरी होगी। जिसके लिए आप दिन- रात काम कर रहे हैं। 31 मार्च 2023 को पिछली सरकार ने 76 हजार 185 करोड़ रुपये का ऋण विरासत में मौजूदा सरकार को दिया। अभी माननीय पूर्व मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि आंकड़ों का जाल,मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब उनकी सरकार थी।

श्रीमती के एस द्वारा जारी

18.03.2025/1530/केएस/एएस/1

श्री राम कुमार जारी---

मैं केवल दून क्षेत्र की बात कर रहा हूं जहां 36 स्कूल अपग्रेड किए। डिग्री कॉलेज बरोटीवाला दिया और उसके भवन के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि जारी की।

आई0टी0आई0 कुठाड़ व पट्टा दी। इसके साथ-साथ उन भवनों के निर्माण के लिए जो एस्टीमेट के मुताबिक राशि बनती थी, वह दी। बद्दी की पी0एच0सी0 को 50 बैडिड करके साढ़े नौ करोड़ रुपये की राशि उसके भवन के लिए दी। सी0एच0सी0 चण्डी में स्टाफ क्वार्टर्ज़, डॉक्टर क्वार्टर्ज़, हॉस्पिटल और बी0एम0ओ0 कार्यालय के लिए लगभग साढ़े तेरह करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी लेकिन माननीय जय राम जी की सरकार आते ही वे सारे पैसे डाइवर्ट हो गए। इनकी सरकार के पांच वर्षों के कार्यकाल में जो भवन हमने जहां छोड़े थे, वहीं के वहीं रह गए। हमारी सरकार बनी तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया कि जो भवन हमने वर्ष 2012 से 2017 के कार्यकाल में शुरू किए थे, उनका निर्माण कार्य अधूरा है इसलिए उनको राशि दीजिए। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करुंगा कि इन्होंने बद्दी हॉस्पिटल के लिए 3.74 करोड़ रुपये की राशि, जो ठेकेदार की देनदारी थी, वह दी जिससे उस हॉस्पिटल का कार्य अप्रैल तक कम्पलीट हो जाएगा और वह इनॉग्रेशन के लिए तैयार है। इसी तरह से चण्डी में बी0एम0ओ0 ऑफिस के लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने धनराशि दी। घियान खड्ड पर पुल का कार्य वर्ष 2012 में हमने शुरू किया था लेकिन पिछली सरकार के समय में केवल 80 लाख रुपये की राशि मिलने के कारण उसका कार्य बंद हो गया था। उसके लिए भी सवा करोड़ रुपये की धनराशि मुख्य मंत्री जी ने अभी जारी की है। इसी तरह से आई0टी0आई0 के भवन जो हमारे पट्टा और कुठाड़ में हैं, उनका कार्य भी अधूरा पड़ा था जिनका कार्य माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा अभी पूरा करवाया गया। जितनी भारी बरसात इस साल हुई, अगर उस समय हुई होती तो शायद, क्योंकि पिछली बार के समय में जो हमारे मुख्य रोडज़ के शैल्फ थे, वह जयराम जी की सरकार नहीं उठा सकी और वे रोड बंद रहे। मेरे चुनाव क्षेत्र के लगभग 434 घर तबाह हो गए थे। रोडज़ कनैक्टिविटी टूट गई थी। मैंने मुख्य मंत्री जी से आग्रह किया तो उनकी रेस्टोरेशन के लिए इन्होंने पैसा दिया और वे सारे रीस्टोर हो पाए। सिल्ह-सुल्हाणी और हमारा जो साई का क्षेत्र जिसमें बहुत ज्यादा तबाही हुई, उन क्षेत्रों के लिए हमने अभी सी0एस0आर0 के तहत तीन-तीन लाख रुपये के मकान बना कर दिए।

18.03.2025/1530/केएस/एएस/2

जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि मकान के लिए डेढ़ लाख रुपये की राशि एक मजाक था। माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में हमारी चर्चा हुई। हमने कहा कि कम से कम 10 लाख रुपये की राशि इसमें आप दें तो इन्होंने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सात लाख रुपये की राशि घोषित की जिसमें से तीन-तीन लाख रुपये की किश्त के रूप में पूरे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक जिला हैड क्वार्टर पर जा कर स्वयं लोगों को चैक बांटे जो कि मुख्य मंत्री जी की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम था।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत्त है और माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं मुख्य मंत्री जी ने शुरू कीं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि योजना, मुख्य मंत्री सुख आश्रय योजना, मुख्य मंत्री सुख आश्रय कोष की इन्होंने स्थापना की जिसमें स्वैच्छिक योगदान और सी0एस0आर0 फंड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वर्ष 2024-25 में इस योजना के अंतर्गत लगभग चार हजार से अधिक बच्चों को प्रमुख भारतीय त्योहारों के लिए त्योहार भत्ता एवं अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, वस्त्र भत्ता, पोषण अनुदान, मिश्रित अनुदान, उच्च शिक्षा और कौशल विकास, स्टार्ट-अप अनुदान के रूप में 14 करोड़ 77 लाख 02 हजार रुपये व्यय किए गए हैं। यह बहुत बड़ा काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश ग्रीन राज्य है। ग्रीन राज्य के मध्यनज़र माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन की दृष्टि से हमारे प्रदेश को विकसित करने का सपना देखा और इसमें बहुत महत्वपूर्ण कदम इन्होंने उठाया। इन्होंने कहा कि जो ग्रामीण इलाकों में लोग हमारे होटल बनाएंगे, वैलनैस सैंटर बनाएंगे या टूरिज्म के क्षेत्र में अन्य कार्य करेंगे उनको ब्याज दर जो है 4 प्रतिशत और प्रतिशत के रूप में सरकार उसमें वहन करेगी। यह बहुत बड़ा कदम माननीय मुख्य मंत्री जी ने उठाया और तीन-चार दिन पहले मेरे चुनाव क्षेत्र के कोई ढाई-तीन सौ लोग मुख्य मंत्री जी से मिले।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

18.03.2025/1535/av/AS/1

श्री राम कुमार-------- जारी

और उन्होंने कहा कि हमारी जमीनें चली गई हैं। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनके हाथ खड़े करवाए कि एक लाख रुपये, दो लाख रुपये और तीन लाख रुपये वाले कितने-कितने लोग हैं? इन्होंने उस समय तो कुछ नहीं कहा मगर मन में निश्चय कर लिया कि इन लोगों को इसी बजट में राहत दूंगा जोकि इन्होंने करके दिखाया। हम सभी जानते हैं कि बड़े-बड़े उद्यमियों के तो सभी सरकारों ने समय-समय पर ऋण के ब्याज माफ किए हैं या उनको अनुदान दिए हैं। मगर यह पहली ऐसी सरकार है जिसने ऐसे गरीब लोगों को जिनकी जमीन व घर बिक रहे थे और चैक लगाकर जिनको हाई कोर्ट और जिला मुख्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे थे। उन लोगों का दर्द समझते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह फैसला किया कि उन लोगों के ऋणों का 50 प्रतिशत ब्याज सरकार वहन करेगी जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में 50 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी, अगर आप चर्चा के दौरान अपने भाषण में इस बात की सराहना भी करते तो हमें काफी अच्छा लगता। लेकिन आपको तो राजनीति के लिए सरकार के हर कार्य की आलोचना करनी है। मैं माननीय श्री जय राम ठाकुर जी से कहना चाहूंगा कि आप और हम सभी यहां पर लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए आए हैं। ठीक है, आप विरोध कीजिए मगर उन चीजों की भी प्रशंसा कीजिए जैसे अभी माननीय डॉ0 हंस राज जी ने कहा कि आपने हमारे पंचायती राज संस्थाओं में नगर निगम के लिए चयनित प्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है।

माननीय मुख्य मंत्री जी इस बजट में पशु पालन विभाग के लिए 673 करोड़ रुपये का बजट सम्मिलित किया है।

कृषि विभाग के अंतर्गत Agriculture Loan Interest Subvention Scheme लाई गई है। जिसके तहत ऐसे किसानों, जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो उनके द्वारा लिए गए 3 लाख रुपये के कृषि लोन को चुकाने हेतु सरकार बैंकों के माध्यम से One Time Settlement Policy लाएगी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करूंगा क्योंकि इन्होंने किसानों के दर्द को समझा और उनके लिए यह

पॉलिसी लाई। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ही पहली बार गेहूं और मक्का जैसी फसलों के लिए अपने पिछले बजट में एम0एस0पी0 दी और इस बार इसमें बढ़ोतरी करके किसानों के हित में एक बहुत ही अहम कदम उठाया है।

18.03.2025/1535/av/AS/2

इसके अतिरिक्त इस बार बजट में हल्दी उत्पादन हेतु भी एम0एस0पी0 रखा गया है क्योंकि विश्व में 78 प्रतिशत हल्दी उत्पादन के साथ भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस वर्ष हल्दी के लिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की घोषणा की है। इसके लिए प्रदेश भर के उन किसानों को लाभ होगा जिनके पास बहुत ही कम जमीन है। वे उस कम जमीन में अपने परिवार का पालन-पोषण इस न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई बढ़ोतरी से बड़े अच्छे तरीके से कर पाएंगे जोकि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा एक प्रशंसनीय कदम उठाया गया है। कृषि क्षेत्र में आलू एक महत्वपूर्ण फसल है और राज्य में कुल सब्जी उत्पादन में आलू का 20 प्रतिशत हिस्सा है। अतः आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिला ऊना में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से 500 किलोग्राम प्रति घंटा की क्षमता वाले Potato Processing Plant को स्थापित करके हमारे ग्रामीण परिवेश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा कार्य किया है। यह प्रदेश में वर्ष की दोनों मौसमों की फसलों के लगभग 54,200 मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा।

इसके अतिरिक्त किसानों की सिंचाई के लिए सौ गांवों में सिंचाई योजनाओं का निर्माण करके Local Committees को स्थानांतरित किया जाएगा। कृषि यंत्रीकरण पर सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। परियोजना क्षेत्र के लाभार्थी किसानों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे और लगभग 4,000 Demonstration on Vegetable Cultivation आयोजित किए जाएंगे जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार करूंगा। Weather Based Crop Insurance Scheme के अंतर्गत लगभग 60,000 से अधिक बागवानों को लाभ मिलेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने हमारे ग्रामीण परिवेश के लिए इस प्रकार के सराहनीय कदम उठाए हैं।

एन0एस0 **द्वारा जारी**

18-03-2025/1540/NS-एच0के0/1

श्री राम कुमार ----- जारी

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ग्रीन हिमाचल के सपने को साकार करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र के विस्तारीकरण के विभिन्न कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है और वर्ष 2025-26 के लिए 5,000 हैक्टेयर में वृक्षारोपण का लक्ष्य तय किया गया है जिसमें जंगली फलों के पौधों और अन्य फलदार पेड़ों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा कदम है क्योंकि यहां पर पिछले जितने भी सत्र हुए हैं तो उनमें बहुत से माननीय विधायकों ने जंगली जानवरों से फसलों को बचाने हेतु चर्चा की है। लेकिन पिछली सरकारों ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। हम जब तक जंगली जानवरों को जंगल में नहीं रोकेंगे, उनको खुलेआम खेतों में आने से नहीं रोकेंगे तब तक फसलों को नहीं बचाया जा सकता है। इसके लिए ठोस कदम मुख्य मंत्री जी ने उठाया है। हमारे कई लोगों ने कृषि करना छोड़ दिया था। उसके लिए मुख्य मंत्री जी ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी की सराहना करूंगा।

इस दस्तावेज में कहा गया है कि महिला मंडलों को 1 लाख रुपये से ले करके 6.50 लाख रुपये की राशि हर वर्ष दी जाएगी। पहले महिला मंडल डिमांड करते थे कि हमें ग्रांट दी जाए। अब ग्रांट के साथ-साथ मुख्य मंत्री जी ने काम भी बांटा है। जिसके तहत महिला मंडल सुदृढ़ होंगे और उनकी आमदनी में भी वृद्धि होगी तथा उनको काम भी मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने दून विधान सभा क्षेत्र में भवनों को पूर्ण करने के लिए पैसा दिया है। मेरे क्षेत्र में बद्दी-शीतलपुर रोड के लिए पिछले वर्ष घोषणा की थी और उसका पैसा आ गया है, उसका टेंडर भी लग गया है। लगभग 66 करोड़ रुपए की राशि से हरियाणा बॉर्डर से जगातखाना में ड्रग पार्क बन रहा है। मैं इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि इन्होंने यह बड़ी राशि स्वीकृत की है। भाट की हट्टी से कुठार

रोड हेतु 22.50 करोड़ रुपये सड़क को चौड़ा करने के लिए दिए गए है और यह कार्य चल रहा है। जोहड़जी-ढकिरियाणा मार्ग को लगभग 5.35

18-03-2025/1540/NS-एच0के0/2

करोड़ रुपये की राशि मुख्य मंत्री जी ने स्वीकृत की है। गांगुडी-काटल का बाग जोकि धर्मपुर को रोड आएगा उसके लिए भी लगभग 5.50 करोड़ रुपये की राशि से कार्य चल रहा है। मैं मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मेरे क्षेत्र में चण्डी अस्पताल है उसमें बी0एम0ओ0 के साथ-साथ डॉक्टर्ज के क्वाटर्ज बनने शेष हैं तो उसके लिए भी धन का प्रावधान किया जाए ताकि उनको कंपलीट किया जा सके। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने पी0एच0सी0, पट्टा को सी0एच0सी0 बनाया था लेकिन जब से सी0एच0सी0 बनी है उसमें एक ही डॉक्टर रह गया है। यह अस्पताल 14 पंचायतों को कवर करता है। लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं लेने के लिए सोलन जाना पड़ता है। मैं आग्रह करता हूं कि सी0एच0सी0, पट्टा में डॉक्टर का एक पद सृजित किया जाए ताकि वहां के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिले।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग का एक्सिअन कार्यालय नहीं है। उसके लिए भी मैं मांग करता हूं कि मेरे दून क्षेत्र में जैसे हमें बी0डी0ओ0 कार्यालय दिया है, बी0एम0ओ0, बद्दी दिया है वैसे ही लोक निर्माण विभाग का कार्यालय हरिपुर में दिया जाए क्योंकि यह सेंटर प्लेस पड़ता है। नालागढ़ से बद्दी 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नेशनल हाइवे होने के कारण हर रोज कोई न कोई एक्सिडैंट होता रहता है। पी0एच0सी0, मानपुरा चल पड़ी थी और इसके लिए भवन भी बना दिया गया है लेकिन इसे डिनोटिफाई कर दिया गया है। मैं चाहूंगा कि इस पी0एच0सी0 को रिनोटिफाई करके दोबारा खोला जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसके लिए सी0एस0आर0 के तहत भवन का निर्माण करवा दिया गया है।

वहां पर लगभग 350 लोगों की ओ0पी0डी0 रोज होती थी और यह बहुत जरूरी अस्पताल है। बरोटी वाला-बनलगी, स्पाठू-दयोडी सोलन रोड में सोलन विधान सभा क्षेत्र, कसौली और दून विधान सभा क्षेत्र कवर होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण रोड है। इससे बनलगी का जो औद्योगिक क्षेत्र है वह भी बसेगा और वहां पर लगभग 250 बीघा जमीन उद्योग विभाग की है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.03.2025/1545/RKS/एचके-1

श्री राम कुमार.... जारी

हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोग जो छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं इससे उन्हें रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसके लिए तीन स्टेप्स पर डी0पी0आर0 बनाई गई हैं। पहला पैच, बरोटीवाला से हरिपुर तक है उसकी डी0पी0आर0 नालागढ़ डिवीजन द्वारा बनाई गई है और इसकी लागत लगभग 35.84 करोड़ रुपये है। दूसरा पैच, हरिपुर से सपाटू तक है जिसकी डी0पी0आर0 136 करोड़ रुपये की है। तीसरा पैच, सपाटू से सोलन तक है जिसमें 84 करोड़ रुपये की डी0पी0आर0 बनाई गई है। मैं चाहूंगा कि हमारा पहला पैच जो 35.84 करोड़ रुपये का है, अगर इस बजट में स्वीकृत हो जाता है तो इस रोड के कार्य की शुरुआत हो जाएगी। इस सड़क के बनने से हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। बद्दी के वार्ड नंबर-3, सुराज माजरा में लगभग 65 बीघा जमीन समतल है। हमारे दून क्षेत्र में अभी तक कोई स्टेडियम नहीं है। मैंने पहले एक इंडोर स्टेडियम की स्थापना की थी। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि मेरे क्षेत्र में स्टेडियम के लिए बजट का प्रावधान किया जाए। हमारा क्षेत्र सीमा क्षेत्र के साथ लगता है और यहां के बच्चों को नशे की लत लग रही है। अगर यह स्टेडियम बन जाता है तो इससे हमारे युवाओं का भला होगा। हमारे यहां बी0बी0एम0बी0 के अधीन एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जहां कई सड़कें बी0बी0एम0बी0 द्वारा मेंटेन की जाती हैं। पिछली बार हमने इसका बजट लगभग 85 करोड़ रुपये तक बढ़ाया था लेकिन पिछले दो वर्षों से बी0बी0एम0बी0 का बजट जीरो है जिस कारण इस औद्योगिक क्षेत्र की सड़कों की हालत बहुत खराब है। वहां पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

नहीं है और सीवरेज सिस्टम भी बहुत खराब है। मेरा मुख्य मंत्री जी से अनुरोध है कि आप इस विकास प्राधिकरण का बजट फिर से बहाल करके इस बजट में कम-से-कम 50 करोड़ रुपये स्वीकृत करने की कृपा करें। मैंने डे बोर्डिंग स्कूल के लिए बद्दी के कल्याणपुर मौजा में 63 बीघा जमीन ट्रांसफर करवाई थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने 1 करोड़ रुपये की प्रपोजल भेजी है और हमारे जितने भी स्कूल हैं उनकी छात्र संख्या एक हजार से पंद्रह सौ तक है। झाड़माजरी के प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या एक हजार है, जहां अध्यापकों की कमी थी लेकिन मुख्य मंत्री जी ने अध्यापकों के पद सृजित किए हैं जिससे यह कमी दूर हो जाएगी। मेरा अनुरोध है कि हमारे क्षेत्र में डे बोर्डिंग स्कूल तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। मैं इस बजट का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं, क्योंकि यह एक अच्छा बजट है।उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

18.03.2025/1545/RKS/एचके-2

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया है। सरकार हमेशा यह कहती आई है कि पूर्व सरकार ने फिजूलखर्ची करते हुए हमारी सरकार को मुश्किलों में डाला लेकिन मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने जो मित्र मंडली की फौज खड़ी की है और जो सी0पी0एस0 बनाए थे, क्या वह फिजूलखर्ची नहीं थी? मैं माननीय न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं जिसने माननीय विधायकों को सी0पी0एस0 के पद से हटने के आदेश पारित किए। आज सरकार के सिर पर कोई जूं नहीं रेंग रही है लेकिन सरकार जिस तरह से सरकारी कोठियों की रेनोवेशन के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है वह पैसा कहां से आ रहा है? जब हम सरकार से विकासात्मक कार्यों के लिए पैसे की मांग करते हैं तो सरकार यह कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और हमें केंद्र सरकार से पैसे की मांग करनी चाहिए। हमारी केंद्र सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है और केंद्र से जो पैसा मिल रहा है उसी से हमारे प्रदेश में भी विकास के कार्य किए जा रहे हैं। आज कई विधायकों को कैबिनेट रैंक का दर्जा दिया गया है उनकी आलीशान कोठियां हैं और उनके साथ जो गाड़ियां चल रही हैं, क्या उन पर सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है?

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

18.03.2025/1550/बी.एस./वाई के/-1

श्री इन्द्र सिंह गांधी जारी...

लेकिन जब कोई गरीब अपनी व्यथा सुनाने के लिए आता है या सहायता मांगता है कि मुझे मेडिकल के पैसे दिए जाएं तो कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि यह जो खजाना है इसे वर्तमान सरकार ने 50 साल से खत्म करते हुए आई है और आज दिन तक इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आदणीय जय राम ठाकुर जी ने जितने भी संस्थान खोले थे, उन्हें रद्द कर दिया गया और रद्द करने के बाद हम बार-बार मांग करते हैं कि मेरे नेचौक मण्डल या मेरे नेरचौक शहर में जो मैडिकल कॉलेज है उसकी व्यवस्था और सुविधा चरमरा गई है। जब लाइट चली जाती है तो वहां पर चोरी होती है। वहां पर जो टेबल और कुर्सियां हैं उन्हें चुरा कर ले जाते हैं। वहां जो गद्दे और कंबल हैं उन्हे चुरा कर ले जाते हैं। पूर्व सरकार ने वहां पर बिजली बोर्ड का डिवीजन खोला था उसको बंद कर दिया गया और उसे बंद करने के बाद आज उस अस्पताल की यह हालत बन गई है कि महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। मेरा आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस बिजली बोर्ड के डिवीजन को जल्द से जल्द खोला जाए। आज लोगों को एक बिजली का पोल और एक तार के लिए मण्डी जाना पड़ता है। हमारा नेरचौक का सब डिवीजन सुन्दरनगर, रिवालसर का सब डिवीजन मण्डी जाता है और जो हमारा बग्गी का सब डिवीजन है वह गोहर जाता है। लोगों को इतनी दिक्क्त है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने देखा नहीं कि इस मैडिकल कॉलेज में बिजली की कितनी जरूरत है या इस शहर में कितनी जरूरत है। उसे आनन-फानन में बंद कर दिया गया। मुख्य मंत्री जी शायद अपने कमरे में बैठे होंगे, मेरा उनसे निवेदन है कि इस बिजली के डिवीज को खोला जाए ताकि आम लोगों और मरीजों

को बिजली की सुविधा मिल सके। वहां पर मीटर भी लगे हुए हैं, वहां पर केमरे भी लगे हुए हैं। वह कैमरे किस लिए लगाए हुए हैं जब बिजली ही चली जाएगी तो कैमरे क्या काम करेंगे। वे कैमने किस लिए लगाए हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए वहां हर कमरे में कैमरा है। मेरा कहने का मतलब है कि वे कैमरे भी जाली हैं क्योंकि वे न चोर को पकड़ पाते हैं और न चोर पकड़ा जाता है।

18.03.2025/1550/बी.एस./वाई के/-2

मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में कहना चाहूंगा कि यह जो अभिभाषण था उसमें हमारे कई नेता लोग सोए हुए थे और मजाक बना रहे थे। बाद में मेज थपथपा रहे थे कि राज्यपाल महोदय ने अच्छा भाषण दिया और अच्छा भाषण पढ़ा। जो सोए हुए मंत्री थे या सोए हुए एम0एल0ए0 थे वे सबको क्या संदेश दे रहे थे और उनसे क्या सीखेंगे? जब मैंने पूछा कि ये लोग खराटे मार रहे हैं तो ये बजट में क्या चर्चा करेंगे और इन्हें कैसे पता चलेगा कि बजट मैं क्या लिखा है?

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : माननीय सदस्य, यह जो माननीय सदस्य सोए हुए थे इन्हें क्या दंड देना चाहिए।

श्री इन्द्र सिंह गांधी : जो सदन में सोए हुए थे इन्हें रिटायरमेंट दे देनी चाहिए। इनकी काम करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। मेरा कहना का मतलब है कि यह व्यवस्था परिवर्तन है न कि बजट का परिवर्तन है। मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि मैंने सुख आश्रय योजना दी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन ऐसे बच्चे हैं जिनकी न मां है और न बाप है और न ही उनके पास कोई जमीन है। उन तीनों व्यक्तियों को आज दिन तक सुख आश्रय का कोई लाभ नहीं मिला है और न ही घर मिला है। मैं सदन में उनके नाम पढ़ना चाहता हूं। कुमारी कामनी देवी, तेज कुमारी सुपुत्री स्वर्गीय श्री भवानी सिंह, इसी तरह रोहित कुमार सुपुत्र स्वर्गीय श्री भवानी सिंह ये दो बेटियां और एक बेटा है। माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमने

सुख आश्रय योजना चलाई है और सब को सुख दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इन बच्चों को कब सुख मिलेगा जिनके मां-बाप मर चुके हैं।

उपध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इन बच्चों को पंजीकृत करवाई।

श्री इन्द्र सिंह गांधी : महोदय, अगर आपने बजट दिया होता तो आपके विभागों में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

18.03.2025/1555/DT/YK-1

श्री इन्द्र सिंह जारी...

आपने बजट में कहा कि हम कृषि क्षेत्र को सशक्त बना रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। इनके विभाग में इतना भ्रष्टाचार है बजट की बात तो दूर है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि कृषि विभाग की ओर से 1 प्रतिशत बजट बढ़ाया गया है और यह कहा गया है कि हम कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। महिला मंडल और युवक मंडल जो उस काम को करेंगे चाहे वह वन विभाग में पौधे लगाने की बात हो, चाहे बंजर भूमि को खेतिहर करने की बात हो, आज वह बंजर भूमि है क्यों है? इस बंजर भूमि पर जो पौधों पहले लगाए गये थे वह पौधे कहां गये? आज महिलाओं की बात की जा रही है। पहले भी आपने प्रदेश की महिलाओं को ठगा। महिला मंडलों को जो लेकिन आपने 4 या 5 प्रतिशत का जिक्र जो किया है उससे आप महिलाओं को फिर ठगेंगे। पहले आपने 1500 रुपये देने की बात की और आज आप 2.4 प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं। महिला मंडलों और युवक मंडलों के द्वारा आप बंजर भूमि में पौधा रोपण की बात कर रहे हैं। आजकल सभी के घर में एक बच्चा होता है वह युवक मंडल में काम करेगा या आप उसे रोजगार देंगे? यह बजट झूठ का पुलिंदा है और सिर्फ ठगबाजी की सरकार चली हुई है, यह बात मैं दावे के साथ बोलता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कांवाकुन्नी एक

रोड है। माननीय लोक निर्माण मंत्री यहा बैठे हुए हैं, उस रोड के लिए बजट दिया गया उसका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन अधिकारी बोलते हैं कि यह रोड तो लड़ाई-झगड़े वाला है, मैं आज 58 वर्ष का हो गया हूं लेकिन वह रोड अभी भी वहीं का वहीं है, वह रोड न इधर खिसका न उधर खिसका आज तक उसको पक्का नहीं किया जा रहा है। 6.84 करोड़ रुपये की राशि उसके लिए सैंक्शन हुई है। इस रोड में 180 मीटर की लैंथ ही पक्का करने के लिए शेष बची है क्योंकि उस लैंथ में थोड़ा डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है वह विभाग जाने, लेकिन जो विभाग के द्वारा इस काम के लिए लीपापोती की जा रही है और लोगों को ठगा जा रहा है। क्योंकि वहां लोग आपस में लड़े हुए हैं। लेकिन विभाग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए मैं माननीय लोक निर्माण मंत्री जी कहना चाहता हूं कि इसका संज्ञान लिया जाए। इसमे कौन सा अधिकारी दोषी है? क्या इसमें जो जमीन का मालिक है वह दोषी है? 58 वर्ष इस रोड को बने हुए हो गए और आज इस

18.03.2025/1555/DT/YK-2

रोड को पूरा पक्काा होने से रोका जा रहा है। मेरा कहने का अर्थ है कि जो 180 मीटर की लैंथ इस रोड की बची हुई है, उस हिस्से को भी पक्का किया जाए अन्यथा उन अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाए जिनके कारण यह काम लटका हुआ है या जो उस भूमि का मालिक है उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाए। क्योंकि उस रोड के पक्के न होने के कारण लोगों को दिक्कत आ रही है। लेकिन रोड के कच्चे होने के कारण उस रोड के हिस्से में पानी खड़ा हो जाता है जिसके कारण कई बार वहां दुर्घटना हुई हैं। पिछले दो-तीन साल से इस रोड का काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसका संज्ञान लिया जाए। नेर चोक का का जो नगर परिषद है आपने उसके लिए बजट में बात कही। मैं यह कहना चाहता हूं कि आजतक एक भी ग्रांट नगर परिषद, नेर चोक को वर्तमान सरकार द्वारा नहीं दी गई है। लेकिन जो विधायक निधि मेरे द्वारा दी गई है या जो सांसद निधि की राशि इसके लिए प्राप्त हुई है, वह 2 करोड़ 44 लाख रुपये की है, उस राशि का उपयोग भी नहीं हो पाया है क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार के टेंडर नहीं हो पा रहे हैं, और आप बजट की

बात कर रहे हैं। इस नगर परिषद को बजट देने की बात दूर लेकिन जो ग्रांट इसके लिए आनी थी उसे भी रोक रखा है। इसके लिए जो विधायक निधी से पैसा दिया है उस से ही टेंडर लगाने का काम हो रहा है। यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, यह मेरा कहना है। आप प्रदेश में विकास के बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। हम प्रदेश में सड़के बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल शक्ति मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, वह अभी अपने स्थान पर विराजमान नहीं हैं, मैं पहले भी तीन बार इस माननीय सदन में कह चुका हूं कि जो मेरा क्वाड़मार्क नेरचोक है वहां पर सुकेती खड्ड है, वहां पर दस-बारह घर ऐसे हैं जिनको खतरा बना हुआ है। आज से पूर्व सुकेती खड्ड में जो सिल्ट आती थी उसके लिए बी.बी.एम.बी. बुलडोजर लगाती थी और उसके द्वारा सिल्ट को उठाया जाता था। इससे सुकेती खड्ड का लेवल डाउन हो जाता था। लेकिन अब सिल्ट जब उस खड्ड में जमती है तो उससे पानी का स्तर ऊपर उठ जाता है और पानी वहां रह रहे लोगों के घरों में घुस जाता है, इससे लोगों को व उनके घरों को खतरा निरंतर बना रहता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने उसका आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया। मैं इसके संदर्भ में माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय से मिल चुका हूं और माननीय

18.03.2025/1555/DT/YK-3

मुख्य मंत्री महोदय से भी मिल चुका हूं। वहां जो लोग रहते हैं वह गरीब लोग है और वह रो रहे हैं। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में कंसा चोक है वहां पर एक मैदान बना हुआ है । वर्ष 2023 में इस मैंदान में त्रासदि आई जिसके कारण इस मैदान का एक बीघा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, यानी उस क्षेत्र का इरोजन हो गया। पूर्व में खेल मंत्री रहे माननीय विक्रमादित्य जी से भी मैं इस संदर्भ में मिला था और इनसे आग्रह किया था कि इस मैदान को बचाया जाए क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र बल्ह में यह एक ही मैदान है। चाहे पॉलटिकल इवेंट के आयोजन की बात हो, चाहे किसी सामाजिक इंवेट की बात हो किसी भी इवेंट की बात हो, हरेक कार्यक्रम उसी मैदान में होता है।

श्री एन.जी.द्वारा जारी....

18.03.2025/1600/ए.जी.-एन.जी./1

श्री इन्द्र सिंह......जारी

बच्चे वहां पर खेलते-कुदते हैं। वहां पर टूर्नामैंट भी आयोजित किए जाते हैं। वहां पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं लेकिन आज तक भी उस ग्राऊंड को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। वहां पर न तो प्रोटैक्शन वॉल लगाई जा रही है और न ही क्रेट वॉल लगाई जा रही है। मैं इसके समाधान के लिए बार-बार चींख रहा हूं क्योंकि वहां के बच्चे बुरी आदतों की ओर आगे बढ़ रहे हैं और चिट्टे का नशा कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में एक कंसा का ही ग्राऊंड है जहां पर बच्चे खलते हैं। मेरे क्षेत्र के बच्चे आज उस ग्राऊंड से भी वंचित हैं और बुरी आदतों की ओर जा रहे हैं। मेरा कहने का यह मतलब है कि जब आप उस ग्राऊंड को दोबारा से बना देंगे तो वहां पर बच्चे खेलेंगे-कुदेंगे और नशे व चिट्टे की ओर जाने से बच जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने बजट में घोषणा की कि मेडिकल कॉलेज में 21 करोड़ रुपये की लागत से एम0आर0आई0 की मशीन लगा दी जाएगी। मैं माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर एम0आर0आई0 मशीन लगाने के लिए वर्ष 2022 में टेण्डर हो चुका था लेकिन सरकार बदलने के बाद इस टेण्डर को निरस्त कर दिया गया और दोबारा से टेण्डर नहीं लगाया गया। लेकिन इस बजट में इसकी घोषणा फिर से कर दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस बजट में बल्ह विधान सभा क्षेत्र के लिए क्या दिया गया है? मेरे क्षेत्र को सिर्फ छुनछूना दिया गया है। मैंने पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा देने की बात कही थी। मेरे क्षेत्र में रिवालसर की झील, कुंथ की झील और

एक नलसर की झील है। इन तीनों झीलों को यदि पर्यटन की दृष्टि से बढ़ावा दिया जाए तो इससे हमारे क्षेत्र के हज़ारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। मैं अनेकों बार इस विषय के संदर्भ में कह चुका हूं और लिखित तौर पर भी माननीय मुख्य मंत्री जी को दे चुका हूं।

18.03.2025/1600/ए.जी.-एन.जी./2

मेरा पर्यटन निगम के चेयरमैन और माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस विषय को गम्भीरता से लिया जाए ताकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुंथ की झील को विकसित किया जा सके। इसके अलावा रिवालसर की झील के लिए भी मास्टर प्लान तैयार किया जाए और नलसर की झील में नाव के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। आज सरकार कहती है कि हम 25 हज़ार नौकरियां देंगे। मैं कहता हूं कि सरकार यदि एक साल में 5000 नौकरियां भी दे देगी तो मैं इनको ईनाम दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह झूठ का पुलिंदा हमेशा चलता रहा है। वर्तमान सरकार ने कहा था कि एक लाख नौकरियां प्रतिवर्ष दी जाएंगी। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने जिन 20 हज़ार लोगों को नौकरी से निकाला था उन्हें तो आज तक पुनः नौकरी नहीं दी गई है। इस प्रकार से सरकार कौन-से बजट की बात कर रही है?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनदेखी हो रही है। मेरे क्षेत्र के मिनी सचिवालय में आज केवल एस0डी0एम0 महोदया ही बैठ रही है। तहसीलदार वहां से 3 किलोमीटर दूर ढ़ढ़ोर में बैठता है। नायब तहसीलदार व अन्य कर्मचारी भी वहीं पर बैठते हैं। उस भवन में जब एस0डी0एम0 को काम होता है तो तहसीलदार उठ जाता है और जब तहसीलदार को काम होता है तो अन्य कर्मचारी उठ जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर मिनी सचिवालय श्री जय राम ठाकुर जी की देन है और उसका कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। उसको पूर्ण करने के लिए केवल 2 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। मैं पिछले 2

वर्षों से 2 करोड़ रुपये की राशि मांग रहा हूं। इस भवन के पूर्ण हो जाने के बाद क्षेत्र के लोगों को एक छत के नीचे सभी विभागों की सुविधाएं प्राप्त होंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, रिवालसर के सिविल अस्पताल को माननीय पूर्व मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी ने दिया था। पूर्व सरकार के समय में वहां पर लगभग 10 डॉक्टर हुआ करते थे लेकिन आज उस सिविल अस्पताल में केवल दो डॉक्टर हैं।

18.03.2025/1600/ए.जी.-एन.जी./3

एक डॉक्टर दिन को आता है और एक डॉक्टर रात में आता है। दिन वाला डॉक्टर तो स्वयं नशे में रहता है और वह लोगों का कैसे उपचार करेगा? माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष शिवरात्रि महोत्सव के दौरान उस सिविल अस्पताल के भवन का मण्डी से ही उद्घाटन किया था। उसकी उद्घाटन पट्टिका को कोने में लगाया गया था और उसके आगे डब्बे भी रख दिए गए थे ताकि इसे कोई देख न पाए। वहां पर न तो कोई मशीनरी है, न ही कोई प्रयोगशाला है और न ही डॉक्टर्स हैं, सरकार इस प्रकार से कैसी स्वास्थ्य सुविधा की बात करती है? मेरा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जी से निवेदन है कि वहां पर डॉक्टर्स की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में एक पी0एच0सी0 लेधा है। वर्ष 2023 की आपदा में उसका पूरा आंगन डह गया था। वहां के नेता हैं और वे ए0एम0सी0 के चेयरमैन हैं तथा मेरे दोस्त हैं। उस पी0एच0सी0 के आंगन का डंगा डह गया है जिससे उस पी0एच0सी0 को खतरा बना हुआ है।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

18.03.2025/1605/AG/PB/-1

श्री इन्द्र सिंह जारी...

जब वहां पर कोई बच्चा या मरीज़ आता है तो वहां किसी अप्रीय घटना का खतरा बना रहता है लेकिन आज तक उस डंगे को न पक्का किया गया है और न ही लगाया गया है। माननीय जय राम ठाकुर जी ने इसके लिए 80 लाख रुपये की राशि दी थी लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यह इस सरकार का व्यवस्था परिवर्तन है। अगर आप इस बजट की बात करते हैं तो मैं इसे दिशाहीन कहूंगा और मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

18.03.2025/1605/AG/PB/-2

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे यह बोलते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि यह बजट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही निराशाजनक और एक हताशा से भरा हुआ बजट है । इस बजट में सारे के सारे सेगमेंट कवर्ड हैं। समाज के हर वर्ग के लिए इस बजट के अंदर कुछ न कुछ प्रोविजन्स हैं। विपक्ष जब भी इसको अपोज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वह कर नहीं पा रहे हैं। अब ये किस चीज़ को अपोज करेंगे? क्या आप किसानों, बागवानों, दिहाड़ीदारों-मज़दूरों का अपोज करेंगे या हमारे रेहड़ी-फड़ी वाले भाइयों को अपोज करेंगे? यह विपक्ष के लिए निराशाजनक हो सकता है और इसके लिए आपकी हताशा भी झलक रही है। अगर आप मीडिया वालों को देखेंगे तो वे भी इस बजट पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। विपक्ष का समर्थित मीडिया भी बजट पर बात नहीं कर रहा है और वे इधर-उधर की बात कर रहे हैं क्योंकि इस बजट में वे कुछ खोट नहीं निकल पा रहे हैं। अब मैं थोड़े विस्तार में आपको इसके बारे में बताता हूं।...(व्यवधान)। अगर आप मुख्य मंत्री जी का सामाजिक परिवेश देखें तो वह एक आम आदमी और साधारण परिवार से उठे व्यक्ति हैं और आज वे मुख्य मंत्री बने हैं। इन्हें एक आम परिवार का दुःख और दर्द पता है इसलिए मैं इस बजट को बड़े साफ़ शब्दों में कहना चाहूंगा कि यह एक आम आदमी के मुख्य मंत्री का आम आदमी के लिए बनाया हुआ बजट है। आप एक-एक करके देखिए कि

इस बजट में क्या है। इसका मेन हाईलाइट यह है कि यह किसानों, बागवानों, मजदूरों, कर्मचारियों, हमारी बहनों और हमारे युवाओं के लिए समर्थित बजट है। इसमें समाज के हर वर्ग के लिए कुछ-न-कुछ प्रावधान किया है। हमारे सामने विपक्ष के जो प्रोटेस्ट आ रहे थे और कैपिटल एक्सपेंडिचर और इन सब चीज़ोंके ऊपर बातचीत हो रही थी, इसको मैं आपको एक कहानी के स्वरूप में बताने की कोशिश करता हूं। एक संयुक्त परिवार था, उस परिवार में पिता जी बीमार पड़ गए और तबीयत बहुत खराब होने के कारण वह बिस्तर से उठ नहीं पा रहे थे। लोगों ने बड़े बेटे से कहा कि पिता जी का इलाज करवाने का दायित्व तुम्हारा है। बड़े बेटे ने पिता जी के सिरहाने बैठ कर कहा कि इन्हें गाना सुनना बहुत पसंद है। पिता जी का अच्छा उपचार करवाने के लिए उसने चम्बा, कांगड़ा तथा बिलासपुर से संगीतकार बुलाए परंतु उनके संगीत से वह ठीक नहीं हुए। तब बड़े बेटे ने

18.03.2025/1605/AG/PB/-3

कहा कि पिता जी को नाच देखने का भी बहुत शौक है। फिर उसने भंगड़ा,लुड्डी और नाटी वाले बुला लिए, वे महीनों भर नाचगान करते रहे परंतु पिता जी ठीक नहीं हुए। जब पिता जी कोमा में जाने लगे तब रिश्तेदारों ने बोला कि एक बार छोटे बेटे को बुलाकर देख लेते हैं शायद वह कुछ कर सके। जब छोटे बेटे ने देखा कि पिता जी बीमार पड़े हुए हैं उसने पिता जी को आई0जी0एम0सी0, शिमला ले आया। आई0जी0एम0सी0 में उनके टेस्ट करवाए, दवाई दिलवाई, उनको वेंटिलेटर पर डाला गया। जब वेंटिलेटर पर डाला तो धीरे धीरे दवाई के प्रभाव से पिता जी ठीक होना स्टार्ट हो गए। अब अगर मैं यह बोलूं कि यह पिता जी हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था है तो मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि बड़ा और छोटा बेटा कौन है। आपने हिमाचल की अर्थव्यवस्था को कोमा में डाल दिया है और अब जब छोटा बेटा उसको अस्पताल ले जाकर ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो ये कह रहे हैं कि अगर केंद्र मदद न करें तो पिता जी नहीं बचेंगे। इनकी यह बात बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताता हूं कि यह अर्थव्यवस्था कैसे लड़खड़ाई है। इस अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने की शुरूआत वर्ष 2017 में ही शुरू हो गई थी। पिता जी को पहले बीमारी कब लगी?

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

18.03.2025/1610/AS/AP/1

श्री भवानी सिंह पठानिया द्वारा जारी ....

पिता जी पहले बीमारी तब लगी जब 32000 करोड़ रुपया जी0एस0टी0 कपंनसेशन का 2017-18 में भारत सरकार ने शुरू कर दिया। अब बात यह है कि कुछ बच्चे लायक होते है, कुछ लायक नहीं होते। जब पैसा ज्यादा दिखा तो आपने ज्यादा पैसा बांटना शुरू कर दिया। इसके बाद 15 वें वित्त आयोग की आर0डी0जी0 की ग्रांट आ गई। उसमें लगभग 11 हज़ार 800 करोड़ रुपया पहले साल मिला, 10 हज़ार 500 करोड़ रुपया दूसरे साल मिला। अब हम सब यह बोल रहे है कि यह ग्रांट्स खत्म होनी थीं, यह जी0एस0टी0 कपंनसेशन खत्म होना था, आपको यह सब पहले दिन से पता था। अगर अच्छा बेटा होता, तो जिस समय पिता जी को जब नज़ला शुरू हुआ था अगर उस समय उसका उपचार करना शुरू कर देता तो शायद यह बिमारी कैंसर न बनती। यह सबको पता था कि ग्रांट्स कम आएगी। 11 हज़ार 400 करोड़ से यह ग्रांट्स कम होकर 3200 करोड़ रूपये आएगी, यह बात बच्चे-बच्चे को पता थी। जब आपको पता था उस समय आपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया? हमारा प्रश्न सिर्फ यह है कि 3 हज़ार 200 करोड़ का जी0एस0टी0 कपंनसेशन गायब होगा, इसको कवर करने के लिए आपने क्या किया? इसका कोई जवाब नहीं है। उसके बाद रिटॉरिकल सवाल-पे-सवाल आते है कि अच्छा यह तो होना ही था, पता ही था। आपको पता था लेकिन आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। एक्शन अब शुरू हुआ है। दो साल पहले जब हमारी सरकार बनी, माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी को मुख्य मंत्री का कार्यभार दिया गया। उसके बाद से आप देखिए कि सारे एक्शन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर हो रहे हैं, यह सभी एक्शन्स फिजूलखर्ची को कम करने के लिए हो रहे हैं और हमारे रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हो रहे हैं। इसकी पहली कड़ी 2

हज़ार 600 करोड़ रुपये का रेवेन्यू पिछले साल इस सरकार ने अर्जित किया है, पिछले साल के ऊपर। यह कैसे हुआ? रेवेन्यू में हज़ार करोड़ रुपया आया है, उसके बाद वैट में पैसा आया है, उसके बाद liquor vends की ऑक्शन में पैसा आया है, माइनिंग में पैसा आया है। 2 हज़ार 600 करोड़ का पैसा सरकार ने इनक्रिज़ किया है और इसको हम बढ़ाकर 5.50 से 6 हज़ार करोड़ रुपये तक लेकर जाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है और ऐसे ही फैसलों से लोगों को तकलीफ होती है। तकलीफ उसको होती है जो एक व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है और उस व्यवस्था को चूस के उससे अपना

18.03.2025/1610/AS/AP/2

मुनाफा ले रहा है। जब यह व्यवस्था बदलेगी, अब जैसे शराब के ठेके हैं। शराब के ठेकेदार हर साल आते थे, हर साल आकर पता नहीं क्या देते थे, लेकिन उनका वेंड 10 प्रतिशत रिन्यू हो जाता था। किसी को कोई समस्या नहीं थी। जब ऑक्शन हुई तो भुक्तभोगी जो थें, चिल्लाएंगे तो वह ही। इस बजट से आप अगर देखे कौन लोग प्रसन्न नहीं हैं on the street, विधान सभा क्षेत्र में भी हो सकता है कि चिट्टे का डीलर पसंद नहीं है, हो सकता है शराब का माफियां प्रसन्न नहीं है या हो सकता है कि अवैध खनन वाला वह प्रसन्न नहीं है। लेकिन आप किसानों, बागवानों, रेड़ी-फड़ी वाले मजदूर, दिहाड़ी वाले मजदूरों से बात करके तो देखो कि क्या आप इस बजट से खुश है या नहीं। मैं आपको बता दूं यह जो मैंने अभी नाम लिये हैं यह 90 प्रतिशत हमारा हिमाचल है और यह इस बजट से न केवल प्रसन्न है बल्कि प्रदेश सरकार को यह सपोर्ट भी कर रहे हैं और आगे भी सरकार को सपोर्ट करते रहेंगे। इसके बाद आप यह देखिए, बजट एक विज़न डॉक्यूमेंट नहीं है, यह एक statement of accounts है। वह statements of accounts को प्रजेंट किया है, यह कोई पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं होता। इस करके अगर वहां पर जिक्र न भी हो तो इसका मतलब यह नहीं कि विकास के कार्य रूक गये हैं। इसके बाद दूसरी बात मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आज से दो साल पहले जो बजट नेता प्रतिपक्ष ने पेश किया था। उस बजट में भी एक छोटी सी कहानी मैंने सुनाई थी। मैंने यह कहा था कि जब दो राजाओं की आपस में लड़ाई होती है तो उसमें एक राजा दूसरे के राज्य को घेर लेता है और जो राज्य घिरा हुआ होता है

उसको थोड़े दिनों बाद पता चल जाता है कि हमारा अब ज्यादा दाना-पानी बचा नहीं है। तो वह क्या करते थे कि चोर दरवाजे से अपनी सेना को लेकर भाग जाते थे। भागने से पहले एक काम और करते थे कि वहां पर जो अन्न के बचे हुए भंडारण होते थे, उनको आग लगा देते थे। पानी के कुओं में जहर डाल देते थे। उस समय मैंने श्री जय राम ठाकुर जी को यही बोला था कि आपकी सरकार जाने वाली है, आप जा तो रहे हो, लेकिन यह जो यह बजट आपने पेश किया है यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपने हमारे पानी के कुओं में ज़हर डाल दिया है और जो अन्न के थोड़े- बहुत भंडारण थे आपने उनको आग लगा दी है। क्योंकि आप जाते-जाते 1100 संस्थान खोल के जा रहे हो।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी......

18.03.2025/1615/AT/ए0एस0/1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी---

तो आप क्या करके जा रहे हो? आप जो एक हृष्टपुष्ट पौधा जो हिमाचल प्रदेश में हम लगाने की सोच रहे हैं, उसकी जड़ों में आप तेल डाल रहे हैं। बोलने का मतलब यह है कि लगभग 8000 करोड़ रुपये का आर0डी0जी0 ग्रांट की शॉर्ट फॉल, उसके बाद 3200 करोड़ की आपकी जी0एस0टी0 कंपनसेशन की शॉर्टफॉल बनती है। हमने ओ0पी0एस0 लागू किया। ओ0पी0एस0 लागू करने के बाद 1600 करोड़ हमारी लैंडिंग जो बॉरोइंग लिमिट है, वह काम कर दी । टोटल बनता है 14000 करोड़ । उसके बाद प्राकृतिक आपदा जब आई तो 4500 करोड़ हमारी जेब से एडिशनल निकल गया जो काउंटेड फॉर नहीं था। इसके बाद जब केंद्र की टीम आई और उन्होंने आकलन किया 10000 करोड़ का उसमें से आज फूटी कौड़ी भी हमको नहीं मिली है। टोटल अगर आप देख तो 25000-26000 करोड़ का एक होल बना हुआ है और इस होल में अगर आप देखें तो जब हम बात करते हैं कि केंद्र सरकार के साथ इसके बारे में बात की जाए, आर0डी0जी0 ग्रांट ठीक है अभी वापस नहीं आ सकती, जी0एस0टी0 कंपनसेशन के ऊपर डेफिनेटली बात की जा सकती है लेकिन जो हमारा पी0डी0एन0ए0 का पैसा है, जो 10,000 करोड़ पी0डी0एन0ए0

का पैसा है। हम आवाज उठा रहे हैं और हमारे विपक्ष के नेताओं को भी आवाज उठानी चाहिए और 7 एम0पी0 जो हमने चुन के भेजे हैं उनको भी आवाज उठानी चाहिए। यह पिछली बार भी मैंने बोला था और आज से कोई चार दिन पहले मेरे ट्वीटर पर एक पॉपअप आया1 उसमें मैंने देखा कि माननीय सांसद, मंडी लोकसभा में बोल रही है तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने सोचा कि शायद वह बी.डी.एन.ए. का पैसा मांगेगी पर उन्होंने जो सवाल वहां पर उठाया वह सवाल यह था की मंडी में लाइट नहीं आती तो कृपया आप उसकी लाइट का कुछ कीजिए। अब मेरे मन में सवाल यह है की लाइट तो हमारा एक्सिअन भी ठीक कर देता है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी के पास जाने की क्या जरूरत है। उसके बाद जो उन्होंने बोला तो उससे तो मेरे और भी चक्षु खुल गए । उन्होंने बोला कि तीन हमारी कांस्टीट्यूएंसी ऐसी हैं, जहां बिजली की समस्या है पहली सिराज, दूसरी आनी और तीसरी बंजार। अब बोलने का मतलब है कि 27 साल से माननीय नेता प्रतिपक्ष वहां के एम0एलए0 हैं। एक बार मंत्री भी रहे, एक बार मुख्यमंत्री भी रहे। 27 साल में क्या वहां की

18.03.2025/1615/AT/ए0एस0/2

बिजली की समस्या ठीक नहीं हो पाई? अगर वे नहीं कर पाए तो हम कहां से करेंगे? एम.पी. जो सवाल वहां पर उठा रहे हैं, वह मुद्दा विहीन सवाल है जो हिमाचल के हित में नहीं है। हिमाचल के हित के सवालों को लोकसभा में पहुंचाने के लिए उनको लोगों ने चुनकर भेजा है। मेरी इस माननीय सदन के माध्यम से रिक्वेस्ट कि आप भी एक बार जो हमारे पी0डी0एन0ए0 का पैसा है और बाकी जो हमारी जी0एस0टी0 कंपन्सेशन जो हमारी फंसी हुई है, उसके लिए आप एक बार अपने रिस्पेक्टिव एम0पीज़0 को सभी ने नए कोट सिलवा कर मदद की थी कैंपेनिंग के समय पर, आप उनको कहिए कि हिमाचल के हित की बात अपनी लोकसभा में उठाएं। इसके बाद मैं बजट पर आऊंगा। बजट में बाकी सारी चीजों के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तीन चीजों के ऊपर बात करूंगा पहले है

किसान। इस सदन में किसानों के ऊपर इतनी ज्यादा चर्चा आज से पहले अपने 3 साल में मैंने नहीं देखी। हम चिट्टे की बात करते हैं, हम खनन की बात करते हैं, हम कर्मचारियों की बात करते हैं, किसान की बात हम नहीं करते। किसान हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा प्रताड़ित वर्ग है और मैं प्रताड़ित इसलिए बोलूंगा क्योंकि जो किसान का उत्पाद है, वह तो एक लैवल पर जाकर रुक गया। आप एक लैवल के ऊपर उसको पैसा नहीं देते लेकिन उसकी जो जरूरत की चीज हैं, उनका जो रेट है, उनका जो भाव है वह आसमान को छू रहा है। कबीर जी ने जो किसान को देखकर ही दोहा लिखा था कि चलती चक्की देख के दिए कबीरा रोये, दो पाटन के बीच में बाकी बचा न कोये। ऊपर आपकी सरकार की पॉलिसीज है जो आपके एम0एस0पी0को बढ़ने नहीं देती और दूसरी तरफ आपकी जो महंगाई है, वह किसान को मारे जा रही है । मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। वर्ष 1980 के अंदर सोने का भाव 1350 रुपये तोला था आज 85 से 90,000 रुपये तोला है। आप ट्रैक्टर देखें, आईशर का ट्रैक्टर वर्ष 1980 में ₹10000 का आता था आज वही ट्रैक्टर 6 लाख रुपए का है यानी 60 गुना वृद्धि हुई है। डीजल दिल्ली में 1.40 रुपये पैसे प्रति लीटर था आज वह लगभग 90 रुपए प्रति लीटर है लगभग 80% गुना इसमें वृद्धि आई है लेकिन जो व्हसीट का एम.एस.पी. है, वह एक क्विंटल का 122 रुपए हुआ करता था, आज वह 2200 रुपया है। किसान की जो उत्पाद है वह 20 गुणा बढ़ा और जो चीजों के ऊपर वह पैसा खर्च करता है वह बढ़ा 80, 90 और 100 गुणा। अब आप मुझे यह बात बताएं कि किसान की आय अगर नहीं बढ़ेगी तो उसने क्या ठेका ले

18.03.2025/1615/AT/ए0एस0/3

रखा है कि आपको वह गेहूं उस रेट पर बचेगा जिस रेट पर आपके बच्चे 55 रुपए की ब्रैड खा पाए और उसका बेटा भूखा सोये? यह कहां का न्याय है? किसान की आय को बढ़ाने के लिए मुझे नहीं लगता इससे बड़ा स्टैप आप कोई ले सकते हैं जो कि अभी मुख्यमंत्री ने लिया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्राकृतिक खेती के थ्रू अगर आप मक्की बेचते हैं तो वह 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की है और अगर आप कनक बेचते हैं तो 40 रुपए से बढ़ाकर 60

रुपये की है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपका नॉर्मल कनक या नॉर्मल व्हीट का है, वह 2200 रुपए प्रति क्विंटल है। इस हिसाब से वो 6000 रुपये प्रति क्विंटल बन जाएगा अगर

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी ....

18.03.2025/1620/MD/एचके/1

श्री भवानी सिंह पठानिया ---जारी

आप मक्की बेचते हैं तो वह 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की है। अगर आप कनक बेचते हैं तो 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये की है। नॉमर्ल कनक और मक्की का मिनिमम सपोर्ट प्राइज 2200 रुपये प्रति क्विंटल है। इस हिसाब से वह 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल बन जाएगा। अगर आपकी पैदावार 20 प्रतिशत भी गिरती है तो आपकी इन्कम 250 प्रतिशत बढ़ रही है। मैं सभी किसान भाइयों से यह प्रार्थना करूंगा कि आप प्राकृतिक खेती के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप प्रोडक्शन को छोड़िए और अपनी जेब के अंदर पैसा डालिए क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा होगा आप तभी अपने परिवार का भरण-पोषण कर पाएंगे। दूसरों को सस्ता अनाज देने के चक्कर में आपको अपने परिवारों को बर्बाद नहीं करना है। दूसरी चीज हल्दी है, हल्दी के ऊपर सरकार ने 90 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से सपोर्ट प्राइज लाँच की है। इसका मतलब यह है कि किसान को 10 क्विंटल हल्दी के ऊपर लगभग 90 हजार रुपये की आय होगी। हिमाचल प्रदेश जैसे परिवेश के एक एकड़ के अंदर एक साल में प्रोडक्टीविटी 8 से 10 टन के आस-पास की है। हल्दी उन एरिया के लिए सूटेबल है जहां पर बंदरों और अवारा पशुओं की वजह से बर्बादी हो चुकी है तथा लोग फसल बेचना बंद कर चुके हैं। आपसे यही प्रार्थना है और कृषि मंत्री को भी मैं बोलूंगा कि इस स्कीम को हम जितनी जल्दी धरातल पर ले जाएं उतनी जल्दी किसानों के हित की बात हम कर पाएंगे। तीसरी चीज ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दूध के रेट से संबंधित है। गाय के दूध और भैंस के दूध में 6 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। आज सरकार भैंस

के दूध का 61 रुपये प्रति लीटर दे रही है। अगर आप चिलिंग प्लांट से दो-अढाई किलो मीटर दूर रहते हैं तो सरकार आपको 2 रुपये प्रति लीटर रेट ऑफ कॉस्ट भी दे रही है। सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गैल्वेनाईज करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अगर इसके लिए भी आप ताली नहीं बजा सकते तो पता नहीं किस के लिए बजाएंगे। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र,राजस्थान, बिहार और यू0पी0 के अंदर किसान आत्महत्या करते हैं और वे आत्महत्या इसलिए करते हैं क्योंकि वे कर्ज़ में डूबे रहते हैं। उनकी सरकारें कुछ

18.03.2025/1620/MD/एचके/2

कर रही हैं या नहीं कर रही, वह मुझे नहीं पता। लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने छोटे और मीडियम किसान, जिसका 3 लाख रुपये तक का क़र्ज है उस के लिए इस बजट में वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी प्रस्तुत की गई है। वन टाइम सैटलमैंट में यह है कि आपके मूलधन के ऊपर जो भी ब्याज बना है, उस ब्याज का 50 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। यह उन सब छोटे किसानों के लिए एक शॉर्ट इन द आर्म है जिन्होंने लोन तो ले लिया और किसान क्रेडिट कार्ड बना लिए लेकिन आज वे इस लोन को पे करने में असमर्थ हैं, यह सरकार द्वारा बहुत बड़ा कदम लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे रेहड़ी-फड़ी वाले भाइयों के लिए भी लोन में वन टाइम पॉलिसी लाई गई है। अगर आप कर्ज़ के चंगुल में फंस चुके हैं, अगर आपको यह लग रहा है कि आपको कोई ड्रास्टिक कदम उठाना पड़ेगा तो उसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि सरकार आपके साथ खड़ी है और सरकार वन टाइम सैटलमैंट पॉलिसी के तहत आपके इंटरस्ट का 50 प्रतिशत बैंक को अपनी जेब से अदा करेगी। इसके बाद हमारा जो खेत संरक्षण योजना के अंदर फैंसिंग हो वह चाहे इलैक्ट्रिक फैंसिग या कंटीली वायर हो या फिर नॉर्मल जाला हो। इसके लिए बजट में प्रावधन किया गया है। फिशरीज में एक बहुत बडा ऐतिहासिक स्टैप लिया गया है कि जो सरकार के जलाशय सोसायटी ओपरेट

करती हैं। उसमें से प्रोड्यूस का 15 प्रतिशत रॉयल्टी सरकार को देती है। इसका मतलब यह है कि असली मछुआरे को पैसा कम मिलता है।

खेत संरक्षण योजना के अंतर्गत आपकी चाहे इलैक्ट्रिक फैंसिंग की बात की जाए या कंटीली वायर या नॉर्मल जाले की बात की जाए इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है। जलाशय में 15 प्रतिशत रॉयल्टी को घटाकर साढ़े सात प्रतिशत कर दिया गया है। इसका मतलब अब मछुआरे की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा और वह भी अपने जीवन को ज्यादा समृद्धशाली बना सकता है।

इसके अतिरिक्त ग्रीन हिमाचल के निर्माण हेतु ईको-सिस्टम के अंतर्गत जो 78 साइट्स ऑक्शन हो रही हैं उन 78 साइट्स से अगले तीन-चार वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व आने वाला है जोकि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। ईको टूरिज्म

18.03.2025/1620/MD/एचके/3

ईकोलॉजी व पर्यावरण को प्रोटैक्ट करने के साथ-साथ गांवों में रोज़गार के अवसरों को भी बढ़ाता है। सरकार ने ई-टैक्सी और ई-रिक्शा के अंतर्गत 40 प्रतिशत की सब्सिडी अनाउंस की है। अगर कोई भी हमारे बेरोज़गार भाई ई-टैक्सी, ई-बस या ई-रिक्शा चलाना चाहते हैं तो सरकार उनको 40 प्रतिशत सब्सिडी सीधी-सीधी वहन करेगी। इसके अलावा होम स्टे के अंतर्गत अगर हमारा कोई भाई या बहन होम स्टे चलाना चाहते हैं तो उसके लिए बैंक से लोन लेने पर उसके ऊपर 4 व 5 प्रतिशत सबवैंशन स्कीम उपलब्ध है।

श्रीमती के एस द्वारा जारी

18.03.2025/1625/केएस/एचके/1

श्री भवानी सिंह पठानिया जारी---

इसका मतलब यह है कि अगर आपका लोन 9 प्रतिशत पर है तो आपको सिर्फ 5 प्रतिशत पे करना है, बाकी 4 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। इसके अलावा ई-चार्जिंग स्टेशन्ज़ आदि चीजें ऑलरेडी बजट में डाल दी हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि ध्वनी प्रदूषण के बारे में भी आपको कदम उठाना चाहिए। इसके लिए सारे क्लॉज़ हमारे पास बने हुए हैं। ध्वनी प्रदूषण में मेरा सबसे बड़ा इश्यू प्रैशर हॉर्न से है। अगर आप रिमोट एरिया टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो देखिए कि अगर एक सुन्दर सी जगह पर आपने एक बड़ा अच्छा होम स्टे बनाया लेकिन वहां से रोज़ के पांच-पांच टिप्पर गुज़र रहे हैं और जब वे अपना प्रैशर हॉर्न बजाते हुए जाते हैं तो मेरे हिसाब से जिस टूरिस्ट ने वहां पांच दिन रहना होगा, दो दिन के बाद वह अपना बोरिया-बिस्तर उठाएगा और चला जाएगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप कीजिए।

श्री भवानी सिंह पठानिया : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एन0जी0टी0 की तरफ से 10 हजार रुपये की पैनल्टी है जो कि आप लगाना शुरू करें। कृपया डी0जी0पी0 साहब और बाकी सम्बन्धित अधिकारियों को कहकर इन प्रैशर हॉर्न वालों के चालान करवाएं। इससे किसी गरीब के पेट पर लात नहीं पड़ेगी। हमारे प्राइवेट बस ऑप्रेटर्ज़, टिप्पर वाले और जितने भी हमारे बड़े वाहन वाले लोग हैं, उनके लिए यह प्रावधान हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी से उन्हीं के नेताओं की बात सुनने के बाद बालूंगा, सत्ती जी ने आज से कोई दो सैशन पहले कहा था, हमको सलाह दी थी कि यह सुखविन्दर सिंह सुक्खू है, इतनी जल्दी कुर्सी नहीं छोड़ता। जब ये एन0एस0यू0आई0 के प्रधान बने तो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया। उसके बाद जब ये यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने, फिर टेन्योर के हिसाब से अपना रिकॉर्ड कायम किया। जब ये एच0पी0सी0सी0 के अध्यक्ष बने तब ये छः साल के टेन्योर पर रहे और इनको कोई हटा नहीं पाया। अब ये मुख्य मंत्री बने हैं तो इनको भी हटाने की कोई सोचना मत। ये बड़ी लम्बी पारी खेलेंगे। आप इसको दूसरा या तीसरा बजट मानकर मत चलो, यह इस टेन्योर का तीसरा बजट है लेकिन अगले टेन्योर का पहला बजट भी इनको ही प्रस्तुत करना है।

18.03.2025/1625/केएस/एचके/2

आखिर में उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर कहना चाहूंगा कि :-

बस कुछ देर की खामोशी थी, फिर कानों में शोर आया था,

तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

18.03.2025/1625/केएस/एचके/3

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्या श्रीमती रीना कश्यप जी भाग लेंगी।

श्रीमती रीना कश्यप : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान पर चर्चा करने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कल, यानी 17 मार्च, 2025 को माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत किया। ऐसा लग रहा था कि सभी चीजें, जिनका वर्णन पहले बजट में हुआ, दूसरे बजट में हुआ और जितनी चीजों का उनमें वर्णन हुआ अब तीसरे बजट में भी वही वर्णन नज़र आ रहा है। मैं तो कहना चाहूंगी कि यह बजट सरकार का तीसरा बजट और तीसरी बार रिपीट किया हुआ बजट है। यह पूरे प्रदेश की जनता के लिए निराशाजनक बजट है। वर्ष 2022 में जो आपने वायदे किए थे, दस गारंटियां दी थीं, इस बजट में उसका बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। इस बजट से प्रत्येक वर्ग, वह चाहे किसान वर्ग हो, महिला वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो या युवा वर्ग हो, कहीं न कहीं एक उम्मीद थी कि यह बजट राहत भरा बजट होगा मगर यहां तो उल्टा ही हुआ। यह राहत भरा नहीं बल्कि आफ़त भरा बजट सामने आया है। यह बजट प्रदेश की जनता के लिए शून्य के समान है। वर्ष 2022 के दौरान जब चुनाव हुआ तो आपने दस गारंटियां दी थीं। एक-एक करके आपने कहा था कि हम यह करेंगे, वह करेंगे लेकिन जब मैंने यह बजट पढ़ा, इसमें दस गारंटियों का बिल्कुल भी ज़िक्र नहीं है। 10 गारंटियों में से जो एक महत्वपूर्ण गारंटी है,

---

जिस पर मुझे आज इस सदन में कहना है वह महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी है। मैं महिलाओं की बात करुंगी तो मैं कहना चाहूंगी कि :-

एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है,

तुमने देखा नहीं आंसुओं का समंदर होना।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.03.2025/1630/av/YK/1

श्रीमती रीना कश्यप-------- जारी

आप इसको इस बात से समझ सकते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि आपकी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये के नाम पर एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन-तीन बार ठगा है और 1500 रुपये की राशि देने के नाम पर आपने वोटों को लूटा है। वर्ष 2022 में जब विधान सभा के चुनाव हुए तो आपने प्रदेश की महिलाओं को कहा कि सभी 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500-1500 रुपये मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी की सरकार के सत्ता में आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये की पेंशन देने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आपने महिलाओं के साथ झूठ बोला है। ...(व्यवधान) अभी आप लोग मेरी बात सुनिए। मैं बताती हूं कि आपने दूसरी बार झूठ कब बोला। ...(व्यवधान) आप लोगों को महिलाओं के श्राप पड़ने वाले हैं। आपने दूसरी बार लोक सभा के चुनाव के दौरान झूठ बोला। उस समय आपने प्रदेश की सभी महिलाओं के फॉर्म भरें। मैं तो लोक मित्र केंद्रों और बी0डी0ओ0 ऑफिस में महिलाओं का रश देखकर हैरान हो गई। मैंने जब उनसे पूछा कि आप लोग यहां पर क्यों खडी हैं तो उन्होंने कहा कि हमें सरकार ने कहा है कि सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये की पेंशन मिलेगी। जब मैंने पूछा कि यह किसने कहा तो उन्होंने कहा कि विधायिका जी, आपने नहीं सुना? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस प्रकार कहा है कि अगर सास, ननद, देवरानी और

जेठानी इत्यादि परिवार की सभी महिलाओं को 1500-1500 रुपये की राशि मिलेगी। अब तीसरी बार और महिलाओं को ठगने के उद्देश्य से सरकार का एक नया फ़रमान आया है। क्योंकि पिछले कल बजट में कहा गया कि प्रदेश में 21 वर्ष की आयु पूरी करने वाली बेटियों को ही पेंशन मिलेगी। मैं तो इस बात से हैरान हूं क्योंकि इस 21 वर्ष वाले नये फ़रमान का कोई सिर और पैर नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई वर्णन ही नहीं है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि जो 18 वर्ष से 21 वर्ष के बीच की आयु वाली हमारी प्रदेश की बेटियां हैं, उन बेटियों के साथ क्या होगा? मेरे हिसाब से सरकार ने उन बेटियों के साथ अन्याय किया है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आपने जो पेंशन हेतु 21 वर्ष की आयु सीमा रखी है तो 18 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु वर्ग की बेटियों के साथ आपने अन्याय क्यों किया? मैं तो यह कहना

18.03.2025/1630/av/YK/2

चाहती हूं कि आपने प्रदेश की बेटियों को आयु के हिसाब से बांट दिया है। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के दौरान घोषणा की थी कि 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही प्रदेश की बेटियों को हर महीने 1500 रुपये की राशि मिलेगी। इस प्रकार से मेरे हिसाब से प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के साथ गलत हुआ है। यहां पर पहले भी माननीय सदस्यों की तरफ से कहा गया है कि प्रदेश की महिलाओं और बेटियों के साथ इस प्रकार के 'चरण' की नीति न अपनाएं। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आपको प्रदेश की महिलाओं के साथ किए गए वायदे को निभाना पड़ेगा। ..(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए :-

मत भूलो ए सत्ता वालों, यह केवल हिमाचल की नारी की शक्ति है,
जो आपको सत्ता दिला सकती है,
और ठगा हुआ महसूस होने पर आपको सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है।
यह हिमाचल की नारी की शक्ति है।

इसका जीता-जागता उदाहरण अभी पीछे लोक सभा का चुनाव है :-

क्योंकि नारी अब अबला नहीं, सबला है।

सरकार की झूठी गारंटियों का अब बजने वाला तबला है।

इसलिए जो वायदा किया, वह आपको निभाना पड़ेगा। ..(व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप तो मेरे मायके से हैं। मैं अभी आगे आपकी भी तारीफ करूंगी।

इस बजट में महिलाओं के उत्थान और उनके जीवन-स्तर को सुधारने के लिए क्या-क्या प्रयत्न किए गए हैं, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है।

एन0एस0 **द्वारा जारी**

18-03-2025/1635/NS-YK/1

श्रीमती रीना कश्यप ----- जारी

मैं पूर्व मुख्य मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जब भाजपा की सरकार थी तो महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अनेकों कार्य किए गए, अनकों योजनाएं तैयार की गईं जिनका सीधा लाभ महिलाओं और बेटियों को हुआ है। मैं यहां पर कुछेक योजनाओं को बताना चाहूंगी। शगुन योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी जिसके माध्यम से बी0पी0एल0 परिवार की बेटी की शादी के लिए 31,000 रुपये दिये जाते थे मगर अब यह योजना बंद है और इसका लाभ बेटियों को नहीं मिलता है। जैसे ही आप सत्ता में आए आपने यह योजना बंद की है और यह आपने बेटियों के साथ बहुत गलत किया है। इसी प्रकार से गृहिणी सुविधा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना थी और इसका लाभ भी हिमाचल की बहुत सी गरीब बहनों को हुआ है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, बेटी है अनमोल योजना और बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधा महिलाओं और बेटियों को मिला है। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए जब आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार थी तो मैं अपने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र का एक उदाहरण देना चाहूंगी। उन्होंने 'शी हाट' के रूप में एक बहुत बड़ा तोहफा महिलाओं को दिया है। जिसके कारण आज महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हैं। मैं कहना चाहूंगी कि उस समय हमारे उपायुक्त श्री आर0के0 पुर्थी हुआ करते थे और उनका बहुत

ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं तो सरकार को कहना चाहूंगी कि जब इतने अच्छे अधिकारी आपके पास हैं तो आप उनसे जरूर सलाह लें और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करें। आज के समय में 'शी हाट' पूरे हिमाचल प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन मुझे इस बजट में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया कि महिलाओं के उत्थान के लिए आपने कुछ किया हो। इसी प्रकार मैं बात करना चाहूंगी कि इस बजट में जिस प्रकार यहां पर मान्य मुख्यमंत्री जी द्वारा पढ़ा जा रहा था कि मानदेय में वृद्धि की गई। परंतु मुझे इस बात का दुःख है कि आशा वर्कर के मानदेय में केवल 300 रुपये की ही वृद्धि हुई है जबकि आशा वर्कर सुबह से शाम तक फील्ड में डोर टू डोर कार्य करती है और बहुत ईमानदारी से अपना कार्य करती है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि उनके मानदेय को और बढ़ाया जाए ताकि उनके हौंसले बढ़े और वे अपना काम ईमानदारी से करें।

18-03-2025/1635/NS-YK/2

इसके अलावा जो हमारे मल्टी टास्क वर्कर्ज, चाहे वे जल शक्ति विभाग या अन्य विभागों में हैं तो उनके मानदेय में भी 500 रुपये की वृद्धि की गई है। उनको कुल 5500 रुपये मिलते हैं। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि यह बहुत कम है। उनके मानदेय में कम से कम 5,000 रुपये की वृद्धि होनी चाहिए थी ताकि उन्हें एक सम्मानजनक राशि मिलती। इसमें भी आपने इस तरह के कदम नहीं उठाए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से शिक्षा विभाग के स्कूलों में 6,717 पार्ट टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज सेवाएं दे रहे हैं और इस बजट में उनके भी मानदेय में वृद्धि नहीं की गई है। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत अच्छे हैं और जो भी इनके पास जाता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं आता है। मगर पहली बार ऐसा हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। आप जरूर इनके बारे में सोचेंगे और जो भी उनकी दिक्कत है आप उसको सॉल्व करेंगे तथा उनके मानदेय में बढ़ोतरी करेंगे। इस दस्तावेज के पेज नम्बर-25 में उल्लेख किया गया है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत से मंदिरों को करोड़ों रुपये की राशि दी गई। मेरा निवेदन रहेगा और मैं पच्छाद

विधान सभा क्षेत्र की बात करती हूं। मैं सिरमौर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के शाया मंदिर और श्रीगुल महाराज की बात करूंगी तथा पर्यटन की दृष्टि से हम इस मंदिर को डवलप कर सकते हैं। मेरा इसके लिए आपसे निवेदन रहेगा कि इस पर विचार किया जाए। इसी प्रकार से सराहां क्षेत्र में चुड़ेश्वर महादेव मंदिर है और यह बहुत सुंदर मंदिर है । यहां पर दूर दूर से लोग आते हैं और इसे भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर सकते हैं।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

18.03.2025/1640/RKS/ag-1

श्रीमती रीना कश्यप जारी.......

मैं सबसे पहले हमारे पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने "नई राहें, नई मंजिलें योजना" के तहत शिरगुल महाराज मंदिर के लिए 25 लाख रुपये और भूरेश्वर महाराज मंदिर के सौंदर्यकरण के लिए 35 लाख रुपये की राशि जारी की थी। उनके इस योगदान के लिए मैं इनका धन्यवाद करती हूं। मेरी सरकार से भी यह प्रार्थना है कि धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास के लिए पर्याप्त राशि जारी की जाए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पहले बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त माननीय मंत्री जी ने मुझे नारग में स्वास्थ्य संस्थान स्थापित करने का आश्वासन दिया था। यह संस्थान मेरा और मंत्री जी का साझा सपना है और मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इसे जल्द-से-जल्द साकार किया जाए ताकि नारग क्षेत्र की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आप हमारे विधान सभा क्षेत्र से होकर गुजरते हैं और आपको मालूम होगा कि पूर्व सरकार ने सरांह अस्पताल को 100 बिस्तरीय करने की घोषणा की थी। लेकिन जैसे ही प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई उस

नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया गया। यह स्वास्थ्य संस्थान 30-40 पंचायतों के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि उस नोटिफिकेशन को पुनः बहाल किया जाए ताकि वहां के लोग सोलन या शिमला न जाकर अपने उपचार के लिए सरांह अस्पताल का लाभ उठा सकें। ...(व्यवधान) यदि हम पी0एच0सी0, ढंगयार की बात करें तो वहां काफी समय से डॉक्टर का पद रिक्त पड़ा है। पी0एच0सी0, कोटीबधोग, रासूमांदर क्षेत्र में पड़ती है। यह संस्थान 5-6 पंचायतों को कवर करता है लेकिन वहां भी डॉक्टर के पद खाली पड़े हैं। मेरा निवेदन है कि इन रिक्त पदों को भी शीघ्र भरा जाए। माननीय मंत्री जी, आपने मुझे मेरे विधान सभा प्रश्न के माध्यम से और विधान सभा के बाहर भी यह आश्वासन दिया है कि आप हमारी स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को सुलझाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। इस बजट में लोक निर्माण विभाग की कई योजनाओं का जिक्र किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रदेश सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अच्छी सड़कों और पुलों का निर्माण करना है। परंतु यदि मैं अपनी पच्छाद विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां पिछले दो वर्षों से सड़क निर्माण संबंधी कोई नया कार्य नहीं हुआ है। सरांह-चंडीगढ़ सड़क हमारे क्षेत्र की

18.03.2025/1640/RKS/ag-2

महत्वपूर्ण सड़क है। कुछ महीनों पहले जब माननीय मुख्य मंत्री जी सरांह दौरे पर आए थे तो उन्होंने इस सड़क को डबल लेन करने की घोषणा की थी। मैंने इस सड़क को अपनी विधायक प्राथमिकता में भी शामिल किया है लेकिन हमारी नाबार्ड की लिमिट बहुत कम होने के कारण इस परियोजना को लागू करना संभव नहीं हो पा रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस परियोजना को किसी अन्य मद में शामिल किया जाए ताकि यह कार्य सुनिश्चित हो सके। आप इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास भेजने की भी कृपा करें। साथ ही मैं एक अन्य महत्वपूर्ण सड़क, सोलंग-मिनस रोड की बात करना चाहूंगी। उपाध्यक्ष महोदय, यह सड़क आपके निर्वाचन क्षेत्र से होकर भी गुजरती है। यह सड़क राजगढ़ होते हुए नोहराधार से आगे जाती है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

18.03.2025/1645/बी.एस./ए जी/-1

श्रीमती रीना कश्यप जारी...

आपसे भी निवेदन रहेगा कि इस महत्वपूर्ण रोड, जिसके लिए काफी समय से डिमांड थी कि इसे डबल लेन किया जाए।

श्री विपिन सिंह परमार : उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर चर्चा चली है और यहां पर कोई भी सुनने वाला नहीं है।

श्रीमती रीना कश्यप : यह बिल्कुल सही है कि यहां पर केवल दो ही मंत्री बैठे हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्रीमती रीना कश्यप: उपाध्यक्ष महोदय, आप तो मेरी बात सुन ही रहे हैं। इसी प्रकार में कहना चाहूंगी कि जो नैना टिक्कर-ढंगयार सड़क है इसे मैंने अपनी विधायक प्राथमिता में भी डाला है और मैं चाहती हूं कि इसकी डी0पी0आर0 भी जल्दी बन करके तैयार हो। आप कृपया, ऐसे विभाग को अदेश दें। उसी तरह से नैना टिक्कर भिंडोबाग और ढमूह-सिलांजी ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी सड़के हैं और ये सड़कें हमने विधायक प्राथमिकता में डाली हैं। इनकी डी0पी0आर0 जल्दी-से-जल्दी तैयार हों। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सड़कों में सुधार हो, यह आपकी भी प्राथमिता है और हमारी भी प्राथमिकता है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप पच्छाद की तरफ विशेष ध्यान दें ताकि पच्छा की सड़कों में सुधार हो।

पृष्ठ न0 9 में इस बजट में जो वर्णन किया गया है कि नगर पंचायत राजगढ़ के लिए सिवरेज योजना का कार्य वर्ष 2025-26 में शुरू हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगी कि इस योजना को वर्ष 2021-22 में पहले ही आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने 22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे परंतु दुःख की बात है कि अभी तक यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है। यह

कार्य बजट बुक में शामिल है तो मेरा निवेदन रहेगा कि इस कार्य को जल्दी-से-जल्दी शुरू किया जाए। अंत में मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी पता नहीं जो भी मैंने बजट पर बोला मुझे सच में लग रहा है कि यहां पर न उप-मुख्य मंत्री जी हैं और न अन्य मंत्री हैं। आप सिरमौर के हैं, आप ही मेरी बात सुन रहे हैं।

उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, यहां पर बैंठे हैं।

18.03.2025/1645/बी.एस./ए जी/-2

श्रीमती रीना कश्यप : महोदय, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि यह सारा बजट झूठा है और यह सरकार मित्रों की सरकार है। वह इसलिए क्योंकि फोरेस्ट गार्ड की जगह वन मित्र, नर्स की जगह रोगी मित्र और टीचर की जगह गेस्ट मित्र, सारे मित्र सैट तो हम कह सकते हैं कि यह सरकार मित्रों की सरकार है। अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि यह बजट हर वर्ग के लिए निराशा जनक और दिशाहीन है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन नहीं कर सकती। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत, जय हिमाचल।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भी धन्यवाद। आपको अग्नि शमन केन्द्र दिया है कम-से-कम उसका धन्यवाद तो कर देते। अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी भाग लेंगे।

श्री किशोरी लाल : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 मार्च, 2025 को हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी ने 58,514 करोड़ रुपये का बजट अनुमान इस सदन में पेश किया। बजट के समर्थन में चर्चा करने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद। बजट सरकार का आइना है, बजट विकासोन्मुखी, हर वर्ग को राहत देने वाला, नौजवानों को रोजगार देने वाला, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला सभी वर्गों का सर्वांगीण विकास और उनके जीवन को सुरमयी बनाने वाला कर मुक्त यहां पर पेश किया गया। इसके लिए मैं

आदरणीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। यहां बड़ी-बड़ी बातें हमारे सामने वाले साथी कर रहे थे। मैं इन्हें उस वक्त की बातें याद दिलाना चाहता हूं

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

18.03.2025/1650/DT/AS-1

श्री किशोरी लाल जारी...

पंजाब में 1966 से पहले लोगों की जो हालत थी वह हालत मैं बयान करना चाहता हूं। केवल बैजनाथ-पठानकोट और बैजनाथ से मंडी जो एक नेरो सड़क थी इस सड़क में जब कोई गाड़ी आती थी तो एक गाड़ी जब गंतव्य में पहुचती थी उसके बाद दूसरी गाड़ी जाती थी। गांव में सड़कें नहीं थी। पीने के पानी की योजनाएं नहीं थी। बिजली नहीं थी। उस समय कोई व्यवस्था नहीं थी। पूर्णरूप से जंगलराज था। 1966 के बाद हमारा कांगड़ा क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मिला और तत्कालीन प्रधान मंत्री आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्णराज्य का दर्जा दिया, उसके बाद यह प्रदेश अस्तित्व में आया। आज विपक्ष के हमारे मित्र बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। उस समय यह नारा लगाते थे कि "स्टेट हुड-मारो ठुड" । यह बात सबको पता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये तो प्रदेश के विरोधि हैं। उस समय किसान परेशान थे। साहुकारों की जमीन को काश्त करते थे और साहुकार सारी उपज को उठाकर ले जाते थे। उसकी ढुलाई का भाड़ा भी किसान को ही देना पड़ता था। किसानों की हालत उस समय बड़ी खस्ता थी। लेकिन हिमाचल प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, 1972 लागू किया और किसानों को भूमि का मालिक बनाया। यह पॉलिसी भी कांग्रेस सरकार की थी ताकि किसानों को ऊपर उठाया जा सके। लेकिन उसके विरोध में चौधरी हरदयाल के पैर में कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी चढ़ा दी गई। उस समय स्वर्गीय पंडित संत राम जी विधायक होते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस वाले कहीं छुप गये, इधर-उधर भाग गये। इसके लिए सेना बुलानी पड़ी। उस

समय प्रदेश की ऐसी हालत थी। वह वक्त मैं यहां बयां करना चाहता हूं। यहां बड़ी-बड़ी बातें विपक्ष के साथियों द्वारा की जा रही हैं। आज प्रदेश में सड़को का जाल बिछा हुआ है, गांव-गांव में बिजली पहुंच चुकि है। पानी की उपलब्धता घर-घर में है। शिक्षा के क्षेत्र में अपार विकास हुआ है। गांव-गांव में स्कूल खोले गये, यह सभी सुविधाएं कांग्रेस पार्टी प्रदेश के लोगों को दी थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं वहीं मौजूद था। मैंने सब कुछ देखा है। लेकिन जब मैं ये बातें बोल रहा हूं तो विपक्ष के साथियों को मिर्चें लग रही हैं, क्योंकि मैं सच्ची बात कह रहा हूं। प्रदेश में कई मुख्य मंत्री आए। स्वर्गीय डा. यशवन्त सिंह परमार जी जिन्होंने इस प्रदेश को बनाया। स्वर्गीय ठाकुर राम लाल जी प्रदेश के मुख्य

18.03.2025/1650/DT/AS-2

मंत्री रहे। स्वर्गीय श्री वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के 6 बार मुख्य मंत्री रहे। उनके नेतृत्व में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ। श्री शांता कुमार जी मुख्य मंत्री रहे। प्रो. प्रेम कुमार धूमल जी प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। आदरणीय जय राम जी प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे। सभी ने इस प्रदेश के लिए काम किया। किसी के काम के लिए भी इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वर्तमान सरकार ने मुख्य मंत्री श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में तीसरा बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है। यह बजट गांव का विकास करने वाला बजट है। इस बजट में ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने की बात की गई हैं। गांव का वह व्यक्ति जो आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उसकी जेब में पैसा कैसे जाए-इस बजट में ऐसे सभी प्रकार के प्रावधान किए गये हैं। यह बजट ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला यह बजट है। जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की बागडोर सम्भाली उस समय प्रदेश के ऊपर 75000 करोड़ रुपये का कर्ज और 11000 करोड रुपये की देनदारियां थी, जो भाजपा की पूर्व सरकार छोड़ कर गई थी, उसके बावजूद भी प्रदेश में विकास को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सिमित साधन होते हुए भी प्रदेश में ऐसा बजट पेश किया जोकि प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देगा और ग्रामीण लोगों को इसका लाभ होगा। प्रदेश सरकार को वर्ष 2023-2024 में 9478 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ। एन.पी.एस. शेयर के रूप में राज्य सरकार और सरकारी

कर्मचारियों का 9000 करोड़ का फंड केंद्र सरकार से लेना शेष है। वह फंड आज तक प्रदेश सरकार को नही मिला। वर्ष 2023 में मानसून के दौरान प्रदेश को भारी तबाही का सामना करना पड़ा तथा प्रदेश में हजारों घर तबाह हुए, कई बहुमूल्य जाने गईं। केंद्र सरकार ने प्रदेश में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए सैंट्रल पी.डी.एन.ए. टीम भेजी। उस टीम ने 9042 करोड़ रुपये का

श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

18.03.2025/1655/ए.एस.-एन.जी./1

श्री किशोरी लाल......जारी

जो नुकसान था उसकी रिपोर्ट बना कर केन्द्र सरकार को भेजी लेकिन केन्द्र सरकार से आज दिन तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है जोकि बहुत शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रदेश का हक है और सरकार को यह पैसा मिलना चाहिए। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इस पैसे को लाने का इंतजाम करें क्योंकि केन्द्र में इनकी पार्टी की सरकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। वर्षों से चली आ रही व्यवस्थाओं में परिर्वतन करके विकास के संकल्प को साकार करने के पथ पर अडिग रही है तथा इसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में State Excise Duty और VAT में 867 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि एक्साइज पॉलिसी में किये गए बदलावों के द्वारा ही संभव हो पाई है। राज्य की आत्मनिर्भरता की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है। शराब पर लगाए गए उपकर से भी 145 करोड़ रुपये अर्जित किए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए बिना रसायनिक खाद के तैयार की हुई मक्की के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया तथा गेहूं को 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया है। यह किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इससे किसान आत्मनिर्भर होगा तथा किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान अपनी उपज को मंडी में ले जाना चाहते हैं तो उसे 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से Freight Subsidy दी जाएगी। जहां पर बंदरों का प्रकोप है और वहां पर किसान फसल नहीं उगाते हैं तो ऐसे क्षेत्रों में प्राकृतिक हल्दी पैदा करने की योजना बनाई है और सरकार ने उस कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 90 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया है। इसके साथ ही हल्दी, अदरक, अरबी, कटहल,

18.03.2025/1655/ए.एस.-एन.जी./2

रतालू आदि की फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से 500 KG Per Hour की क्षमता वाले पोटैटो प्रोसैसिंग प्लांट को स्थापित करने जा रही है। 3400 हैक्टेयर में लगभग 54,200 मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाले किसानों को इसका लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए "हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना" शुरू करने जा रही है। इस परियोजना में 154 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। परियोजना के तहत निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगेः-

- 100 गांव में सिंचाई योजना का निर्माण किया जाएगा।

- कृषि यंत्रीकरण पर सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- परियोजना क्षेत्र के लाभार्थी किसानों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की बेहतरी के लिए मुख्य मंत्री जी ने "मुख्य मंत्री खेत संरक्षण योजना" शुरू की है। जंगली जानवरों से फसलों के नुकसान को बचाने के लिए Solar Fencing, जालीदार और कांटेदार बाड़बंदी को लगाने में उपदान प्रदान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, बागवानी के क्षेत्र में Universal Carton का इस्तेमाल आरम्भ किया गया है। लगभग 153 करोड़ रुपये की पुरानी देनदारियां भी सरकार ने चुकाई हैं। हिमाचल प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए HP SHIVA परियोजना के तहत इस वर्ष 100 करोड़ रुपये का व्यय किए जाएंगे। इससे फलदार बगीचे लगाने वाले किसानों को

18.03.2025/1655/ए.एस.-एन.जी./3

फायदा होगा। इसके अलावा सिंचाई के लिए कुहलों का निर्माण किया जा रहा है। जहां पर कुहलें नहीं हैं वहां पर उठाऊ सिंचाई योजनाओं से लाभ प्रदान किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 20 हजार से अधिक मछुआरे, मछली पालन व्यवसाय से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। प्रदेश सरकार मछुआरों और मत्स्य कृषकों से 15 प्रतिशत दर से Royalty लेती है। अब सरकार ने इस Royalty की दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया है जिससे प्रदेश के मछुआरों को बहुत लाभ होगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट के लिए बैठ जाइए क्योंकि माननीय सदन की बैठक का समय बढ़ाना पड़ेगा। मेरे पास जो सूची है उसके अनुसार चार माननीय सदस्य विपक्ष की ओर से और दो माननीय सदस्य सत्ता पक्ष की ओर से बोलने के लिए शेष हैं। इस प्रकार से कुल 6 माननीय सदस्य बोलने के लिए शेष हैं।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

18.03.2025/1700/HK/PB/-1

उपाध्यक्ष जारी...

समय सीमित है, अन्य मामाननीय सदस्यों को भी चर्चा मे भाग लेना है और इन्हें 10-10 मिनट का समय दिया जाएगा। यदि सदन की अनुमति हो तो अब इस सदन की बैठक को 6:00 बजे अपराह्न तक एक्सटेंड की जाती है। माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी अपनी बात रखेंगे।

श्री किशोरी लालः उपाध्यक्ष महोदय, मछुवारों के पास जो मत्स्य योजना है, इसके अंतर्गत 80 प्रतिशत सब्सिडी युवाओं को दी जा रही है ताकि वे अपने जीवन को रोजगार से जोड़ कर आगे बढ़ सकें। राज्य के मछुआरों को मछली परिवहन की सुविधा के लिए ट्रांसपोर्टेशन फीस में राहत दी जा रही है। साथ ही, मोटरसाइकिल व तीन पहिया वाहन भी प्रदान किए जाएंगे। सरकार मछुआरों की पुरानी नावों को बदल कर नई नाव खरीदने पर 40 से 60 प्रतिशत तक का अनुदान देगी।

ग्रीन हिमाचल मिशन को साकार करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र के विस्तारीकरण के उद्देश्य से "राजीव गांधी वन संर्वधन योजना" शुरू की जा रही है। इस योजना में युवक मंडलों, महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को बंजर भूमि पर फलदार वृक्ष लगाने हेतु प्रोत्साहन दिया जाएगा। दो हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण पर इन समूहों को 2.40 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके बाद पांच वर्षों तक प्रोत्साहन राशि तथा संरक्षण राशि भी दी जाएगी। इस प्रकार कुल 6.40 लाख रुपये की राशि प्रत्येक समूह को मिल सकेगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इन क्षेत्रों में इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण इको-टूरिज्म के लिए एक आदर्श स्थल है। स्थानीय

समुदायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। वर्ष 2024 में इको-टूरिज्म साइटों का चयन किया किया गया। अगले चरण में 78 नई इको-टूरिज्म साइटों का आबंटन किया जाएगा। वन विभाग के विभिन्न सर्कलों में इको-टूरिज्म समितियों का गठन किया गया है और अगले पांच वर्षों में 200 करोड़ रुपये अर्जित करने का लक्ष्य है।

18.03.2025/1700/HK/PB/-2

प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कांगड़ा जिले को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है। कांगड़ा के गग्गल हवाई अड्डे के विस्तारीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वर्ष 2025-26 के दौरान इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नादौन में राफ्टिंग केंद्र और अन्य जिलों में वॉटर स्पोर्ट्स तथा एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरूआत की है। पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के लिए होमस्टे योजना के तहत गांवों में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ होगा।

हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से माता चिन्तपुरनी मंदिर के सौंदर्यीयकरण के लिए 58 करोड़ रुपये, माता ज्वालाजी मंदिर के सौंदर्यीकरण लिए 100 करोड़ रुपये, माता नैना देवी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपये तथा धर्मशाला के तपोवन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कम्युनिकेशन सेंटर के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। सरकार द्वारा बनखंडी कांगड़ा में जूलॉजिकल पार्क और हर्बल प्लांटेशन टूरिज्म विकसित किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। ...(घंटी)...

प्रदेश सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की है और मनरेगा की मजदूरी में 20 रुपये की वृद्धि की है और जो मजदूरी 400 रुपये थी उसमें 25 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार छोटे दुकानदारों, फल-सब्जी विक्रेताओं,

चाय विक्रेताओं, पान दुकानदारों, जूता मरम्मत करने वालों, चार्ट-टिक्की विक्रेताओं और अन्य छोटे व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत सहायता प्रदान कर रही है।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

18.03.2025/1705/HK/AP-1

श्री किशोरी लाल द्वारा जारी ....

जिन दुकानदारों की सालाना इनकम 10 लाख रुपए से कम है, उनको 1 लाख रुपये तक के लोन के लिए च्वन टाइम सेटलमेंटछ की सुविधा दी जाएंगी तथा लोन पर लगने वाले टैक्स प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना से भी युवाओं की आर्थिक स्थिति रूप से मजबूत होगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल, जय बैजनाथ, जय कांग्रेस पार्टी।

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री दलीप ठाकुर जी।

18.03.2025/1705/HK/AP-2

श्री दलीप ठाकुरः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो माननीय मुख्य मंत्री सुक्खवीन्दर सिंह सुक्खू जी ने जो बजट अनुमान वर्ष 2025-2026 पर मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका अभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार का यह तीसरा बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। इस तीसरे बजट में यानी 3 वर्ष के कार्यकाल में तीन शब्द निकल कर आये हैं-पहला व्यवस्था परिवर्तन, दूसरा नीड बेस और तीसरा चरणबद्ध। मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता प्रदेश सरकार से पूछना चाहती है, पहला आपने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन, दूसरा नीड बेस और तीसरा कहा चरणबद्ध तरीके से। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश

की जतना इन बातों को समझ नहीं पा रही है। न ही इन शब्दों का कोई अर्थ निकला है और न ही कोई आर्थिक विकास हो रहा है। इसलिए हर वर्ष नया नाम लेकर आना, अभी 2026 व 2027 का बजट बचा है। आने वाले साल 2026 में यह सरकार कौन-सा नया शब्द यह सरकार प्रयोग करने वाली है, इस बात का 2026 के बजट में पता चलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जब केंद्र की बात आती है, जब केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती है तो ये लोग कहते हैं कि यह तो एक संघीय ढांचा है। जब प्रदेश की बात आती है। जब पिछली बार श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार थी तो यहां से सतापक्ष के कुछ एक साथी कह रहे थे कि पिछली सरकार ने 76,185 करोड़ रुपये का बोझ इस वर्तमान सरकार पर रखा है। लोन लिया है परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि ढाई वर्ष के कार्यकाल में आपने कितना लोन लिया है? आपने ढ़ाई वर्ष के कार्यकाल में जो आपने इस बजट बुक में दर्शाया गया है कि 29,046 करोड़ रुपए का लोन आपकी सरकार ने लिया है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि लगभग 30 हजार करोड़ रुपए का लोन आपकी सरकार ने लिया है, यह नीड बेस लोन है या व्यवस्था परिवर्तन का लोन है या चरणबद्ध तरीके का लोन है। यह किस प्रकार का लोन है यह भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप कहां इस प्रदेश को ले जा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम प्रदेश के लिए यह करना चाह रहे हैं। आपने पिछले बजट में बहुत सी घोषणा की थी। पिछले बजट में आपने बहुत से कर्मचारी के लिए बहुत सी घोषणा की थी। मनरेगा में कौन आदमी काम करता है। जो गांव का व्यक्ति मज़दूर और गरीब होता है वह व्यक्ति ही सिर्फ मनरेगा में काम करता है।

श्री ए.टी. द्वारा जारी...

18.03.2025/1710/AT/डी0सी0/1

श्री दलीप ठाकुर :

आपने पिछली बार कहा था कि हमने इसमें 60 रूपये की बढ़ौतरी की है। अबकी बार आपने कहा कि हमने इसमें 20 रूपये की बढ़ौतरी कर दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जब पिछली बार आपने 60रू ये की घोषणा की थी, क्या उनमें मनरेगा मजदूरों को 60 रूपये मिले या नहीं मिले? आपने इसकी समीक्षा नहीं की। आपने दोबारा से 20 रूपये की

बढ़ोतरी कर दी और कुल मिलाकर 320 रुपये की दिहाड़ी मनरेगा के मजदूरों को मिलेगी। पर अब मैं कहना चाहता हूं कि इस व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने आज तक उन मजदूरों को कोई बढ़ी हुई दिहाड़ी नहीं दी। भवानी जी कह रहे थे कि यह सरकार किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। आपने कहा था कि हम 80 रूपये गाय का दूध और 100 रूपये भैंस का दूध लेंगे परंतु आपने तो अपनी पीठ खुद थपथपाई है। ...व्यवधान मैं आपको यही बता रहा हूं ,आप सुनिए, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। जो आपने किया वह तरीका नहीं है। आपने कहा कि हमने गाय का दूध 45 रुपये से बढ़ाकर 58 रुपये कर दिया और भैंस का दूध 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये कर दिया है। मैं कहता हूं कि आपने दूध खरीद नहीं है । जो हमारे गांव का किसान है, आज भी गाय का दूध 60 रूपये मिल रहा है और भैंस का दूध 80रूपये प्रति किलो गांव में बिक रहा है। तो किसान आपको क्यों दूध बेचेगा ? आपने कहा था कि हम गाय का दूध 80 रूपये और भैंस का दूध 100 रूपये किलो खरीदेंगे । मैं कहना चाहता हूं आप किसानों के कितने हितैषी हैं, आप किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं? दूसरा मैं कहता हूं, शायद पशुपालन के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में हो,आज आप कह रहे है की मित्रों की सरकार ....व्यवधन आपने बजट बुक में लिखा है। वन मित्र दूसरी बार आ गया, आपका रोगी मित्र । कितने मित्र हैं और यहां भी बहुत से मित्र बैठे हैं और सचिवालय में भी बहुत से मित्र बैठे हैं जो सरकार पर अन्यथा बोझ डाल रहे हैं। सरकार के जो वजन को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, सचिवालय में भी वैसे मित्र बैठे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं । आपको तो दिहाड़ी उन लोगों की बढ़ानी चाहिए थी जो हमारी बहनें आशा वर्कर हैं,जो हमारी बहनें आंगनवाड़ी में काम करती हैं। जो वाटर गार्ड काम करता है। जो पंप ऑपरेटर करता है। उनकी दिहाड़ी आपने कितनी बढ़ाई, 300 और 500 रूपये बढ़ाने का काम किया है जो कि कम से कम दो या तीन हजार रूपये बढ़नी चाहिए थी। तब तो हम आपको

18.03.2025/1710/AT/डी0सी0/2

वास्तव में व्यवस्था परिवर्तन की सरकार कहते। आपने बढ़ाने का काम नहीं किया , आपने उनको ठगने का काम किया है। जो व्यक्ति सारा दिन काम करता है, मजदूरी करता है। जो हमारी आशा वर्कर सारा दिन काम करती हैं, जो गांव-गांव में जाती है, उसको आपने ठगने का प्रयास किया है। यह व्यवस्था परिवर्तन आपकी सरकार का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमेशा छोटे लोगों को ठगने का प्रयास किया, उनको धोखा देने का प्रयास आपकी सरकार ने किया है। मुख्य मंत्री ने बजट बुक के पेज नंबर 10 पर कहा कि प्रदेश को ग्रीन हिमाचल के नाम से जाना जाएगा । चाहे सौर ऊर्जा की बात हो, चाहे एच0आर0टी0सी0 के लिए आपने पिछली बार 17 मार्च 2013 को अपने बस में कहा था कि हम2026 तक ग्रीन हिमाचल का लक्ष्य प्राप्त कर लेगी इसलिए मैं कहना चाहता हूं चाहे सौर ऊर्जा में आपने कितनी वृद्धि की दूसरा ग्रीन स्टेट की बात की अपने एच0आर 0टी0सी0 में ई बस हम चलाएंगे और प्रदेश को ग्रीन सेट बनाएंगे। मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा मैं सरकाघाट जो एच0आर0टी0सी0 का डिपोज है उसकी बात मैं यहां रखी थी । माननीय मंत्री का जवाब मुझे जब मिला । मैं उसमें कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सरकाघाट डिपो में 125 पोस्टें खाली हैं

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी .....

18-03-2025/1715/एम.डी.-वाई.के./1

श्री दलीप ठाकुर.......जारी

जिसमें ड्राइवर के 37 पद खाली हैं और कंडक्टर के 35 पद खाली पड़े हैं। आप कहां से ग्रीन स्टेट बनाने की सोच रहे हैं? आपके पास ड्राइवर्स नहीं हैं, आपके पास कंडक्टर्स नहीं हैं, आपके पास मकैनिक्स भी नहीं हैं, आपके पास तेल भरने वाला व्यक्ति भी नहीं है,

इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप किसे ग्रीन स्टेट बनाने का सपना दिखा रहे हैं? आप बजट में कह रहे हैं कि वर्ष 2026 में हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या बसों में भी अब बस मित्र रखे जाएंगे और ड्राइवर-कंडक्टरों की भर्ती नहीं करेंगे? इसके अलावा क्या कोई योजना मित्रों के लिए लाई जाएगी? मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने कहा था कि किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के संदर्भ में एक योजना लेकर आएंगे। आप किसान से मक्की 24 रुपये प्रति किलो खरीद रहे थे और उसके बाद इसका रेट बढ़ाकर 30 रुपये प्रति किलो कर दिया। अब इस बजट में इसका रेट बढ़ाकर 40 रुपये प्रति किलो कर दिया है। आप डिपुओं में मक्की का आटा 50 रुपये प्रति किलो बेच रहे हैं। इसके साथ ही सरकार कह रही है कि जो मक्की का आटा नहीं लेगा उसे राशन नहीं मिलेगा। इससे पता चलता है कि आप कितने किसान हितैषी हैं और किसान के लिए कितना काम करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व सरकार ने गाय माता के लिए बहुत काम किया था। मैंने इस बजट बुक में देखा कि गौ-सेवा के लिए कोई विशेष पैकेज या विशेष योजना इस सरकार ने नहीं बनाई है। माननीय श्री जय राम ठाकुर की सरकार ने 6 हज़ार रुपये गाय के लिए दिए थे और उनके रहने-खाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार ने की थी। माननीय श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार ने 22900 गायों के रहने व खाने की व्यवस्था करने के लिए गौ-सदनों का निर्माण करवाया था। वर्तमान सरकार ने इस योजना पर कोई भी काम नहीं किया है। इसलिए मुझे लगता है कि यह सरकार गाय माता की सेवक नहीं है और गाय माता के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती।

18-03-2025/1715/एम.डी.-वाई.के./2

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदर्श स्वास्थ्य संस्थान के संदर्भ में कहना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आदर्श स्वास्थ्य संस्थान किस-किस विधान सभा क्षेत्र में खोले गए हैं? मुझे तो कोई जानकारी नहीं है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान कहां पर खोला गया है। यहां पर कितने ऐसे माननीय विधायक बैठे हुए हैं जिनके विधान सभा क्षेत्र में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोला गया है? प्रदेश सरकार ने पिछले बजट में कहा था कि सभी

विधान सभा क्षेत्रों में यानि के कुल 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। सरकार ने इसमें भी भेदभाव की नीति अपनाई है। पूर्व मुख्य मंत्री माननीय श्री जय राम ठाकुर जी ने अपने भाषण में ठीक कहा था कि सरकार की मंशा साफ है कि भाजपा के विधायकों को छोड़ देंगे और जहां पर कांग्रेस के विधायक हैं उनके क्षेत्र की डी0पी0आर0 पहले बनाई जाएंगी और उन्हीं के विधान सभा क्षेत्रों में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। धर्मपुर विधान सभा क्षेत्र, मेवा विधान सभा क्षेत्र (वर्तमान में भोरंज विधान सभा क्षेत्र) और सरकाघाट विधान सभा क्षेत्र का केन्द्र सरकाघाट बनता है। आज सरकाघाट अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं हैं। बार-बार निवेदन करने के बाद भी इस सरकार ने वहां पर डॉक्टर्स की नियुक्तियां नहीं की हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकाघाट अस्पताल में डाक्टर्स को भेजने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए। आपका विषय आ गया है।

श्री दलीप ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट के लिए बोलने दीजिए। मुझ से पूर्व वक्ताओं ने 20-20 मिनट बोला है। मैं थोड़े टाइम में ही अपनी बात रख दूंगा।

उपाध्यक्ष : यदि आप ज्यादा समय लेंगे तो आपके सहयोगी सदस्यों का ही समय कम हो जाएगा।

श्री दलीप ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने बजट में कहा है कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के सेवानिवृत कर्मचारियों का ऐरियर व डी0ए0 देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यह चरणबद्ध तरीका कब से शुरू होगा? जब से आपकी सरकार आई है तब से आपने कर्मचारियों को न डी0ए0 दिया है और न ही उन्हें ऐरियर दिया है। एक कर्मचारी 58 या 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत हो जाता है तो क्या वह कर्मचारी 75 वर्ष की आयु तक डी0ए0 या ऐरियर का इंतज़ार करेगा?

18-03-2025/1715/एम.डी.-वाई.के./3

उस कर्मचारी को उसकी नौकरी के दौरान का ऐरियर व डी0ए0 कब मिलेगा? आज पेंशनर्ज़ को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है। इसके अलावा दैनिक भोगी कर्मचारियों को

सैलरी नहीं मिल रही है। बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। कर्मचारियों को ऐरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा........जारी

18.03.2025/1720/केएस/एजी/1

श्री दलीप ठाकुर जारी---

पिछली बार 4 प्रतिशत डी0ए0 की बात की थी और अब की बार 3 प्रतिशत की बात की है, किसी भी कर्मचारी को अभी तक आपकी तरफ से कोई डी0ए0 नहीं मिला है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री दलीप ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, जो दस गारंटियां दी थी, उनका इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मुझे तो इन गारंटियों पर एक गाना भी याद आ रहा है। वह इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आपके जो नेता दिल्ली से आए, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और अलका लांबा आदि,उन्होंने घोषणा कर दी और आज प्रदेश के मुख्य मंत्री जिस बात को महसूस कर रहे हैं, उस पर मुझे एक गाना याद आ रहा है कि पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई। आज माननीय मुख्य मंत्री व प्रदेश सरकार यह महसूस कर रही है कि हम तो पिंजरे में बंद हो गए हैं। घोषणा करने वाले दिल्ली चले गए। आपदा आई और आपदा के समय में भी वे प्रदेश में नहीं आए। प्रदेश के मुख्य मंत्री को पिंजरे में बंद कर दिया। इसीलिए मुझे यह गाना याद आ रहा है क्योंकि मार पड़ेगी तो वह मुख्य मंत्री को पड़ेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में बहुत सी सड़कें आपदा के समय में खराब हुई थीं। आज तक उनको ठीक नहीं किया जा रहा है। मैंने बार-बार मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आप लिख कर दे दो, मैंने लिखकर दिया लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद आज भी मेरे क्षेत्र में वे सड़कें ठीक नहीं हुई हैं।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री दलीप ठाकुर : उपाध्यक्ष जी, मेरे चुनाव क्षेत्र में 13 स्कूल बंद हो गए हैं। वे बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है, सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। शगुन योजना, हिमकेयर योजना, सहारा योजना व गृहिणी योजना आदि सारी योजनाएं आपकी सरकार ने बंद कर दीं। इस बजट में इन योजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी, मज़दूर विरोधी तथा महिला विरोधी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है, मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूं तथा इसका समर्थन करने में पूरी तरह से असमर्थ हूं। धन्यवाद।

18.03.2025/1720/केएस/एजी/2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में श्री विवेक शर्मा जी भाग लेंगे।

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट जो मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी द्वारा पेश किया गया, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विपक्ष ने जिस तरह से इस बजट के बारे में लगातार अपनी बात रखी है, मेरा मानना है कि यह देश कृषि प्रधान है और हम लोग सब किसानी से जुड़े हैं। इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी आर्थिकी को मज़बूत करने की की गई है, किसान को मज़बूत करने की बात की गई है। हमारे विपक्ष के साथी बार-बार कह रहे हैं कि यह बजट किसान विरोधी है, ये प्रत्येक चीज़ का विरोध कर रहे हैं लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है। शायद इन्होने बजट को सही ढंग से सुना व पढ़ा नहीं है। पता नहीं इनको किस चीज़ में विरोध नज़र आ रहा है? आज किसान से जुड़ी हुई प्रत्येक बात को यहां पर रखा गया।

जिस समय वाटर कैरियर रखा गया तो सरकार द्वारा 4500 रुपये की राशि के ऊपर उसको रखा गया और उसके साथ यह कहा गया कि आप किसी और क्षेत्र में काम भी नहीं करेंगे और आपको 4500 रुपये ही मिलेंगे। आज हमारी सरकार ने पहले उसके 500 रुपये बढ़ाए, उसके बाद दोबारा पैसे बढ़ाए और प्रत्येक वर्ग का पैसा आदरणीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा बढ़ाया गया है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.03.2025/1725/av/ag/1

श्री विवेक शर्मा-------- जारी

माननीय मुख्य मंत्री जी ने देवभूमि को आगे बढ़ाने वाला बजट पेश किया है। यह प्रदेश के लिए ऐतिहासिक संकल्प का बजट है जबकि हमारे भाजपा के मित्रों के लिए यह बजट 'सावन के अन्धे' जैसा लग रहा है जिन्हें हरियाली नज़र नहीं आएगी। मैं यह बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि सरकार ने पिछले बजट में दूध के रेट बढ़ाने की बात की थी और इस बार दूध का दूसरी बार रेट बढ़ाया गया है। इस बार गाय के दूध में 45 रुपये से 51 रुपये प्रति लीटर तथा भैंस के दूध में 55 रुपये से 61 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान या सोसाइटी दो किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाइड कलैक्शन सेंटर पर दूध स्वयं ले जाते हैं तो उन्हें दो रुपये प्रति लीटर की दर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी भी दी जाएगी। इस बजट में किसान-बागवान, युवा, महिला, बुजुर्ग, पशु-पालक व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। इसके अतिरिक्त हमारी पंचायती राज संस्थाओं के चयनित जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। यह 28,000 रोज़गार देने वाला बजट है जिसमें हर श्रेणी के अंतर्गत रोज़गार देने की बात की गई है।

वर्तमान सरकार ने अपने पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग, पशु पालन विभाग, परिवहन विभाग इत्यादि सभी विभागों में रोज़गार दिया है। यहां पर स्वास्थ्य विभाग की बात की जा रही थी कि इस विभाग में क्या-क्या सुविधाएं नहीं थीं। अभी हमारी सरकार को बने हुए केवल दो वर्ष का समय हुआ है उससे पहले 5 वर्ष का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का था। उससे पहले भी 80 के दशक के बाद लगभग 20 वर्षों का कार्यकाल यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रहा। आप कम-से-कम यह तो बताएं कि आपने इतने वर्षों में प्रदेश के विकास हेतु क्या-क्या कदम उठाएं। यहां पर बात की गई कि आई0जी0एम0सी0 में माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के कर-कमलों द्वारा आज 19 वर्षों से खराब पड़ी हुई मशीन को चेंज किया जा रहा है। हमारे भाजपा के मित्रों को यह बजट इसलिए भी खराब लग सकता है क्योंकि इस बजट के

अंतर्गत प्रदेश में 70 वर्ष से ऊपर के आयु वाले बुजुर्गों की जांच के लिए 1,000 स्वास्थ्य मित्र रखने की बात की गई है। हमारी सरकार बुजुर्गों का सम्मान

18.03.2025/1725/av/ag/2

कर रही है। हमारी सरकार ने प्रदेश की 40,000 महिलाओं को 1500 रुपये की राशि दे दी है। वर्ष 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी थी तो उस समय यह वायदा किया गया था कि प्रत्येक परिवार को 15-15 लाख रुपये की राशि दी जाएगी और साथ ही दो करोड़ बेरोज़गार युवाओं को रोज़ागार देने की बात भी कही थी। आज तक उसके ऊपर भाजपा की तरफ से हमारा एक भी साथी चर्चा नहीं करता है कि वह रोज़गार और पैसा कहां गया। यहां पर हमारे भाजपा के साथी बार-बार 1500 रुपये की राशि की बात करते हैं। लेकिन प्रदेश की 40,000 महिलाओं को वह 1500 रुपये की राशि दे दी गई है। आज सरकार ने 21 वर्ष की आयु से ऊपर की बेटियों को जब 1500 रुपये देने की बात की तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे विपक्ष के साथी उसका विरोध कर रहे हैं या उसके पक्ष में हैं। यह बजट भाजपा के साथियों को दिख नहीं रहा क्योंकि इस बजट में घर में काम करने वाली निर्धन महिलाओं को दिनांक 1 जून, 2025 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और उनकी पात्र बेटियां भी 1500 रुपये प्रति माह लेने की हक़दार होंगी। भाजपा सरकार 75,000 करोड़ रुपये का कर्ज़ छोड़कर गई थी। इसके अतिरिक्त भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों की 11,000 करोड़ रुपये की देनदारियां छोड़ी थीं जोकि हमारी सरकार ने सत्ता के आने के बाद पूरी की हैं। आज श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी की सरकार सारी देनदारियां चरणबद्ध तरीके से दे रही हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को पूरे न्यायसंगत के साथ उनका हक़ दिया गया है। हमारी सरकार ने वायदा किया था कि कर्मचारियों को पेंशन दी जाएगी। हालांकि उसको देने से प्रदेश की आर्थिकी पर काफी बोझ पड़ा मगर उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने जो वायदा किया था उसको निभाते हुए यहां पर बजट में हर बात का ध्यान रखा है। हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन को भी बहाल किया है। हमारे भाजपा के साथियों को सिर्फ राजनीति नज़र आ रही है। इस बजट के माध्यम से नशे में संलिप्त लोगों के लिए कठोर कानून बनाए जाने की बात की गई है। लेकिन आज इस बात

का भी समर्थन नहीं किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए इस बजट में हर वर्ग को साथ लेकर चलने की बात की जा रही है। इस बजट के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का पैसा भी बढ़ाया गया है।

एन0एस0 द्वारा जारी

18-03-2025/1730/NS-ए0एस0/1

श्री विवेक शर्मा (विक्कू) ---- जारी

आंगनबाड़ी सहायिका का भी मानदेय बढ़ाया गया है। हर वर्ग का पैसा बढ़ाया गया है। आउटसोर्स कर्मचारियों के भी मानदेय में वृद्धि की गई है और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के साथियों को प्रदेश की चिंता नहीं है। 27 तारीख को धरना देने की बात कर रहे हैं और इस माननीय सदन में विपक्ष का हरेक सदस्य अपने आपको आगे रखने की कोशिश कर रहा है कि वह इस बजट का विरोधी है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बजट के विरोधी ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश की आम जनता के हित के भी विरोधी हैं। हम यहां पर जनता की बात रखने और उनके हक की बात करने के लिए आए हैं। मात्र सिर्फ अपनी राजनैत्तिक रोटियां सेंकने के चक्र में और हाई कमान के नेताओं को बताने के लिए कि हम सदन में लड़ाई लड़ रहे हैं तथा हर व्यक्ति अपनी लीडरशिप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता हूं कि इन सब चीजों के साथ ये लोग प्रदेश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। जनता एक उम्मीद के साथ जनप्रतिनिधि को चुन कर भेजती है। विपक्ष की भूमिका हर बात का विरोध करना नहीं है। मुख्य मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रदेश की जनता को दिया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और आने वाले समय में जब इस पर काम होगा तो प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी। धन्यवाद।

18-03-2025/1730/NS-ए0एस0/2

उपाध्यक्ष : अब माननीय डी0एस0 ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री डी0एस0 ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26 जोकि मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 17-03-2025 को इस सदन में प्रस्तुत किया गया, मैं इसके संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट अनुमान मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो वे आम जनता के हित में कितना खरा उतरता है, इस बात का गवाह तो आने वाला समय ही बनेगा। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि जिन दावों और वायदों पर वर्तमान सरकार सत्ता में आई है और वर्तमान सरकार ने पिछले दो वर्षों में जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किए हैं तो उन बजट में की गई बातें अभी भी धरातल पर व्यावहारिक नहीं हो पाई हैं। इस सरकार ने चुनाव के समय जो दावे व वायदे किए थे तो बीते दो वर्षों में इनका आस्तित्व सिर्फ पुस्तकों और सरकार के दस्तावेजों में सिमट कर रह गया है। सरकार के दावे अभी तक आम जनता के दरवाजे तक नहीं पहुंचे हैं। मैं पूरे प्रदेश के बारे में न बोलते हुए अपने विधान सभा क्षेत्र डलहौजी के बारे में बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिविल अस्पताल, किहार में 8 डॉक्टर्ज की पोस्टें स्वीकृत थीं जिनमें से अभी तक एक ही डॉक्टर वहां पर सेवाएं दे रहा है। सिविल अस्पताल, सलूणी में भी 8 एम0ओ0 की पोस्टें हैं और वहां पर मात्र एक ही एम0ओ0 सेवाएं दे रहे हैं। इन दोनों सिविल अस्पतालों में 50,000 की आबादी स्वास्थ्य लाभ लेती है। लेकिन मात्र एक डॉक्टर होने के कारण लोगों को चम्बा जाना पड़ता है या फिर प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाना पड़ता है। मेरे क्षेत्र की गरीब जनता को अपनी जेब से पैसे देकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। पी0एच0सी0, सुंडला में भी एम0ओ0 की पोस्ट खाली है। पी0एच0सी0, बृगांल में भी एक पोस्ट डॉक्टर की खाली पड़ी है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

18.03.2025/1735/RKS/एएस-1

श्री डी0एस0 ठाकुर... जारी

कुल मिलाकर एम0ओ0 के 20 पद सृजित किए गए हैं लेकिन वहां पर केवल दो ही एम0ओ0 कार्यरत हैं। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट जारी करने की बात की है लेकिन मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करूं तो वहां स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। मैंने इस विषय को पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान में लाया था लेकिन वे इस मुद्दे को हल्के में ले रहे हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसमें डलहौजी विधान सभा क्षेत्र का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। यदि हम लोक निर्माण विभाग की बात करें तो डलहौजी और सलूणी डिवीजन के बीच जो बाथरी-सूंडला-सलूणी-लंगेरा सड़क जाती है उसके विस्तारीकरण के लिए पूर्व सरकार ने वर्ल्ड बैंक से स्वीकृति ली थी। विभाग को इस सड़क के विस्तारीकरण के लिए डी0पी0आर0 तैयार करनी थी लेकिन आज दो वर्ष से भी अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी विभाग से उस सड़क की डी0पी0आर0 तैयार नहीं हो पाई है। यह सड़क पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है लेकिन इसकी हालत बहुत दयनीय है। प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में जो डी0पी0आर्ज0 बन रही हैं और उन सड़कों के निर्माण के लिए जो लोग अपनी जमीनें दे रहे हैं उनके पास काफी कम जमीनें उपलब्ध हैं। कुछ क्षेत्रों में एफ0सी0ए0 और कुछ क्षेत्रों में जमीनें न देने के कारण डी0पी0आर0 बनाने का काम रुक गया है। इस पर सरकार को चाहिए कि जिन लोगों की जमीन जा रही हैं उन्हें जम्मू-कश्मीर की तर्ज पर मुआवजा राशि दी जाए ताकि सड़कों का निर्माण कार्य सुनिश्चित हो सके। डलहौजी विधान सभा क्षेत्र में FCA/FRA के कुल 56 मामले हैं। यदि हम सीमणी-चमोगी FCA की बात करें तो इसमें 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है लेकिन अभी तक इसकी FCA क्लीयरेंस नहीं हो पाई है। हमारा नडल से जतराहन तक का क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में भी FCA क्लीयरेंस की प्रक्रिया लगभग 5 वर्षों से अटकी हुई है। मेरा लोक निर्माण मंत्री से आग्रह है कि इन सड़कों की FCA क्लीयरेंस शीघ्र करवाई जाए ताकि इन सड़कों का कार्य पुनः आरंभ हो सके ताकि जनता को इनका लाभ मिल सके। डलहौजी विधान सभा क्षेत्र में बाहर से काफी पर्यटक घूमने आते हैं लेकिन वहां न तो रोपवे और न ही पार्किंग की व्यवस्था है। इन असुविधाओं के कारण पर्यटकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिछली सरकार के समय इन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए 1.70 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की गई थी लेकिन दो वर्षों से अधिक का

18.03.2025/1735/RKS/एएस-2

समय व्यतीत जाने के बाद भी वहां कोई पार्किंग व्यवस्था का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। पर्यटकों को वहां अपने वाहनों को खड़ा करने में काफी परेशानी होती है। पूर्व सरकार के समय डलहौजी बस स्टैंड के निर्माण कार्य की स्वीकृति मिली थी लेकिन अभी तक वह कार्य भी आरंभ नहीं हो पाया है। रोपवे का कार्य भी शुरू नहीं किया गया है। पिछली सरकार के समय डलहौजी विधान सभा क्षेत्र को जो बजट जारी किया गया था उसमें कोई भी राशि खर्च नहीं हो पाई है जिसके कारण हमारा पर्यटन क्षेत्र काफी पिछड़ गया है। सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के लिए जो बजट जारी किया गया है उसमें डलहौजी विधानसभा क्षेत्र का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

श्री बी.एस.द्वारा...जारी

18.03.2025/1740/बी.एस./एच के/-1

श्री डी0एस0 ठाकुर जारी...

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम बिजली विभाग की बात करें तो बिजली विभाग में हालत बड़ी खराब है और वहां पर हफ्ता-हफ्ता बिजली के टांसफार्मर खराब रहते हैं। अभी पीछे मंगलेरा पंचायत में एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया उसके बाद उसकी रिपेयर तक नहीं हुई। हमारा क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है और वहां पर काफी ट्रांसफार्मर्ज खराब रहते हैं। विभाग के पास बजट न होने के कारण ट्रांसफार्मर्ज की मरम्मत नहीं हो पाती और बच्चों को पढ़ाई में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस बजट में डलहौली विधान सभा चुनाव क्षेत्र का नाम तक नहीं है इस चीज से लोग काफी निराश हैं।

यदि मैं शिक्षा क्षेत्र की बात करूं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं जिन्हें शायद सरकार आने वाले समय में डिनोटिफाई कर दे। क्योंकि इन स्कूलों और कॉलेजों में

चाहे प्रोफैसर की बात करें, लेक्चरर की बात करें या अध्यापकों की बात करें तो वर्तमान में इस निवार्चन क्षेत्र में अनगिनत पद रिक्त पड़े हैं। जिन स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों की संख्याः 300-400 हुआ करती थी आज वहां पर यह संख्याः 50 तक पहुंच गई है। ...(घंटी)... शिक्षा मंत्री महोदय, यहां पर बैठें हैं, ये दो माह पहले मेरे क्षेत्र तेलका में आए थे। जब आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार थी तो वहां सीनियर सेकैंडरी स्कूल की बिल्डिंग का इन्होंने शिलान्यास किया। वहां पर पूर्व सरकार ने फंड्ज दिए थे। मंत्री जी दो वर्ष के बाद वहां पर आए। वहीं भलेई माता मंदिर में ये माथा टेकने आए थे और वहीं पर हम आदरणीय मंत्री जी से मिले। मैंने इनसे निवेदन किया कि हमारे तीन कॉलेज हैं एक तेलका, भलेई और बनीखेत। पूर्व में आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार में हमें तीनों कॉलेजों के लिए 5.50- 5.50 करोड़ रुपया मिला था। परंतु जो तेलका कॉलेज के लिए पैसा सैंक्शन्ड किया गया था उसे आपने किसी और जगह शिफ्ट कर दिया। भलेई कॉलेज की बिल्डिंग का टेंडर भी हो गया था परंतु उसके बाद भी आपने विभाग को निर्देश दिए कि इस टेंडर को न खोला जाए।

18.03.2025/1740/बी.एस./एच के/-2

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया चेयर को एड्रेस कीजिए। मंत्री जी बाद में जवाब दे देंगे।

श्री डी0एस0 ठाकुर : जब मैंने शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में बात लाई तो इन्होंने कहा कि हम यहां पर प्रोफैसर भेजेंगे। परंतु आज तक वहां पर कोई भी प्रोफैसर नहीं आया और न ही बिल्डिंग बानाने के टेंडर को खोलने के निर्देश दिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह भलेई कॉलेज 7 साल पुराना है। लोगों ने इसके लिए जमीन दान में दी है और टेंडर लगने के बावजूद भी मंत्री महोदय ने उसे रोक दिया। मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी ने निवेदन है कि मेरा दूर-दराज का क्षेत्र है इस कॉलेज में छात्राओं की संख्याः ज्यादा थी परंतु वहां पर इन्होंने प्रोफैसर नहीं भेजे तो बच्चों की संख्याः कम होती चली गई। जब संख्याः कम है तो ये इसे डिनोटिफाइ कर देंगे। मेरा निवेदन है कि उस टेंडर को खोला जाए और बिल्डिंग का काम जल्द शुरू करवाया जाए।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाइंडअप कीजिए।

श्री डी0एस0 ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, यदि कानून व्यवस्था की बात करें तो चिट्टे का प्रकोप पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ डलहौजी विधान सभा क्षेत्र या जिला चम्बा में भी काफी फैला हुआ है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

18.03.2025/1745/डीटी/एचके-1

श्री डी0एस0 ठाकुर द्वारा जारी

सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के 5 युवाओं की चिट्टे के कारण मौत हो गई हैं। जो पंजाब से नशीले पदार्थ यहां आते हैं उनका उपयोग हमारे कॉलेज के बच्चों व साथ लगती आई0टी0आईज0 डलहौजी, बनीखेत, सुरंगाणी, सलूणी इत्यादि संस्थानों व क्षेत्रों में हो रहा जिसके कारण चिट्टा पूरे क्षेत्र में फैल रहा है। मेरा सरकार से आग्रह है कि जो लोग नशे के व्यापार में संलिप्त हैं उनके ऊपर कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि जो बच्चे नशे की आदत में फंसते जा रहे हैं उन्हें इससे छूटकारा प्राप्त हो। नशे के कारण बच्चों की पढ़ाई भी बाधित हो रही है इसलिए इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाए जाएं। मुख्य मंत्री जी ने जो वर्ष 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत किया है यह खोखली घोषणाओं का पिटारा है। यह बजट हिमाचल प्रदेश की उम्मीदों में खरा नहीं उतर रहा है। ये आंकड़ों का ऐसा मायाजाल है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। इसमें डलहौजी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की पूरी तरह से अनदेखी की गई है। मेरे क्षेत्र की उपेक्षा करना मेरे क्षेत्र के लोगों का अपमान है। पर्यटन के क्षेत्र में जो 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है उसमें डलहौजी क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है। मेरे क्षेत्र के लिए इस बजट में कोई नई सड़क प्रस्तावति नहीं की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में डलहौजी क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। वहां पर कोई आधुनिक उपकरण उपलब्ध नहीं हैं। जल शक्ति विभाग की योजनाएं अधर में लटकी हैं और गांव में आज भी पानी की काफी समस्या हैं। शिक्षा विभाग में अध्यापकों के काफी पद खाली पड़े हैं। इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका मैं समर्थन कर सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

18.03.2025/1745/डीटी/एचके-2

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य कैप्टन रणजीत सिंह चर्चा में भाग लेंगे।

कैप्टन रणजीत सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2025-26 के बजट पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। मुख्य मंत्री जी जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं जिन्हें हर वर्ग का पता है। इससे यह साबित होता है कि हिमाचल प्रदेश आत्म-निर्भर बनने जा रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले 12 सालों में विकास के नाम पर जनता को ठगा गया है। लेकिन अब मुख्य मंत्री और सरकार के आशीर्वाद से सुजानपुर में कार्य जारों पर चले हैं।

श्री एन.जी. द्वारा...जारी

18.03.2025/1750/वाई.के.-एन.जी./1

कैप्टन रणजीत सिंह राणा......जारी

इसके लिए मैं सुजानपुर की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूं। सुजानपुर में संधौल सड़क के पुनः निर्माण से 10 ग्राम पंचायतों को फायदा होगा। बरसात के समय में इस सड़क में पत्थर पड़ जाते थे और गाड़ियां टूट जाती थीं तथा अनेक बार यह रोड 2-2 दिन के लिए भी ब्लॉक हो जाता था। उसके बाद लोगों को हारसीपतन या टौणी देवी से घूमते हुए 50 किलोमीटर अतिरिक्त चलना पड़ता था। मैं सुजानपुर की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि इन्होंने इस सड़क के पुनर्निर्माण के लिए पैसा दिया जिससे आज इसका काम जोरों पर चला हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से इस सड़क की समस्या का स्थाई समाधान किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में डे-बोर्डिंग स्कूल का बनना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों के बच्चों का भविष्य बनेगा क्योंकि ये लोग प्राइवेट स्कूल्ज़ में ज्यादा फीस होने से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। इस डे-बोर्डिंग स्कूल से करोट, बनाल, चबूतरा, दाड़ला जैसी तकरीबन 12 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई सुविधा से मेरे क्षेत्र की कम-से-कम 10 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा। इस बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, चाहे वह किसान हो, चाहे वह बागवान हो, चाहे वह युवा वर्ग हो और अन्य सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बहुत बढ़िया बजट पेश किया गया है। पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के पांच वर्षों में कोई काम नहीं किया था। उस सरकार ने केवल झूठी घोषणाएं और फट्टे गाड़ने का काम किया था।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई की सुविधा से हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। मेरे क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल है और उसमें 70 प्रतिशत बच्चे हिमाचल प्रदेश के दाखिला लेते हैं। उस सैनिक स्कूल की हालत बहुत दयनीय थी।

18.03.2025/1750/वाई.के.-एन.जी./2

मैं वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी को लेकर गया था। वहां पर हमने देखा कि उसकी छत से सीमेंट गिर रहा है। आज तक उस स्कूल की किसी ने भी सुध नहीं ली थी। वहां पर किसी नॉर्मल बच्चे को लेकर जाएंगे तो वह उस बैड पर बैठ भी नहीं सकेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी सुबह-सुबह जाकर उस स्कूल का निरीक्षण किया। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने वहां के हॉस्टल के सुधार के लिए 3 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे पहले किसी भी सरकार ने इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया था। जब से यह सैनिक स्कूल चला है तब से सरकार का शेयर केवल 10 रुपये है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सरकार के शेयर को 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दिया है। वहां के ऑफ़िसर्स देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करते हैं और हिमाचल प्रदेश को तो वैसे ही वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। इस वीरभूमि में बड़े-बड़े औहदे वाले और बड़े-बड़े

विक्टोरिया क्रॉस पैदा हुए हैं जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया है। ऐसी वीरभूमि में भी उन जवानों के हॉस्टल को आज तक किसी भी सरकार ने नहीं देखा।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश के बच्चे कैसे नशे से दूर रहें, इसके लिए मैंने एक सुझाव रखा था। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्राऊंड सुजानपुर में स्थित है। उस ग्राऊंड में कोई पत्थर नहीं है और केवल घास-ही-घास है। इसके लिए मैंने एक सुझाव रखा था कि यदि हमने बच्चों को नशे से दूर रखना है तो इस ग्राऊंड पर एक सिंथैटिक ट्रैक का निर्माण किया जाना चाहिए। इस ट्रैक से सैनिक स्कूल के बच्चों को भी फायदा होगा और क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी खेलने का मौका मिलेगा। मैं इस माननीय सदन को यकीन दिलाना चाहता हूं कि यदि 6 माह या एक वर्ष में भी यह सिंथैटिक ट्रैक बन जाता है तो हर तीसरे माह में मैं वहां पर बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवाऊंगा और उन्हें प्रोत्साहित करूंगा कि वे नशे से दूर रहें तथा अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए इस ट्रैक का इस्तेमाल करें। यहां पर दौड़ लगाएं, खेल खेलें और अपने जीवन को हमेशा स्वस्थ रखें।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

18.03.2025/1755/YK/PB/-1

कैप्टन रणजीत सिंह राणा...जारी

हमारे मुख्य मंत्री जी ने किसानों के लिए कांटेदार और जालीदार तार लगाने का प्रावधान किया है इससे किसानों को बहुत फायदा होगा क्योंकि जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से जो नुकसान हो रहा है उससे किसानों ने अपनी जमीन बीजना बंद कर दी है। मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने इस योजना को लाया जिससे किसानों को फायदा होगा और हमारी जमीन में पहले की बनिस्बत फसल ज्यादा होगी। जैसे इन्होंने हल्दी, मक्की और गेहूं के आटे का रेट बढ़ाया है इससे भी किसान प्रोतसाहित हो करके ज्यादा से ज्यादा खेती करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि पिछली सरकार अपने कार्यकाल में सुजानपुर में कुछ नहीं किया वहां पर सिर्फ झूठी घोषणाएं की और झूठे इंस्टिट्च्यूट्स

खोल दिए न उनके लिए ज़मीन देखी न उनके लिए स्टाफ का बंदोबस्त किया गया, सीधे घोषणाएं की कि यहां पर यह खुल जाएगा और वहां पर वह खुल जाएगा। उससे कुछ नहीं हुआ उल्टा सुजानपुर विधान सभा क्षेत्र का नुकसान हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने यह बजट हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए और हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जो बजट पेश किया है इसका मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।

18.03.2025/1755/YK/PB/-2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री दीप राज जी भाग लेंगे।

श्री दीप राज : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, 17 मार्च, 2025 को जो बजट पेश हुआ है उस बजट के माध्यम से मुझे पता लगा है कि सरकार और सरकार के अधिकारी जो महान अर्थशास्त्री बैठे हैं जिन्होंने इस बजट के ऊपर कहानियां बना कर जैसे जादूगर जादू दिखाता है और वह जादू थोड़े देर के लिए हम सबको गुमराह करता है लेकिन उसके बाद जब असलियत सामने आती है तो वह एक धोखा होता है। इस तरह का धोखा इन महान अर्थशास्त्रियों ने हिमाचल प्रदेश के साथ किया है। मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वह पंचायत के प्रधान हों उनके बारे में भी बात कही गई कि अगर किसी के ऊपर बिजनैस की इंक्वायरी होती है या किसी के ऊपर केस चल रहा होता है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। हम सब यहां पर चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं। अगर हम सब में से किसी एक के ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लग जाए तो हम दोबारा जीत के सदन में नहीं आएंगे ,चाहे वह आरोप झूठा ही क्यों न हो। उसी तरह से महान अर्थशास्त्री जो उधर बैठे हैं इनके ऊपर अगर किसी भी अधिकारी के ऊपर ओ0डी0आई0 जिसे कि Officer with doubtful Integrity कहते हैं, सैक्शन 16 (3) अगर किसी के ऊपर लगा है तो वे इनके मुख्य सलाहकार हैं। जो भ्रष्टाचारियों से सलाह लेते हैं वे कैसे हिमाचल प्रदेश का विकास करेंगे? दूसरी बात यह वही लोग है जब इन्होंने अच्छी शिक्षा ग्रहण की और टैस्ट पास किया तो उनके पूरे जिले में मिठाइयां बांटी गई तथा इनकी बड़ी सराहना

की गई कि ये अच्छे बच्चे आगे निकल कर आए हैं और हमारे देश का उद्धार करेंगे। यह उतना ही कर्ज आप लोगों का भी है आप लोगों को भी इसमें समझने की आवश्यकता है। क्या आप एक ऐसी पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं या आप इनको समझा नहीं पा रहे हैं। मुझे तो आपके ऊपर भी संदेह होता है। मेरा आदरणीय बुआ जी (श्रीमती कमलेश ठाकुर) से निवेदन है कि आप भी महान अर्थशास्त्री हैं तथा आप भी विधान सभा में पहुंची हैं, आप घर को अच्छे से चलाना जानती हैं तो आप ही कुछ सलाह दे देते।

18.03.2025/1755/YK/PB/-3

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया दो मिनट बैठ जाइए। अब बोलने वाले दो सदस्य हैं। आदरणीय दीप राज जी और लोकन्दर कुमार जी बोलने वाले है।

श्री दीप राज: उपाध्यक्ष महोदय, कृपया, हमें 15-15 मिनट बोलने के लिए दे दीजिए।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

18.03.2025/1800/AG/AP-1

उपाध्यक्ष : अगर सदन की अनुमति हो तो इस सदन की कार्रवाई को 6.20 तक बढ़ाया जाये तो आज की लिस्ट में जो दो सदस्य बोलने के लिए शेष हैं वह भी चर्चा में भाग ले लेंगे।

(सदन का समय 6.20 तक बढ़ाया गया।)

श्री दीप राज : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में सत्ता पक्ष बार-बार पेंशन, सैलरी, लोन पेमेंट की बात करते रहते है और ये भी कहते है कि हमने OPS दे दिया। एक दिन मैंने देखा कि हमारे उप-मुख्य मंत्री जी जब स्टेज में किसी सभा को संबोधित कर रह थे तो वह बड़े दावे से कह रहे थे कि हमने OPS दे दिया। मैं इस सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मण्डी जिले के करसोग विधान सभा के बन्थल गांव में एक कर्मचारी, जो

कि एच0आर0टी0सी0 से रिटायर है, जिनका नाम बेली राम है, यह सब में बातें मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं कि एक वर्ष से उनको पेंशन नहीं मिली है। इसलिए सबसे पहले यह जो झूठे आंकड़े सरकार के द्वारा दिए जाते हैं उसे सरकार बंद करे क्योंकि मैंने इस बात को व्यक्ति के नाम के साथ बताया है। आप बेली राम जी की पेंशन का प्रावधान करें। मैं इस सदन में एक शेर भी कहना चाहता हूंः

ऐ साहिबे-हुकूमत सुन लो मेरी पुकार,

कर्ज और झूठ से नहीं चलेगी सरकार।

हमारा देश युवाओं का देश और हिमाचल युवाओं का प्रदेश है। आपने अपने पहले बजट में भी राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना की बात की। पहले तो मुझे यह समझ नहीं आता की आधिकारी नहीं समझा पा रहें या आप लोग नहीं समझ रहे कि Start-up और Incentive में फर्क होता है। आप लोगों ने पहली बार बात की कि हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत से ऐसे युवा है जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं या IT company में बाहर जोब्स करते हैं, उन सभी को आपने कहा भईया मछली पालो, आपने मछली पालने का Start-up दे दिया। अब कोई बताए की हिमाचल प्रदेश में कितनी ऐसी जगह हैं जहां पर मछलियां पाली जा सकती हैं? आदरणीय सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी मुख्य मंत्री बने तो मुझे लगा कि एक ड्राइवर के हाथों में प्रदेश की बागडोर आ गई, कहने का अर्थ है कि एक मध्यमवर्गीय परिवार के आदमी के हाथ में प्रदेश की कमान आ गई

18.03.2025/1800/AG/AP-2

और हिमाचल के अखबारों में भी खबर लगी कि ड्राइवर के बेटे के हाथ में प्रदेश सरकार का स्टीयरिंग। मुझे लगा कि आम परिवार से निकला एक व्यक्ति अब प्रदेश का विकास करेगा। दूसरी योजना स्टार्ट- अप की वह लाए और जिसमें प्रदेश के युवा को टैक्सी ड्राइवर बनाया गया। क्या आपने बजट में यह बताया है की 2 करोड़ 71 लाख रुपये आपने इस स्टार्ट-अप के लिए इंसेंटिव के रूप में दिया और बजट आपने 100 करोड़ से ज्यादा का

बताया था। पहले साल आपने कहा मछली पालों, दूसरें साल आपने कहा ड्राइवर बनो। लेकिन जब तीसरे साल की बात आई तो मुझे लगा इस बार आप प्रदेश को समझेगें, पर इस बार नई योजना आ गई है कि ढ़ाबे चलाओ और इसके लिए आपने सब्सिडी देने की बात भी कही है। मुझे लगता है की अगले वर्ष आप कहेंगे कि युवाओ अब आप बर्तन धोने का काम करो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपने माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम वरिष्ठ सदस्यों से सिखकर आगे कोशिश करेंगे की हिमाचल प्रदेश में विकास करें। लेकिन आप ऐसी बातें कहेगें तो कैसे चलेगा।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में युवाओं के लिए नौकरियां न होने के कारण आज प्रदेश का युवा चिट्टे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं और हमारा प्रदेश चिट्टे के नशे के मामले में नंबर वन हो गया है। पहले तो उड़ता पंजाब कहा जाता था लेकिन अब लोग उड़ता हिमाचल कहने लग पड़े हैं। मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया उस बजट बुक में बजट सारांश दिया गया है उसमें पेज नम्बर 88 का जो सातवां बिन्दु है उसमें नशा मुक्त हिमाचल की बात कही गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि सिरमौर और टांडा में Drug-De-addiction and Rehabilitation Centre खोले जाएंगे। कांगड़ा जिले में सबसे ज्यादा चिट्टे के केस हैं, हमीरपुर दूसरे स्थान पर है, मण्डी तीसरे पर और शिमला चौथे स्थान पर है। हमें यह भी समझने की आवश्यकता है कि कुछ लोग इसका व्यापार करते हैं, उनको पैसों की बढ़ी महत्वकांक्षा है। दूसरी बात ऐसे लोग जिन्हें इसकी लत लग गई है, वे खुद भी लेते हैं और बाकी लोगों को भी चिट्टा बेचते हैं। इसके लिए आपने कहा था कि हम स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। आपने स्पेशल टास्क फोर्स की बात की क्या हमारे डी0एस0पीज0 इतने सक्षम नहीं है कि क्योंकि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में शायद 20-25 आदमी होते है जो चिट्टे के कारोबार में संलिप्त होते हैं तो क्या हमारे पुलिस के डी.एस.पीज. उन्हें पकड़ न पाएं? लगभग प्रत्येक विधान सभा में ऐसे लोग जो चिट्टे के कारोबार में संलिप्त हैं उन्हें

18.03.2025/1800/AG/AP-3

पकड़े और जेल में डालें। ऐसे तो आपने ओ.पी.एस. का नियम बना दिया। हिमाचल की ज़मीन को बेचने के लिए आपने धारा 118 में बदलाव कर दिये। जब आप इतने बदलाव कर ही रहे थे तो नशे के उपर भी एक एक्ट ले आते। लेकिन इसके लिए भी आपने कुछ नहीं किया, यह प्रदेश के लोगों के प्रति आपकी मानसिकता दर्शाता है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ....

18.03.2025/1805/AT/ए0जी0/1

श्री दीप राज जारी ...

इस बजट में आप लोग एक चीज़ भूल गए। पिछले वर्ष के बीच में अपने एक नई टेक्नोलॉजीइजाद की थी कि हम सैलरी देंगे 5 दिन लेट ,पेंशन 10 दिन लेट और मंत्रियों ने और सी0पी0एस0 ने और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी तनख्वाह 2 महीने लेट की और पूरे प्रदेश को यह बताया कि उससे 300 करोड़ रुपये का प्रदेश को फायदा हुआ । अगर इतना ही फायदा होता तो इस बजट में उस स्कीम को भी ऐड कर लेते। वो स्कीम आपने क्यों नहीं ऐड की।? मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप लगा तो रहे हैं बैंडेड लेकिन इस समय हिमाचल प्रदेश को प्लास्टर की आवश्यकता है । यह स्थिति पिछले 3 वर्षों में कुछ ना कर कर के आंकड़े बता -बता के आप लोगों ने इसका जीरो कर दिया । आप लोगों ने कोई ऐसी स्कीम ही नहीं लाई जिससे हिमाचल प्रदेश का कर्ज खत्म हो। मैंने पहले पहले विधानसभा सैशन में कहा था कि एच0पी0एम0सी0 है, उसको मिनी पी0 एस0 यू0 डिक्लेयर कर देते हैं। हमारा हिमाचल प्रदेश बागवानी में नंबर एक पर आता है। हमारी बहुत सी ऐसी फैसलें हैं, जो कि प्रोसेसिंग युनिट अगर यहीं पर लगाया जाए तो उसका बेनिफिट होगा । वह तो आप कर नहीं रहे हो। उसके अलावा आपने बड़ी -बड़ी बातें कहीं कि हम आई0टी0 में राजस्व विभाग को भी लगाएंगे, विधान सभा को भी करेंगे, अधिकतर काम हम ऑनलाइन करेंगे । जब हम ऑनलाइन करेंगे तो क्या आपको पता है कि हम

इतना डाटा सिक्योर भी कर पाएंगे कि नहीं । क्या हम अपने डेटा की सेफ्टी और सिक्योरिटी कर पाएंगे? इसके लिए अगर हमें किसी से सीखने की जरूरत है, तो पिछले 45 से 50 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो टोयोटा और वोक्सवैगन दुनिया की नंबर एक कंपनी थी । लेकिन पिछले 5 वर्षों में हम देखते हैं कि एक आई0टी0 टेक्नोलॉजी के एलन मस्क आते हैं और वह पूरे देश में नंबर एक बन जाते हैं। अगर हमको सीखना ही है तो हम उनसे सीखते। आई0टी0 इंडस्ट्री में डाटा सर्वर सबसे ज्यादा चलते हैं । जो कि ठंडी जगह पर होने चाहिए ताकि उसमें बिजली का ज्यादा बिल न आए, उनको टेंपरेचर कूल न करना पड़े। जैसा हमारा फोन होता है कई बार वह गर्म हो जाता है। अगर वह कूलिंग स्पेस में रहेगा तो लाहौल-स्पिति हमारे पास ऐसा एरिया आता है जिसमें ठंड

18.03.2025/1805/AT/ए0एस0/2

बहुत है। अगर वहां पर ऐसे सर्वर एस्टेब्लिश करेंगे तो उसे हमारा डाटा भी सिक्योर होगा और हर आदमी डिजिटल इंडिया के साथ जुड़कर, हर व्यापारी अपनी वेबसाइट बना रहा है और उसके अलावा अपने डाटा को वह सिक्योर करना चाहता है। वह हमारे देश में ही होगा और आज से 10 साल बाद, अभी भी आप जो पिछला बोलते रहते हैं कि यह नहीं दिया, वह नहीं दिया, आप यह कोशिश नहीं कर रहे हैं कि किस तरह से नए पैसे का हिमाचल प्रदेश में आरंभ किया जाए । आपने कहा कि हम किसानों को मिल्क में 60 रुपये 65 रुपये देंगे। ठीक है, आपकी सरकार है आप 100 रूपये करो या कुछ और करो लेकिन दूध तो तब ठीक होगा जब वहां पर पशु ठीक होंगे, सड़कें ठीक होंगी। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में माताएं- बहने तब दूध बचेंगी जब बरसात में खराब हुई सड़कें ठीक होंगी। आपने बजट में उस चीज का भी प्रावधान नहीं किया। सड़कों की बात करूं, आपने इसमें करसोग के लिए लिखा कि आप करसोग में बखरोट, सनारली से करसोग सैंज को सड़क बनाएंगे। मात्र एक लाइन मुझे देखने को मिली । वह पैसा तो सी0आर0एफ0 के तहत पिछले वर्ष ही आ गया था।आपने मात्र उसका टेंडर नहीं लगाया और इस वजह से आप प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने

बात कही कि वह पूरा हिमाचल घूमें हैं। तो मेरा उनसे निवेदन है कि वह हिमाचल का एक पार्ट है करसोग, वहां भी आएं और वहां की भी दुर्दशा भी देखें। मैंने उनसे बार-बार कहा कि आपने डे बोर्डिंग स्कूल की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि आप डे -बोर्डिंग स्कूल खोलें। हमारे विधानसभा क्षेत्र में ....(व्यवधान) कोई बात नहीं सर, बस 5 मिनट

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट है आपके पास।

श्री दीप राजः ठीक है, सर। इस बात पर मैंने शायरी तो सुनाई ही नहीं कि :-

"जागो सत्ता में बैठे हुकमरानों जागो, युवा की पुकार सुनो
अब नींद से जागो, सपने जो टूट रहे हैं,
वे सपने नहीं, देश का भविष्य है, अब इनको संभालो ।

18.03.2025/1805/AT/ए0एस0/3

यह मैंने थोड़ा पहले कहना था लेकिन लेट हो गया। उपाध्यक्ष जी, अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं एक रिजर्व कंस्टीच्युएंसी से जीत कर आता हूं। हम यहां पर 17 विधायक बैठे हैं जो की रिज़र्व कंसीच्युएंसी से जीत कर आते हैं। इस बजट में अनुसूचित जाति के नाम पर मात्र मुझे एक लाइन देखने को मिली। पहले बजट में जब आपने डे-बोर्डिंग की बात की थी, आपने पांच स्कूलों की बात कही थी। उस समय मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि भाई हमको नहीं देना तो वहां से कोई रिज़र्व कम्युनिटी के जो विधायक हैं, उनको दे दो। जब यह लास्ट अभिभाषण हुआ, उसमें आपने चार स्कूल बताए, एक स्कूल आपने वैसे ही घटा दिया।

श्रीमती एम.डी. द्वारा जारी...

18.03.2025/1810/एमडी/एचके-1

श्री दीप राज जारी.....

जब यह अभिभाषण हुआ तो उसमें चार स्कूलों के बारे में बताया। एक स्कूल आपने वैसे ही घटा दिया। आपसे एक स्कूल नहीं खुला इसलिए मेरा निवेदन है इस बजट को एक बार फिर से देखा जाए। मेरे विधान सभा में न सही आपके विधान सभा में ही खोल दिया जाए। कहीं तो अनुसूचित जाति के लोगों का भला हो नहीं तो कांग्रेस ने हमेशा अनुसूचित जाति के लोगों का शोषण ही किया है। इसी की बदौलत हमारे हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के इतने केस देखने को मिल रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि:-

हुकूमत की आंखें बंद है कब से सौदा सपनों के सौदागर लूट हैं,

हुकूमत की आंखें बंद है कब से सपनों के सौदागर लूट हैं,

अब अब से यह वक्त की पुकार अब तो जाग जा झूठ के इस खेल को अब तो त्याग जा।

यह बजट गुमराह, ठगने, धोखा देने और अनुसूचित जाति के विरोधी बजट है इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

18.03.2025/1810/एमडी/एचके-2

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य लोकेन्दर जी भाग लेंगे।

श्री लोकेन्दर कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, 17 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है उसे पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जैसा कि दीप राज जी ने बात कही है हम आरक्षित सीटों से जीत के आए हैं और 9 मिनट बोलकर यहां कुछ होने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा या तो आप हाउस का टाइम आगे बढ़ा दें अन्यथा हम इस बजट में कल बोल देंगे।

उपाध्यक्ष : अब इस हाउस का समय नहीं बढ़ेगा।

श्री लोकेन्दर कुमार : तो फिर हम कल बोलेंगे।

उपाध्यक्ष : पहले आप अपनी बात तो रखिए।

श्री लोकेन्दर कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, हम 15-16 विधायक आरक्षित सीटों से जीत कर आते हैं। जनजातीय क्षेत्र से तीन लोग जीत के आते हैं। इन क्षेत्रों की बात एक-एक लाइन में की गई। पहले बात कही गई की हम अंतिम व्यक्ति तक जा रहे हैं और लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर वह अंतिम व्यक्ति कौन है? जो बी.पी.एल., अनुसूचित जाति और पिछड़े क्षेत्र में जन्मे हैं और यहां पर अर्थशास्त्री बने हैं। मैं तो इतिहास विषय का विद्यार्थी हूं मैं यह जानता हूं कि ऐसे ही शासक मोहम्मद बिन तुगलक हुए हैं। उन्होंने सिक्के भी बदल दिए और भी बहुत कुछ बदल दिया। अपनी राजधानी का स्थानांतरण कर दिया, यह सब हो गया परंतु लोगों को मैं अखबार पढ़ रहा था, देख रहा था कि बड़े अच्छे तरीके से भरोसा दिलाया कि हमने बड़ा अच्छा बजट पेश किया है। आपके अर्थशास्त्र के मुताबिक हुआ होगा यह बजट अच्छा। पर मेरा विधान सभा क्षेत्र के अंदर मैं सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं एक बार आनी का नाम लिखा है कि वहां पर दमकल की चौकी बनेगी। दूसरा नाम निरमंड में एक सिंचाई की योजना के बारे में कहा गया है। उसके अलावा वहां पर कुछ भी नहीं है । यहां पर पर्यटन की बात में कर रहा हूं कि कुछ बातें हमने अभी भाषण में बोल दी। कुल्लू, मनाली, बंजार, कांगड़ा हमीरपुर और आनी विधान सभा क्षेत्र के अंदर हमारे बहुत खूबसूरत जगह हैं। बहुत अच्छा क्षेत्र है, पर्यटन की दृष्टि से बहुत आगे जा सकता है, हमारे पास तकरासी, पनेव,चुआई, शीलाबंगला और तराल तथा बागासरान के क्षेत्र हैं।

18.03.2025/1810/एमडी/एचके-3

इसके अलावा बहुत सारी जगह हैं। अंग्रेजों के समय में टकरासी में सन् 1913 में रेस्ट हाउस बना है। पनेव मैं 1912 में रेस्ट हाउस बना है, चुआई में 1915 में रेस्ट हाउस बना है, तराला में 1936 में रेस्ट हाउस बना है और तब वहां पर छोटी सड़के थी और अंग्रेजों की बगिया वहां तक जाती थी परंतु अभी जो सरकार आई और जो इस सरकार के पूर्व सी0पी0एस0 यहां नहीं बैठे हैं वे परसों बड़े जोर से बोल रहे थे कि हमने जलोड़ी में बड़ा कुछ किया। उन्होंने वहां कुछ नहीं किया। किस की डायरेक्शन में किसको उखाड़ा मुझे

नहीं मालूम। पूर्व सरकार ने 14.12.2021 को 3, 49, 65,200 रुपये स्वीकृत करवाए थे तब जाकर वहां स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। उन शैडों को बेरोजगार लोगों को दिया जाएगा परंतु जब सरकार बदली, शैड बन गए तो अब ईको टूरिज्म का नाम लेकर उनकी ऑक्शन करवाई जा रही है। जो जलोड़ी पास 6 महीने बंद रहता है

श्री के0एस0द्वारा...जारी

18.03.2025/1815/केएस/एजी/1

श्री लोकेन्दर कुमार जारी----

उन लोगों से वहां पर 90-90 हजार रुपये किराया लिया गया। वहां पर 6 महीने में 90 हजार रुपये कहां से आएंगे? और उसके बाद जो दूसरी चिट्ठी निकली उसमें 02,20,93,100 रुपये दिए गए। उपायुक्त महोदय यहां से चले गए हैं। इन लोगों ने लाडा से पैसा सेंक्शन किया। उसके बाद वहां के लिए अलग से 54 लाख रुपया पानी की योजना के लिए दिया गया और जब से यह सरकार बनी है, उसके बाद वह पानी की योजना भी बंद हो गई है। ठेकेदार रो रहा है, उसको उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, इस किताब में ईको टूरिज्म की बात कही गई है कि इसके लिए 78 साइटों को चिन्हित किया जाएगा। मेरे चुनाव क्षेत्र में तीन साइटें चिन्हित की गई हैं जो रघुपुरगढ़ है, जलोड़ी पास के लिए जो सरयोड़ सड़क से रास्ता जाता है, वहां पर तीन साइटें चिन्हित की गई हैं। तीन साइटें 10-10 बीघा की चिन्हित की गई हैं और ऑक्शन के लिए रखी हैं। ऑक्शन कौन करेगा? उसके लिए क्या कोई पूंजीपति आएगा या कोई मित्र आएगा, जैसे बहन रीना कश्यप ने कहा कि मित्रों की सरकार है फिर मित्रों को वह ऑक्शन दी जाएगी और लगभग मेरे जलोड़ी क्षेत्र, खनाह, लोहाड़, फनौटी, बागा सराहन के इलाके के लगभग दो-ढाई सौ बच्चे जो अभी अपना रोज़गार कमा रहे हैं, वे बेरोज़गार हो जाएंगे जिसके लिए यह सरकार जिम्मेदार होगी अगर वे दूसरी जगह किसी गलत काम में पाए जाते हैं तो उसके लिए यह सरकार जिम्मेदार होगी, यह मैं इस मंच से कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अंदर कहा गया है कि जल शक्ति में हमने बहुत बजट रखा है और अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में टकरासी-ठारवी की उठाऊ जल परियोजना है। जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, आप अधिकारियों से पता कर लीजिए, वहां सारी पाइपें बिछ गई हैं, सबकुछ हो गया है, सिर्फ पानी भेजना है लेकिन पानी भेजने के लिए अभी तक वहां पर पैसा नहीं आया है। इस योजना से मेरी लगभग तीन-चार पंचायतें, मुहान, बिस्ताधार आदि कई दूसरे जो इलाके हैं, वे सिंचित होने हैं परंतु अभी तक उसके ऊपर कोई कार्य नहीं हुआ है।उपाध्यक्ष महोदय, 31 जुलाई, 2024 को श्रीखंड के अंदर बादल फटा। वहां पर बहुत नुकसान हुआ। हमारी बॉयल और कुरपण की कूहल बुरी तरह से डैमेज हुई। लगभग दो-ढाई हजार बीघा जमीन, जिस पर धान उगता है, वहां धान की सारी फसल नष्ट हो गई है। अभी तक विभाग की ओर से

18.03.2025/1815/केएस/एजी/2

चलाने के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, इन्होंने उस समय वहां का दौरा भी किया था। मैं चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के अंदर जो बड़ी नहरें हैं, उनके ऊपर जल्द से जल्द काम करें ताकि जो किसान हैं, जिनके बारे में आप बात करते हैं कि किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया, वे वहां पर सब्जी उगा सके, गेहूं उगा सके और आने वाले समय में उनको रोज़ी-रोटी के लिए दर-दर न भटकना पड़े।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे चुनाव क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही पुरानी मोचका कूहल है। जब पूर्व विधायक श्री ईश्वर दास जी वहां से माननीय विधायक हुआ करते थे, वह उस समय की कूहल है। वर्ष 1977 से, जब मेरा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से उसका काम चल रहा है परंतु अभी तक भी वह अपने स्थान पर नहीं पहुंची है। रामपुर के सामने वाले क्षेत्र ब्रौ, जगातखाना, चाटी व बक्खन के इलाके में वह कूहल आनी है और उनको अभी तक पानी नहीं मिला है। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री महोदय से चाहूंगा कि मोचका कूहल पर भी कोई गौर फरमाया जाए, कार्रवाई करें। वहां पर बहुत सारे एक्सिअन और एस0ई0 रिटायर हो कर चले गए परंतु यह कूहल अभी तक अपने स्थान पर नहीं पहुंची है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के बारे में कहना चाहता हूं। आनी अस्पताल के बारे में मैंने पहले भी कहा था कि उसको आदर्श अस्पताल का दर्जा दिया गया

है। उस अस्पताल के अंदर एक्सरे की मशीन खराब है। मज़बूर हो कर लोगों को प्राइवेट अस्पताल में एक्सरे करवाने पड़ रहे हैं। यहां पर डॉक्टर गिना दिए कि वहां पर गाइनेकोलॉजिस्ट को भेज दिया है, पांच-छः डॉक्टर और भेज दिए हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर एक ही डॉक्टर है। वहां पर सर्जरी के डॉक्टर के अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का जो आनी का ब्लॉक है, वहां पर 37 पंचायतें हैं, साथ ही करसोग व सिराज का इलाका भी लगता है,

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट रुकिए। क्या आप पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर देंगे? आपको बोलते हुए ऑलरेडी 9 मिनट का समय हो गया है।

श्री लोकेन्दर कुमार : उपाध्यक्ष जी, 10 मिनट का समय और दे दीजिए।

उपाध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक 10 मिनट के लिए बढ़ाई जाती है क्योंकि ये आज के अंतिम वक्ता हैं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

18.03.2025/1820/av//1

श्री लोकेन्दर कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सत्ता पक्ष के साथी बात कर रहे थे कि हमारे पास डॉक्टर्ज इत्यादि सारा स्टाफ उपलब्ध है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर चीज अच्छे तरीके से चल रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहां नगर पंचायत के अतिरिक्त 70 ग्राम पंचायतें हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आनी, दलाश, नित्थर और निरमण्ड में अस्पताल है। पूर्व की सरकार के समय में आनी में नये अस्पताल का भवन बन रहा था जिसके लिए बजट में 66 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान था। उसमें से 12 करोड़ रुपये की राशि मिल चुकी है मगर जब से नई सरकार बनी है उस भवन के निर्माण हेतु एक भी पैसा नहीं मिला है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, आप इसको चैक कर लीजिएगा। मैं बार-बार आग्रह करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें हैं। वहां अच्छे स्कूल नहीं है। वहां अस्पतालों में डॉक्टर्ज नहीं हैं। वहां डॉक्टर्ज इसलिए भी नहीं आते क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्कूल भी अच्छे नहीं है। ...(व्यवधान) माननीय शिक्षा मंत्री जी, मैं आपसे इसके संदर्भ में आगे बात करूंगा। ...(व्यवधान) वह कैसे हैं, मैं आपको इसके

बारे में भी बताऊंगा। शिक्षा मंत्री जी, आप तो वहां मेरे साथ आए थे। वहां से मैं भी पढ़ा हूं और यह मेरा भी सौभाग्य है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहता हूं कि दलाश के अस्पताल का काम भी बंद हो गया है। वहां पर ठेकेदार ने अपना सामान एकत्रित करना शुरू कर दिया है और वहां से जाने की तैयारी में है। इसके अतिरिक्त निरमण्ड अस्पताल के अंतर्गत मेरी 32 पंचायतें आती हैं। वहां रामपुर के साथ लगते क्षेत्र के लोग भी उपचार के लिए आते हैं जिनको वह अस्पताल नज़दीक पड़ता है। वह अस्पताल केवल दो डॉक्टर्ज के हवाले हैं और अगर उसमें बी0एम0ओ0 को भी शामिल किया जाए तो वहां केवल तीन डॉक्टर्ज हैं। आप यहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में कह रहे हैं कि हमने आदर्श संस्थान चलाए हैं तो उस आदर्श संस्थान को थोड़ा-सा मेरे निर्वाचन क्षेत्र को भी भेजें। मैं इसके लिए मंत्री महोदय, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। मैं यहां पर नित्थर की बात भी करना चाहता हूं। वहां पर पिछले दो-तीन महीने से डॉक्टर छुट्टी पर है। जिसके कारण वहां के लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उस अस्पताल के अंतर्गत 6-7 पंचायतें आती हैं। लेकिन वहां पर लोगों को कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, यहां तक कि वहां पर जुकाम-बुखार की गोली तक नहीं मिल रही है।

18.03.2025/1820/av/ag/2

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर बागवानी की बात की गई। यहां पर आदरणीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। आप अखबारों और टी0वी0 के माध्यम से देखते होंगे कि हमारी सरकार यह कहती है कि प्रदेश के किसानों-बागवानों को आत्मनिर्भर बना दिया है। आप बजट में यह भी लिख रहे हैं कि उनको ऋण मुक्त कर देंगे। लेकिन यदि आप सच्चाई देखें तो आज गांवों के अंदर किसानों की बेदख़ली हो रही है। यहां तक कि किसानों के घरों से पानी-बिजली के कनैक्शन काटे जा रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उसमें सीमान्त, गरीब व अनुसूचित जाति से संबंद्ध रखने वाले किसान आते हैं। आप यह बात भी याद रखना कि 20 मार्च को वे किसान शिमला में आपकी सरकार को घेरने के लिए आ रहे हैं। अगर आप यह कह रहे हैं कि यह बजट बहुत अच्छा है तो इसमें यह जिक्र भी करते कि सरकार ने

अपने सी0पी0एस0 को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपये की राशि दी है। परंतु किसानों की आवाज को दबाने के लिए अब यहां पर पुलिस को तैनात कर देंगे और उनकी आवाज को नहीं सुनेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा हमारे ऊपरी शिमला, कुल्लू, मण्डी, सिराज़, करसोग के किसानों-बागवानों को उजाड़ा जा रहा है। मेरे सहयोगी श्री दीप राज जी यहां बात कर रहे थे कि हम आम परिवारों से आए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं भी आम परिवार से हूं, मेरे पिताजी भी दिहाड़ीदार हैं। यहां पर हम जो बैठे हुए हैं तो हम सभी के अभिभावक किसान-बागवान हैं। यहां पर जब माननीय श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी मुख्य मंत्री बने तो हमने सोचा कि अब आम परिवार के लोग आगे बढ़ेंगे और उनके जीवन-यापन तथा रोज़ी-रोटी में सुधार होगा। लेकिन जब कल यह बजट आया तो इससे आशा वर्कर्ज और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान हैं। आपने उनको सारे-का-सारा काम दे दिया है। यहां तक कि आपने अपने बजट में भी लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और जिम्मेवारी मिलेगी। आपने उनके वेतन में थोड़ी-सी राशि बढ़ाकर 'ऊंट के मुंह में जीरा' डालने वाली बात कही है। आपने यहां पर जल रक्षक और मल्टी टास्क वर्कर्ज के मानदेय में बढ़ोतरी की बात की है। लेकिन मैं सच्चे व शुद्ध मन से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो 500 रुपये या 25 रुपये दिहाड़ी बढ़ाने की बात की है तो आप एक दिन मॉल रोड पर जेब में 500 रुपये ले जाकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं। हम इस सदन में किसकी बात कर रहे हैं।

श्रीमती नीना द्वारा जारी

18-03-2025/1825/NS-एच0के0/1

श्री लोकेन्दर कुमार ---- जारी

आपने इस बजट दस्तावेज में ये बातें कह दी हैं कि आम व्यक्ति को आगे कर दिया है। यहां पर मेरे किसी साथी ने कहा था कि आप जनता के बीच भेष बदल कर जाएं। आज सत्ता पक्ष से वे माननीय सदस्य खुश हो रहे हैं जिनको लीज के ऊपर होटल, जमीनें व टैंडर मिल रहे हैं। पहली लाइन में लिखा है कि माइनिंग माफिया कम हो गया है। यहां से उद्योग मंत्री जी चले गए हैं। फिर भी मैं बताता हूं कि प्रदेश में अवैध माइनिंग के कितने केसिज हैं?

अधिकारी वहां पर जाते हैं तथा चाय पीकर व गोल गप्पे खा कर वापिस चले जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश में ऐसे हालात हैं और वर्तमान सरकार के लिए यह प्रश्न चिन्ह है। मैं यह बात दिल से कह रहा हूं। मैं कम्युनिज्म में रहा हूं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में भी रहा हूं। मेरे स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। मैं आम व्यक्ति के रूप में यहां पर बात कर रहा हूं क्योंकि हम आम जन के बीच में रहते हैं और मेरे पिता जी आज भी दिहाड़ीदार का काम करते हैं। वे आज भी प्राइवेट नौकरी करते हैं। हम आज उन लोगों के मजे ले रहे हैं जो फील्ड में जा रहे हैं। हो सकता है कि हमीरपुर में पानी लाने की दिक्कत न हो लेकिन मेरे क्षेत्र में पानी लाने की दिक्कत है। मेरे क्षेत्र में बहुत घने जंगल हैं। वहां पर भालू व बाघ मिलते हैं। अगर किसी को खा गया तो उसके जिम्मेदार कौन हैं? अभी हाल ही में मेरे क्षेत्र में लाइट ठीक करने के लिए मल्टी टास्क वर्कर चला गया जोकि दिहाड़ीदार था और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं कि उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह सरकार जिस तरीके से इस दस्तावेज में तथ्यों को पेश कर रही है कि हमने अंतिम पायदान के लोगों को बजट दिया है। इसकी अखबारों में खबरें लगा दीं कि हमने पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को बजट दिया है। अरे भाई! आपने कौन-से अंतिम व्यक्ति को 20 रुपये दिहाड़ी बढ़ा कर बजट दिया है। आपने मनरेगा में 20 रुपये की दिहाड़ी बढ़ाई है। मैंने पहले भी कहा है कि मनरेगा के पिछले पैसों का भुगतान करना अभी शेष है। आप उन पैसों को अभी तक नहीं दे पाए हैं। यह बात ठीक है कि आपने यह एक दस्तावेज बनाया है। हमारी पूर्व की सरकारों ने भी यह दस्तावेज बनाया है। विपरीत परिस्थिति के अंदर पूर्व मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी ने जिस तरीके से इस प्रदेश को चलाया है वह काबिले तारीफ है। प्रदेश के अंदर जब कोरोना फैला और कई व्यक्तियों की मृत्यु हुई तब भी माननीय जय राम ठाकुर जी ने प्रदेश को बेहतर तरीके से चलाया है। वर्तमान सरकार के पास आज सब कुछ है।

18-03-2025/1825/NS-एच0के0/2

आपके पास अच्छे अधिकारी हैं। यहां पर मेरे सहयोगी ने कहा कि यहां पर जो अर्थशास्त्री बैठे हैं उन्होंने गोलमोल करके यह बजट बनाया है। अगर इसमें एक भी बात छोटे किसान/बागवान की होती तो मैं इस बजट का खुलेमन से समर्थन करता कि इसमें उनके हितों की बात की गई है। यहां पर लाहौल और स्पिति की माननीय सदस्या बैठी हैं और

आप इनसे पूछें कि इनके क्षेत्र में एफ0आर0ए0 के कितने केसिज पैंडिंग पड़े हुए हैं? आप यहां पर एफ0सी0ए0 केसिज की बात कर रहे हैं। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात करता हूं और यहां पर अधिकारी भी बैठे हुए हैं, वहां पर एफ0सी0ए0 की अप्रूवल मिल गई है, पैसा जमा हो गया है लेकिन उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमैंट ऑब्जैक्शन लगा रहा है कि एफ0सी0ए0 की जमीन की अभी तक म्यूटेशन नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जिला कुल्लू है और जिला कुल्लू के अंदर आनी विधान सभा क्षेत्र है तथा वहां पर शत प्रतिशत एरिया फॉरेस्ट है। आप कौन-सी म्यूटेशन की बात कर रहे हैं? अभी बंदोबस्त मनाली में चल रहा है और अभी तक आनी में नहीं पहुंचा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मैंने यहां बड़े ऊंचे स्वर में बात कह दी है कि मैं किसान/बागवान परिवार से संबंध रखता हूं। मेरे पिता जी दिहाड़ी का काम करते हैं और मेरी माता जी अस्पताल में कार्य करते हैं। मैं छोटी सी जगह से पल कर यहां पर पहुंचा हूं और अगर किसी एक भी व्यक्ति को वहां पर फायदा हुआ होता तो मैं इस बजट का समर्थन करता। परंतु यह बजट महिला, किसान, अनुसूचित जाति और सभी वर्गों के हितों का विरोधी बजट है। इसलिए मैं इसका समर्थन करने में असमर्थ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।

उपाध्यक्ष : आज कुल 14 माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया है।

अब इस माननीय सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला- 171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 18 मार्च, 2025 **सचिव।**